[2024] 3 एससीआर 462: 2024 आईएनएससी 161

सीता सोरेन

बनाम

भारत संघ

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 451)

04 मार्च 2024

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ए. एस. बोपन्ना, एम. एम. सुंदरेश, पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा, जे.बी. पर्दीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति गण]

विचार के लिए मुद्दा

तत्काल संदर्भ में बहुमत के निर्णय के दृष्टिकोण की शुद्धता पर पुनर्विचार करने से संबंधित है - *पी. वी. नरसिम्हा राव का वाद जो की विधायिका के एक सदस्य को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला मामला से सम्बंधित है जो कथित रूप से बोलने या वोट डालने के लिए रिश्वतखोरी में लिप्त है।

शीर्ष टिप्पणियां

भारत का संविधान- अनुच्छेद 105 और 196 - संसद या विधानमंडल के सदनों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, जैसा भी मामला हो, और सदस्यों और समितियों की - संसद सदस्य या विधान सभा, यदि आपराधिक अदालत में रिश्वत के आरोप में अभियोजन से प्रतिरक्षा का दावा कर सकते हैं - बहुमत के दृष्टिकोण की शुद्धता पर पुनर्विचार *पी.वी. नरसिम्हा से सम्बंधित वाद जो की विधायिका के एक सदस्य को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो कथित रूप से वोट डालने या बोलने के लिए रिश्वत में लिप्त है:

अभिनिर्धारित: बहुमत का निर्णय - *पी. वी. नरसिम्हा राव के वाद से सम्बंधित इस मामले का जनहित पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र - इस न्यायालय द्वारा एक त्रुटि को बनाए रखने की अनुमति देने एक गंभीर खतरा है यदि निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है - इस प्रकार, उक्त मामले से सहमति नहीं ली जाती है और खारिज कर दिया जाता है। [कंडिका 188]

* लेखक

भारत का संविधान- अनुच्छेद 105 और 196 - संसद या विधानमंडल के सदनों और सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा - विधान सभा के सदस्य के खिलाफ आरोप कि उसने राज्यसभा चुनावों में अपना वोट डालने के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार से रिश्वत स्वीकार की, हालांकि, एक खुले मतपत्र में, उसने कथित रिश्वत देने वाले के पक्ष में अपना वोट नहीं डाला, लेकिन उसकी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला - सदस्य के विरुद्ध आरोप पत्र - आपराधिक आरोपों को रद्द करने के लिए याचिका, अनुच्छेद 194(2) के संरक्षण का दावा करते हुए, उस वाद पर भरोसा करते हुए जो *पी. वी. नरसिम्हा राव से सम्बंधित है की यदि उस सदस्य को संसद में बोलने या मत देने के लिए रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से छूट प्राप्त होगी - उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत - उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला जहां दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया, जिसने आगे पांच न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया - पांच न्यायाधीशों की पीठ ने - *पी. वी. नरसिम्हा राव से सम्बंधित वाद की अवधारणा की शुद्धता पर संदेह किया। *पी. वी. नरसिम्हा राव से सम्बन्धित वाद जिसमें बहुमत के फैसले में कहा गया था कि विधायक/सांसद को प्रतिरक्षा से सम्मानित किया जाता है जब वे संसद में बोलने या अपना वोट देने के लिए रिश्वत स्वीकार करते हैं, जबकि अल्पसंख्यक मत के फैसले में कहा गया की विधायक को संसद में वोट देने या बोलने के लिए प्रभावित करने के लिए रिश्वत देना, अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) द्वारा संरक्षित नहीं है, और मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया गया:

अभिनिर्धारित: बहुमत के निर्णय में प्रश्नगत मुद्दे पर की गई व्याख्या *पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले का परिणाम एक विरोधाभाषी परिणाम के रूप में सामने आता है - इस तरह की व्याख्या अनुच्छेद 105 और 194 के पाठ और उद्देश्य के विपैरीत है - पुनर्विचार - *पी. वी. नरसिम्हा राव के मामला के स्टेयर डेसीसिस के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है - सदन के सदस्य या वास्तव में सदन स्वयं उन विशेषाधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं जो अनिवार्य रूप से उनके कामकाज से संबंधित नहीं हैं - संविधानसार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की कल्पना करता है - विधानमंडल के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वत संसदीय लोकतंत्र की नींव को नष्ट कर देता है - रिश्वत संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है - रिश्वत के अपराध के लिए अप्रासंगिक परिणाम प्रदान करना - राज्य सभा के चुनाव के लिए मतदान अनुच्छेद 194 (2) के दायरे में आता है - इस प्रकार, उक्त मामले से सहमति नहीं हुई और खारिज कर दिया गया। [पारस घ छ, झ, 188]

न्यायिक मिसाल - लंबे समय से तय कानून का फैसला *पी. वी. नरसिम्हा राव का मामला, यदि आवश्यक हो:

अभिनिर्धारित: समय की अवधि जिस पर इस मामले ने जो अवधारणा बनाई है वह प्राथमिक परिणाम का सूचक है - इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं है कि वह खुद को स्टेयर डेसीसिस के सिद्धांत की कठोर समझ तक सीमित रखे - कानून के जैविक विकास और न्याय की उन्नति के लिए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने की इस न्यायालय की क्षमता है - यदि इस न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने की शक्ति से वंचित किया जाता है, तो संवैधानिक न्यायशास्त्र का विकास लगभग एक ठहराव पर आ जाएगा - इस प्रकार, पुनर्विचार - *पी. वी. नरसिम्हा राव के मामला स्टेयर डेसीसिस के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता - *पी. वी. नरसिम्हा राव के इस मामले का जनहित पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र का कामकाज - इसमें कई स्पष्ट त्रुटियां हैं, अनुच्छेद 105 के पाठ की इसकी व्याख्या; संसदीय विशेषाधिकार के दायरे और उद्देश्य की इसकी अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के प्रति इसका दृष्टिकोण, जिसके परिणामस्वरूप एक विरोधाभाषी परिणाम निकल कर सामने आते हैं- यदि *पी. वी. नरसिम्हा के मामले में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो त्रुटि को बनाए रखने की अनुमति देने का एक आसन्न खतरा है। संविधान की गलत व्याख्या, केवल इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पिछली राय के प्रति कठोर निष्ठा के कारण नहीं की जानी चाहिए। [अनुच्छेद 31, 33, 40, 44, 188.1]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 105 और 194 - संसदीय विशेषाधिकार, यदि सदन का सामूहिक अधिकार - विशेषाधिकारों के दो घटक तत्व:

अभिनिर्धारित: संसद के सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त अधिकारों का योग और दूसरा है सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अधिकार - अधिकार और उन्मुक्तियां जैसे कि अपनी प्रक्रिया को नियमित करने की शक्ति, सदन की अवमानना के लिए दंडित करने या किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति, सदन द्वारा अपने उचित कामकाज के लिए एक सामूहिक निकाय के रूप में रखे गए विशेषाधिकारों के पहले तत्व से संबंधित हैं, सदस्यों की सुरक्षा, और अपने स्वयं के अधिकार और गरिमा की पुष्टि - सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों के दूसरे तत्व में भाषण की स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से स्वतंत्रता शामिल है, दूसरों के बीच - सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाने वाला विशेषाधिकार बदले में इसकी आवश्यकता से योग्य है, इसमें

विशेषाधिकार ऐसा होना चाहिए कि "जिसके बिना वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे" - सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त ये विशेषाधिकार सुनिश्चित करने का एक साधन हैं और सदन के सामूहिक कार्यों के प्रभावी निर्वहन की व्यवस्था है - सदन के सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार जो अन्य निकायों या व्यक्तियों के पास मौजूद विशेषाधिकार से अधिक हैं, पूर्ण या अयोग्य नहीं हैं - इस प्रकार, अनुच्छेद 105 और 194 में निहित विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां सामूहिक रूप से सदन से संबंधित हैं - सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से विशेषाधिकारों का प्रयोग इस बात पर पैरीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या यह सदन के स्वस्थ और आवश्यक कामकाज से जुड़ा हुआ है। [कंडिका 76, 77, 84]

भारत कासंविधान - अनुच्छेद 105 और 194 - संसदीय विशेषाधिकार - विशेषाधिकार का दावा करने और प्रयोग करने के लिए आवश्यक पैरीक्षण:

अभिनिर्धारित: सदन के सदस्य या वास्तव में सदन स्वयं उन विशेषाधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं जो अनिवार्य रूप से उनके कामकाज से संबंधित नहीं हैं - संसद या विधानमंडल के किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का दावा दो गुना पैरीक्षण द्वारा शासित होगा, पहला, दावा किए गए विशेषाधिकार को सदन के सामूहिक कामकाज से जोड़ा जाना चाहिए, और दूसरा, इसकी आवश्यकता को एक विधायक के आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक कार्यात्मक संबंध रखना चाहिए - इस बात को संतुष्ट करने का बोझ कि एक विशेषाधिकार मौजूद है और सदन के लिए सामूहिक रूप से अपने कार्य का निर्वहन करना आवश्यक है, विशेषाधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति या निकाय के साथ निहित है - संसद या विधानसभाओं के सदन, और समितियां द्वीप नहीं हैं जो सामान्य कानूनों के आवेदन से अंदर के लोगों को बचाने वाले एन्क्लेव के रूप में कार्य करती हैं - कानून निर्माता के अधीन हैं वही कानून जो कानून बनाने वाला निकाय उन लोगों के लिए लागू करता है जिन पर वह शासन करता है और प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। [कंडिका 87, 90, 91]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 105 और 194 - संसदीय विशेषाधिकार - विशेषाधिकार, यदि संसद या विधानमंडलों के किसी सदस्य की प्रतिरक्षा को आकर्षित करते हैं जो अपने भाषण या वोट के संबंध में रिश्वत में संलग्न हैं:

अभिनिर्धारित: रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है - रिश्वत कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में नहीं है - रिश्वतखोरी अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के खंड (2) के तहत प्रतिरक्षा नहीं है क्योंकि रिश्वत में संलग्न सदस्य एक अपराध करता है जो मतदान करने या उनके वोट पर निर्णय लेने की उनकी क्षमता से

असंबंधित है - सदन या समिति में भाषण के संबंध में रिश्वत पर भी यही सिद्धांत लागू होता है - विधायिका का एक व्यक्तिगत सदस्य वोट या भाषण के संबंध में रिश्वत के आरोप में अभियोजन पक्ष से धारा 105 और 194 के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है - प्रतिरक्षा का ऐसा दावा दोहरे पैरीक्षण को पूरा करने में विफल रहता है कि यह दावा कि सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा हुआ है और यह एक विधायक के आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है। [कंडिका छ, 188.4, 188.7]

भारत का संविधान- अनुच्छेद 105 और 194 - संसदीय विशेषाधिकार - अनुच्छेद 105 के खंड (2) में 'किसी वस्तु' और 'किसी के संबंध में' अभिव्यक्ति - व्याख्या:

अभिनिर्धारित: अनुच्छेद 105 का खंड (2) "किसी भी बात के संबंध में" कहा गया या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में प्रतिरक्षा प्रदान करता है - इस प्रतिरक्षा की सीमा का पैरीक्षण सदन के कामकाज और आवश्यकता पैरीक्षण के आंतरिक संबंध के पैरीक्षण के आवश्कयता पर किया जाना चाहिए - वाक्यांश "के संबंध में" अनुच्छेद 105 के खंड (2) के तहत दी गई प्रतिरक्षा के दायरे को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 105 - खंड (2) में "के संबंध में" शब्द "कुछ भी कहा गया" वाक्यांश पर लागू होते हैं या दिया गया कोई वोट," और बाद के भाग में सदन द्वारा या उसके अधिकार से प्रकाशन के लिए - अभिव्यक्ति "कुछ भी" और "कोई भी" अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) में साथ की अभिव्यक्तियों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए - शब्द "कुछ भी" या "कोई भी" उस ऑपरेटिव शब्द को पढ़े बिना व्याख्या नहीं की जा सकती है जिस पर यह लागू होता है अर्थात क्रमशः "कहा" और "दिया गया वोट" - शब्द "कुछ भी" और "कोई भी" जब उनके संबंधित ऑपरेटिव शब्दों के साथ पढ़ा जाता है इसका मतलब है कि कोई सदस्य सदन के समक्ष किसी भी मामले पर अपनी इच्छानुसार कहने और मतदान करने के लिए प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है - ये न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं - शब्द "के संबंध में" का अर्थ है 'से उत्पन्न होना' या 'स्पष्ट संबंध रखना' और इसका अर्थ किसी भी ऐसी चीज से नहीं लगाया जा सकता है जिसका दिए गए भाषण या वोट के साथ दूर-दूर तक कोई संबंध हो सकता है। [कंडिका 99, 102-103, 188.6]

भारत का संविधान- अनुच्छेद 105 और 194 - संसद में शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति - उद्देश्य और उद्देश्य:

अभिनिर्धारित: संविधान सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा की परिकल्पना करता है - वह उद्देश्य और लक्ष्य जिसके लिए संविधान संसद में शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा को निर्धारित करता है, को ध्यान में रखा जाना चाहिए - विशेषाधिकार अनिवार्य रूप से सामूहिक रूप से सदन से संबंधित हैं और इसके कामकाज के लिए आवश्यक हैं - इसलिए, अनुच्छेद 105 में "के संबंध में" वाक्यांश का अर्थ विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए - अनुच्छेद 105 और 194 एक निर्भीक वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें बहस, विचार-विमर्श और विचारों का आदान-प्रदान संसद और राज्य विधानसभाओं के सदनों के भीतर हो सकता है - उद्देश्य तब नष्ट हो जाता है जब किसी सदस्य को किसी मुद्दे पर उनके विश्वास/स्थिति के कारण नहीं बल्कि रिश्वत के कार्य के कारण एक निश्चित तरीके से वोट देने या बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है - विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वत भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को नष्ट कर देता है - यह संविधान के आकांक्षात्मक और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी है। संविधान एक ऐसी राजनीति का निर्माण करता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करती है। [कंडिका 104, 188.5, 188.8]

भारत का संविधान- अनुच्छेद 105 और 194 - संसदीय विशेषाधिकार - न्यायालय और सदन, यदि रिश्वतखोरी के आरोपों पर समानांतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं:

अभिनिर्धारित: रिश्वतखोरी का मुद्दा अपने रिश्वत लेने वाले सदस्यों पर सभा द्वारा अधिकारिता की विशिष्टता में से एक नहीं है - रिश्वत प्राप्त करने के लिए किसी सदस्य द्वारा अवमानना के विरुद्ध कार्य करने वाले सदन का उद्देश्य आपराधिक अभियोजन से अलग उद्देश्य की पूर्ति करता है - अधिकार क्षेत्र जो एक सक्षम न्यायालय द्वारा एक आपराधिक अपराध पर मुकदमा चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है और रिश्वत की स्वीकृति के संबंध में अनुशासन के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने के लिए सदन का अधिकार विधायिका के किसी सदस्य द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद हैं - आपराधिक अपराध के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय का दायरा, उद्देश्य और परिणाम और उसके सदस्यों को अनुशासित करने का सदन का अधिकार अलग-अलग है - विधायिका के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ दुरुपयोग की संभावना न तो बढ़ाई जाती है और न ही विधायिका के एक सदस्य पर मुकदमा चलाने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देने से कम होती है, जिस पर आरोप लगाया जाता है रिश्वतखोरी का। [कंडिका 188.9, 188.10]

भारत का संविधान- अनुच्छेद 105 और 194 - संसदीय विशेषाधिकार - रिश्वतखोरी का अपराध, जिस चरण में यह क्रिस्टलीकृत होता है:

अभिनिर्धारित: किसी लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने का अपराध अनुचित लाभ प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होने के लिए आंका गया है, न कि उस अधिनियम का वास्तविक प्रदर्शन जिसके लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया जाता है - परिणाम का वितरण रिश्वत के अपराध के लिए अप्रासंगिक है - अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) को बहुमत के फैसले में प्रस्तावित तरीके से पढ़ने के लिए। *पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले का परिणाम एक विरोधाभाषी परिणाम में सामने आता है - इस तरह की व्याख्या का परिणाम ऐसी स्थिति में होता है जहां एक विधायक को प्रतिरक्षा के साथ पुरस्कृत किया जाता है जब वे रिश्वत स्वीकार करते हैं और सहमत दिशा में मतदान करके पालन करते हैं - दूसरी ओर, एक विधायक जो रिश्वत स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, लेकिन अंततः स्वतंत्र रूप से मतदान करने का फैसला कर सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा - इस तरह की व्याख्या न केवल अनुच्छेद 105 और 194 के पाठ को झुठलाती है बल्कि विधायिका के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करने के उद्देश्य को भी - रिश्वत का अपराध सहमत कार्रवाई के प्रदर्शन के लिए अज्ञेयवादी है और अवैध परितोषण के आदान-प्रदान पर क्रिस्टलीकृत होता है - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट सहमत दिशा में डाला गया है या वोट डाला भी गया है - रिश्वत का अपराध उस समय पूरा हो जाता है जब विधायक रिश्वत स्वीकार करता है - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धारा 7. [कंडिका 117, 126, 188.11]

भारत का संविधान- अनुच्छेद 105 और 194 - संसदीय विशेषाधिकार - राज्य सभा के निर्वाचन में राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा डाले गए मत, यदि अनुच्छेद 194(2) द्वारा संरक्षित हों:

अभिनिर्धारित: अनुच्छेद 194 के बजाय 'विधानमंडल' शब्द का प्रयोग संसदीय प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए किया गया है, जो आवश्यक रूप से सदन के पटल पर नहीं होती हैं या इसके पांडित्यपूर्ण अर्थ में विधि-निर्माण' शामिल नहीं है - राज्य सभा या राज्य सभा लोकतंत्र के कार्यकरण में एक अभिन्न कार्य करती है और राज्य सभा द्वारा निभाई गई भूमिका संविधान की मूल संरचना का हिस्सा - राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता है कि मतदान स्वतंत्र रूप से और

कानूनी उत्पीड़न के डर के बिना किया जाता है - कोई अन्य व्याख्या अनुच्छेद 194 (2) के पाठ और संसदीय विशेषाधिकार के उद्देश्य को झुठलाती है - संरक्षण अनुच्छेद 105 और 194 को बोलचाल की भाषा में "संसदीय विशेषाधिकार" कहा जाता है न कि "विधायी विशेषाधिकार" - यह नहीं हो सकता है यह केवल सदन के पटल पर कानून बनाने तक ही सीमित है, लेकिन निर्वाचित सदस्यों की अन्य शक्तियों और जिम्मेदारियों तक फैली हुई है, जो विधानमंडल या संसद में होती हैं, तब भी जब सदन नहीं बैठ रहा हो। [कंडिका 180, 187]

भारत का संविधान- अनुच्छेद 194 - उपयुक्त स्थानों पर "विधानमंडल के सदन" के स्थान पर "विधानमंडल" शब्द का प्रयोग - प्रभाव:

अभिनिर्धारित: प्रावधान के प्रारूपण से यह स्पष्ट है कि दो शब्दों का परस्पर उपयोग नहीं किया गया है - अनुच्छेद 194 (2) का पहला अंग "विधानमंडल या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई कोई बात या कोई वोट दिया गया" से संबंधित है - हालांकि, दूसरे अंग में, इस्तेमाल किया गया वाक्यांश है "किसी भी रिपोर्ट के ऐसे विधानमंडल के सदन द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रकाशन के संबंध में, कागज, वोट, या कार्यवाही" - प्रावधान के दूसरे अंग में "ऐसे विधानमंडल का सदन" शब्द का उपयोग करने के लिए पहले अंग में प्रयुक्त 'विधानमंडल' शब्द से स्पष्ट प्रस्थान है - प्रावधान दोनों के बीच अंतर पैदा करता है - शब्द "विधानमंडल का सदन" और "विधानमंडल" के अलग-अलग अर्थ हैं - "विधानमंडल का सदन" न्यायिक निकाय को संदर्भित करता है, जिसे अनुच्छेद 174 के अनुसरण में राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है - दूसरी ओर, शब्द "विधानमंडल", अनुच्छेद 168 के तहत व्यापक अवधारणा को संदर्भित करता है, जिसमें राज्यपाल और विधानमंडल के सदन शामिल हैं - "विधानमंडल के सदन" के बजाय "विधानमंडल में" वाक्यांश का उपयोग महत्वपूर्ण है। [कंडिका 174, 175।

भारत का संविधान- अनुच्छेद 105, 194 - निम्नलिखित के तहत संसदीय विशेषाधिकार:

अभिनिर्धारित: शासन के संसदीय स्वरूप के कामकाज को व्यवस्थाजनक बनाने में विचारशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है - यह सुनिश्चित करता है कि जिन विधायक में नागरिक अपना विश्वास रखते हैं, वे बिना किसी डर या पक्षपात के सदन के पटल पर अपने विचार और राय व्यक्त कर सकते हैं - एक राजनीतिक दल से संबंधित विधायक जिसका वोट शेयर बहुत कम है, किसी भी प्रस्ताव पर निडर होकर मतदान कर सकता है; देश के एक दूरदराज के क्षेत्र से एक विधायक कानूनी अभियोजन द्वारा परेशान किए जाने के डर के बिना उन मुद्दों

को उठा सकता है जो उसके निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित करते हैं; और एक विधायक मानहानि के आरोप की आशंका के बिना जवाबदेही की मांग कर सकता है। [कंडिका 1]

भारत का संविधान- अनुच्छेद 105, खंड (1), (2), (3), (4) - संसद के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि - स्पष्टीकरण:

अभिनिर्धारित: खंड (1) में घोषणा की गई है कि संसद में वाक् स्वातंत्र्य होगा, संविधान और संसद में प्रक्रिया को नियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए - खंड (2) का पहला अंग निर्धारित करता है कि संसद का कोई सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा और दूसरा अंग यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किसी रिपोर्ट, कागज, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में - खंड (1) और (2) स्पष्ट रूप से संसद में वाक् स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं - खंड (1) एक सकारात्मक अभिधारणा है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है जबकि खंड (2) उसी स्वतंत्रता का विस्तार है जिसे नकारात्मक रूप से अभिव्यक्त किया गया है - खंड (3) में कहा गया है कि उन विशेषाधिकारों के संबंध में जो अनुच्छेद 105 के खंड (1) और (2) के अधीन नहीं आते हैं, शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, वे होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा परिभाषित की जा सकती हैं - खंड (3) संसद को समय-समय पर अपने विशेषाधिकारों पर कानून बनाने की अनुमति देता है - खंड (4) उपरोक्त खंडों में उन सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करता है जिन्हें संविधान के आधार पर संसद में बोलने का अधिकार है - इस प्रकार, अनुच्छेद 105 और 194 में चार खंड एक समग्र संपूर्ण बनाते हैं जो एक दूसरे को रंग देते हैं और एक साथ संसद या विधानमंडल के सदनों और सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का संग्रह बनाते हैं। [कंडिका 63-66,73]

संसदीय विशेषाधिकार - भारत में विधायिकाओं के विशेषाधिकारों का इतिहास:

अभिनिर्धारित: इतिहास को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में संसदीय विशेषाधिकारों के इतिहास के साथ-साथ औपनिवेशिक शासन के तहत इन विशेषाधिकारों का दावा करने के लिए भारतीय विधानमंडलों के संघर्ष में खोजा जा सकता है - ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के विपैरीत, भारत के पास 'प्राचीन और निस्संदेह' विशेषाधिकार नहीं हैं जो संसद और राजा

के बीच संघर्ष के बाद निहित थे - संविधान के शुरू होने के बाद वैधानिक विशेषाधिकार एक संवैधानिक विशेषाधिकार में परिवर्तित हो गया। [कंडिका 49, 188.2]

संसदीय विशेषाधिकार - विशेषाधिकारों की तुलना में रिश्वत - विदेशी न्यायालयों में न्यायशास्त्र - अन्य न्यायालयों में संसद के सदस्य द्वारा प्राप्त रिश्वत की तुलना में विशेषाधिकारों पर कानून का विकास और स्थिति-यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया - समझाया और चर्चा की गई। [कंडिका 128-167]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धारा 7 - लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध - रिश्वतखोरी का अपराध, जब पूरा हो - अपराध के घटक तत्व:

अभिनिर्धारित: धारा 7 के तहत, केवल "प्राप्त करना", "स्वीकार करना" या "प्रयास करना" एक निश्चित तरीके से कार्य करने या कार्य करने से रोकने के इरादे से अनुचित लाभ प्राप्त करना अपराध को पूरा करने के लिए पर्याप्त है - यह आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य के लिए रिश्वत दी गई है वह वास्तव में किया जाए - प्रावधान की पहली व्याख्या ऐसी व्याख्या को मजबूत करती है जब यह स्पष्ट रूप से कहता है कि "प्राप्त करना, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकार करना, या प्रयास करना अपने आप में एक अपराध होगा, भले ही किसी लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य का प्रदर्शन अनुचित न हो - इस प्रकार, एक लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने का अपराध अनुचित लाभ प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत होने के लिए आंका जाता है, न कि उस कार्य का वास्तविक प्रदर्शन जिसके लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया जाता है। [कंडिका 117]

न्यायिक समीक्षा - व्यवस्था - संसदीय विशेषाधिकार का दावा :

अभिनिर्धारित: संसदीय विशेषाधिकार का दावा संविधान के मापदंडों के अनुरूप है, इस तरह न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। [कंडिका 188.3]

न्यायिक अनुशासन - की प्रक्रिया:

अभिनिर्धारित: बड़ी संख्या की बेंच द्वारा दिया गया निर्णय कम या सह-समान ताकत की किसी भी बाद की बेंच पर बाध्यकारी है - कम ताकत की बेंच बड़ी ताकत की बेंच द्वारा लिए गए कानून के दृष्टिकोण से असहमत या असहमत नहीं हो सकती है - हालांकि, एक ही ताकत की बेंच एक समन्वय बेंच द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठा सकती है - ऐसी स्थितियों में, मामले को बड़ी ताकत की पीठ के समक्ष रखा गया है - न्यायिक अनुशासन के अनुरूप, निर्णय की शुद्धता *पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले की इस

न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की सह-समान पीठ द्वारा एक विस्तृत आदेश में मामले पर केवल संदेह किया गया था और तदनुसार, मामले को सात न्यायाधीशों की इस पीठ के समक्ष रखा गया था - इस प्रकार, - *पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले में निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ के संदर्भ में कोई कमी नहीं है। [अनुच्छेद 24, 25, 30]

सिद्धांत - स्टेयर डेसीसिस का मतलब:

अभिनिर्धारित: स्टेयर डेसीसिस का सिद्धांत यह कहता है कि न्यायालय को मिसाल से हल्के ढंग से असहमति नहीं देनी चाहिए - हालांकि, सिद्धांत कानून का एक अनम्य नियम नहीं है, और इसके परिणामस्वरूप जनता के सामान्य कल्याण की हानि के लिए एक त्रुटि को बनाए नहीं रखा जा सकता है - इस न्यायालय की बड़ी पीठ उपयुक्त मामलों में पिछले निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है, इस न्यायालय के उदाहरणों में तैयार किए गए पैरीक्षणों को ध्यान में रखते हुए - यह न्यायालय अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है यदि यह मानता है कि एक त्रुटि है, या निर्णय का प्रभाव जनता के हितों को नुकसान पहुंचाएगा यदि यह संविधान के कानूनी दर्शन के साथ असंगत है - संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में, यह न्यायालय कानून की अन्य शाखाओं की तुलना में अधिक आसानी से ऐसा करेगा क्योंकि प्रकट त्रुटि को नहीं सुधारना सार्वजनिक हित और राजनीति के लिए हानिकारक होगा। [कंडिका 33, 188.1]

संविधानकी व्याख्या - संविधान के एक प्रावधान की व्याख्या:

अभिनिर्धारित: न्यायालय को पाठ की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जो संविधान के ताने-बाने के लिए हिंसा न करे। [कंडिका 92]

संविधान की व्याख्या - अनुच्छेद के लिए सीमांत नोट - का महत्व:

अभिनिर्धारित: संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में, एक सीमांत टिप्पणी का उपयोग अनुच्छेद के अर्थ और उद्देश्य के बारे में कुछ सुराग प्रदान करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है - हालांकि, अनुच्छेद का वास्तविक अर्थ अनुच्छेद के नंगे पाठ से लिया जाना है - जब अनुच्छेद की भाषा सादा और अस्पष्ट हो, इसके साथ संलग्न सीमांत नोट पर अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता है - इसके अलावा, एक क़ानून में एक धारा के लिए सीमांत टिप्पणी धारा के शरीर के अर्थ को नियंत्रित नहीं करती है यदि नियोजित भाषा स्पष्ट है। [कंडिका 173]

विधियों की व्याख्या - वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में संलग्न उदाहरण - प्रासंगिकता:

अभिनिर्धारित: एक धारा में संलग्न दृष्टांत एक वैधानिक प्रावधान के पाठ के निर्माण में मूल्य और प्रासंगिकता के हैं और उन्हें धारा के प्रतिकूल के रूप में आसानी से खारिज नहीं किया जाना चाहिए - पी.सी. अधिनियम की धारा 7 की पहली व्याख्या का चित्रण प्रावधान का अर्थ यह लगाने में सहायता करता है कि रिश्वत का अपराध रिश्वत के आदान-प्रदान पर क्रिस्टलीकृत होता है और अधिनियम के वास्तविक प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है - इसी प्रकार, रिश्वत स्वीकार करने वाले विधायक के निर्माण में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सहमत दिशा में मतदान करता है या वोट देता है - जिस समय रिश्वत स्वीकार की जाती है, रिश्वतखोरी का अपराध पूरा हो जाता है - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988। [कंडिका 118]

केस लॉ का हवाला

*पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सीबीआई/एसपीई), [1998] 2 एससीआर 870: (1998) 4 एससीसी 626 - खारिज कर दिया।

कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ, [2006] 5 सप्ल. एससीआर 1:(2006) 7 एससीसी 1 - स्पष्ट किया गया।

सीता सोरेन बनाम भारत संघ, [2023] 12 एससीआर 753; केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी, [1965] 2 एससीआर 908: एआईआर 1965 एससी 1636; कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ, [1990] 3 एससीआर 352: (1990) 4 एससीसी 207; शंकर राजू बनाम भारत संघ, [2011] 2 एससीआर 1: (2011) 2 एससीसी 132; शाह फैसल और अन्य। बनाम भारत संघ (यूओआई), [2020] 3 एससीआर 1115: (2020) 4 एससीसी 1; राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष लोकसभा, [2007] 1 एससीआर 317: (2007) 3 एससीसी 184; लोकायुक्त, न्यायमूर्ति रिपुसूदन दयाल बनाम म.प्र. राज्य, [2014] 3 एससीआर 242 : (2014) 4 एससीसी 473; केरल राज्य बनाम के. अजीत, [2021] 6 एससीआर 774; केंद्रीय बोर्ड दाऊदी बोहरा समुदाय बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2004] सप्ल. 6 एससीआर 1054: (2005) 2 एससीसी 673; कल्पना मेहता बनाम भारत संघ, [2018] 4 एससीआर 1: (2018) 7 एससीसी 1; अमरिंदर सिंह बनाम पंजाब विधानसभा, [2010] 4 एससीआर 1105: (2010) 6 एससीसी 113; मगनलाल छगनलाल (प्रा) लि बनाम नगर निगम निगम। ग्रेटर बॉम्बे का, [1975] 1 एससीआर 1: (1974) 2 एससीसी 402; बंगाल इम्युनिटी कंपनी

लिमिटेड में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण., [1955] 2 एससीआर 603; शंभूनाथ सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1974] 1 एससीआर 1: (1973) 1 एससीसी 856; लेफ्टिनेंट कर्नल खजूर सिंह बनाम भारत संघ, [1961] 2 एससीआर 828; भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह, [1989] 3 एससीआर 316: (1989) 2 एससीसी 754; प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम भारतीय रासायनिक जैव रसायन संस्थान, [2002] 3 एससीआर 100: (2002) 5 एससीसी 111; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड संघबनाम भारत संघ, [2015] 13 एससीआर 1:(2016) 5 एससीसी 1; अजीत मोहन बनाम विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, [2021] 14 एससीआर 611: (2022) 3 एससीसी 529; राजीव सूरी बनाम डीडीए, [2021] 15 एससीआर 283 : (2022) 11 एससीसी 1; अलगापुरम आर मोहनराज बनाम टीएन विधानसभा, [2016] 6 एससीआर 611: (2016) 6 एससीसी 82; तेज किरण जैन बनाम एन संजीव रेड्डी, [1971] 1 एससीआर 612: (1970) 2 एससीसी 272; एमएसएम शर्मा बनाम श्रीकृष्ण सिन्हा, [1959] सप्ल. 1 एससीआर 806: एआईआर 1959 एससी 395; 1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1, [1965] 1 एससीआर 413; कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ, [1978] 2 एससीआर 1: (1977) 4 एससीसी 608; एन रवि बनाम अध्यक्ष, विधान सभा चेन्नई, 2003 (9) स्केल 464; राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम भारत संघ , [2018] 7 एससीआर 1: (2018) 8 एससीसी 501; किहोटो होलोहान बनाम जचिल्हू, [1992] 1 एससीआर 686: (1992) सप्प 2 एससीसी 651; चतुरदास भगवानदास पटेल बनाम गुजरात राज्य, [1976] 3 एससीआर 1052 : (1976) 3 एससीसी 46; नीरज दत्ता बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), [2023] 2 एससीआर 997: (2023) 4 एससीसी 731; पशुपति नाथ सुकुल बनाम नेम चंद्र जैन एवं अन्य, [1984] 1 एससीआर 939: (1984) 2 एससीसी 404; मधुकर जेटली बनाम भारत संघ, (1997) 11 एससीसी 111; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, [1973] सप्ल. 1 एससीआर 1: (1973) 4 एससीसी 225; के.एस. पुट्टास्वामी (आधार-5 न्यायमूर्ति) बनाम भारत संघ, [2018] 8 एससीआर 1: 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 1642 - संदर्भित .

मार्क ग्रेव्स बनाम न्यूयॉर्क राज्य के लोग, 306 यूएस 466 (1939); कीली बनाम कार्सन (1841-42) 4 मू. पीसी 63; द किंग बनाम सर जॉन इलियट, (1629) 3 सेंट ट्र 294; एक्स पार्टे वासन, (1969) 4 क्यूबी 573; आर बनाम ग्रीनवे, [1998] पीएल 357; आर. बनाम मानक के लिए संसदीय आयुक्त पूर्व पार्टे फायद, [1998] 1 डब्ल्यूएलआर 669; हैमिल्टन बनाम अल फेयद, [2001] 1 एसी 395; प्रीबल बनाम टेलीविज़न

न्यूजीलैंड, (1994) 3 ऑल ईआर 407; सरकारी वाणिज्य कार्यालय बनाम सूचना आयुक्त (हस्तक्षेप करने वाला महान्यायवादी), [2009] 3 डब्ल्यूएलआर 627; आर बनाम, [2010] 3 डब्ल्यूएलआर 1707; मकुडी बनाम बैरन ट्रिसमैन, [2014] क्यूबी 839; संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम थॉमस एफ जॉनसन, 383 यूएस 169 (1966); संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम ब्रूस्टर 408 यूएस 501 (1972); गैवेल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 408 यूएस 606 (1972); संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम हेलस्टोस्की, 442 यूएस 477 (1979); हचिंसन बनाम प्रॉक्समायर, 439 यूएस 1066 (1979); आर बनाम बंटिंग एट अल, 6 [1885] 17 ओआर 524; कनाडा (हाउस ऑफ कॉमन्स) बनाम वैद [2005] 1 एससीआर 667; चैगनोन बनाम *Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québe,* [2018] 2 एससीआर 687; आर बनाम एडवर्ड व्हाइट, 13 एससीआर (एनएसडब्ल्यू) 332; आर बनाम बोस्टन (1923) 33 सीएलआर 386; ओबेद बनाम वज़ीर [2017] एनएसडब्ल्यूसीसीए 221 - संदर्भित।

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएं

एसके नाग, 1947 तक भारत में संसदीय विशेषाधिकारों का विकास, स्टर्लिंग प्रकाशन, (1978), 317-18; एसके नाग, 1947 तक भारत में संसदीय विशेषाधिकारों का विकास, स्टर्लिंग प्रकाशन, (1978), 102-103; एसके नाग, 1947 तक भारत में संसदीय विशेषाधिकारों का विकास, स्टर्लिंग प्रकाशन, (1978), 139-141, 158; एसके नाग, 1947 तक भारत में संसदीय विशेषाधिकारों का विकास, स्टर्लिंग प्रकाशन, (1978), 322; सुधार जांच समिति की रिपोर्ट (1924), 75; एसके नाग, 1947 तक भारत में संसदीय विशेषाधिकारों का विकास, स्टर्लिंग प्रकाशन, (1978), 213-214; ग्रानविले ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ओयूपी (1972), ix; ग्रानविले ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ओयूपी (1972), xiii; सीएडी वॉल्यूम VIII 19 मई, 1949 मसौदा अनुच्छेद 85; सुभाष सी. कश्यप, संसदीय प्रक्रिया-कानून, विशेषाधिकार, अभ्यास और मिसाल, तीसरा संस्करण, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी, 502; एमएन कौल और एसएल शकधर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सचिवालय, मेट्रोपॉलिटन बुक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 7 वां संस्करण, 229; जस्टिस जीपी सिंह, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, 15वां संस्करण (2021), 136; जस्टिस जीपी सिंह, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, 15वां संस्करण (2021), 188-189 संदर्भित ।

एर्स्किन मई का कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और संसद के उपयोग पर ग्रंथ, लेक्सिस नेक्सिस, 25वां संस्करण (2019) 239; कानून, विशेषाधिकार, कार्यवाही और संसद के उपयोग पर एर्स्किन मई का ग्रंथ, लेक्सिस नेक्सिस, 25वां संस्करण (2019) 242 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; भारत सरकार अधिनियम, 1833; चार्टर अधिनियम, 1853; भारतीय परिषद अधिनियम, 1861; भारत सरकार अधिनियम, 1909; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; भारत सरकार अधिनियम, 1919; भारत सरकार अधिनियम, 1935; संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978

खोजशब्दों की सूची

बोलने या वोट डालने के लिए रिश्वत; विशेषाधिकारों के साथ रिश्वतखोरी; संसदीय विशेषाधिकार; विधायी विशेषाधिकार; प्राचीन विशेषाधिकार; वैधानिक विशेषाधिकार; संवैधानिक विशेषाधिकार; विधायिकाओं के विशेषाधिकारों का इतिहास; संसद या विधानमंडल के सदनों की उन्मुक्ति; का पुनर्विचार पी. वी. नरसिम्हा राव का मामला; सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी; संसदीय लोकतंत्र; स्टेयर डेसीसिस का सिद्धांत; राज्यसभा के लिए चुनाव; ख़ारिज; न्यायिक मिसाल; संवैधानिक न्यायशास्त्र; भाषण की स्वतंत्रता; संसद का सदन; आवश्यकता पैरीक्षण; सदन का सामूहिक कामकाज; प्रतिरक्षा "किसी भी चीज़ के संबंध में" कहा गया या कोई वोट दिया गया; समानांतर क्षेत्राधिकार; विधान-मंडल सदन; विधान-मंडल; औपनिवेशिक शासन; ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स; विदेशी क्षेत्राधिकार; अनुचित लाभ प्राप्त करना, स्वीकार करना या प्राप्त करने का प्रयास करना; न्यायिक समीक्षा; न्यायिक अनुशासन; एक अनुभाग में संलग्न चित्र; एक अनुभाग के लिए सीमांत नोट; समिति के सुधार, 1924।

से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 451

2013 की डब्ल्यूपीसीआरएल संख्या 128 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 17.02.2014 के निर्णय और आदेश से

पार्टियों के लिए अधिवक्तागण

परमजीत सिंह पटवालिया, सीनियर एडवोकेट (एमिकस क्यूरी), सुश्री हर्षिका वर्मा, दीपांशु कृष्णन, गौरवजीत सिंह पटवालिया, मनन डागा, सुश्री समृद्धि श्रीवास्तव, गौरव अग्रवाल, एडवोकेट।

राजू रामचंद्रन, सीनियर एडवोकेट, कौशिक लाइक, विवेक सिंह, आशा कौशिक, एम. वी. मुकुंद, शशांक तिवारी, राहुल आर्य, प्रताप शंकर, सुश्री देवयानी गुप्ता, सुश्री तन्वी आनंद अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट।

आर वेंकटरमानी, भारत के अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, के एम नटराज, एएसजी, के परमेश्वर, कानू अग्रवाल, सुश्री चिन्मयी चंद्रा, उदय खन्ना, अक्षय अमृतांशु, अंकुर तलवार, अनमोल चंदन, आनंद वेंकटरमानी, श्रीमती विजयलक्ष्मी वेंकटरमानी, विनायक मेहरोत्रा, सुश्री मानसी सूद, चितवन सिंघल, सुश्री सोनाली जैन, अभिषेक कुमार पांडे, रमन यादव, कार्तिकेय अग्रवाल, अरविंद कुमार शर्मा, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता।

गोपाल शंकरनारायण, विजय हंसारिया, सीनियर एडवोकेट, अश्विनी कुमार उपाध्याय, अश्विनी कुमार दुबे, विशाल सिन्हा, सुश्री जहान्वी दुबे, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, सुश्री अदिति गुप्ता, सुश्री तृषा चंद्रन, वैभव तिवारी, ऋषभ शुक्ल, सुश्री स्नेहा कलिता, सुश्री काव्या झावर, सुश्री जेस्सी कुरियन, केएस भाटी, सुश्री एसआर लियोना, सुश्री शिल्पा बागड़े, सुश्री जॉयश्री बर्मन, शुभम सिंघल, अभिमन्यु भंडारी, सुश्री रूह-ए-हिना दुआ, आरव पंडित, हर्षित खंडूजा, सुश्री धनकक्षी गांधी, साहिब कोचर, सुश्री श्रेया अरोड़ा, रणदीप सचदेवा, डॉ विवेक शर्मा, के. वी. धनंजय, ए वेलन, पवन श्याम, सुश्री नवप्रीत कौर, सुशांत विए, ओजस्वी, धीरज,एस जे. मृत्युंजय पाठक, सचिन एस, आनंद नंदन, अमित पवन, आकाश, जुबैर, विकास, डॉ. ध्रुव मिश्रा, मोहम्मद फैज, सुश्री शिवांगी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, हस्तक्षेपकर्ता/अभियोजकों के लिए एडवोकेट।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश

सामग्री तालिका*

(क). हवाला 4

(ख). पी. वी. नरसिम्हा राव में फैसले का अवलोकन 8

(ग). प्रस्तुतियाँ 14

(घ). पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले का पुनर्विचार - जो स्टेयर डेसीसिस के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं 22

(ड). भारत में संसदीय विशेषाधिकार का इतिहास 34

(च). भारत में संसदीय विशेषाधिकार का अभिप्राय 44

1.कार्यात्मक विश्लेषण 44

2. सामूहिक रूप से संसदीय विशेषाधिकार सदन का अधिकार 54

3. विशेषाधिकार का दावा करने और प्रयोग करने के लिए आवश्यकता पैरीक्षण 60

(छ). रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है 65

1. रिश्वतखोरी किसी कही गयी चीज और वोट देने के संबंध में नहीं 65

2. संविधान में सार्वजनिक जीवन में शुचिता की परिकल्पना की गई है 72

3. न्यायालय और सदन को समानांतर रूप से रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई का अधिकार रखते हैं 76

4.रिश्वतखोरी के मामले में परिणामों की डिलीवरी रिश्वतखोरी के मामले में अप्रासंगिक है 79

(ज) विशेषाधिकारों की तुलना में रिश्वत पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 87

1. यूनाइटेड किंगडम 87

2. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका 99

3. कनाडा 108

4. ऑस्ट्रेलिया 114

(झ) राज्यसभा के चुनाव अनुच्छेद 194(2) का के भीतर हैं 118

(ञ) समाप्ति 131

इडी नोट: पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

1. संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में संहिताबद्ध संसदीय विशेषाधिकार, शासन के संसदीय स्वरूप के कार्यकरण को व्यवस्थाजनक बनाने में विचार-विमर्श लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। यह सुनिश्चित करता है कि जिन विधायक में नागरिक अपना विश्वास रखते हैं, वे बिना किसी डर या पक्षपात के सदन के पटल पर अपने विचार और राय व्यक्त कर सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकार के संरक्षण के साथ, मामूली वोट शेयर वाले राजनीतिक दल से संबंधित विधायक निडर होकर किसी भी प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है; देश के एक दूरदराज के क्षेत्र से एक विधायक कानूनी अभियोजन द्वारा परेशान किए जाने के डर के बिना उन मुद्दों को उठा सकता है जो उसके निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित करते हैं; और एक विधायक मानहानि के आरोप की आशंका के बिना जवाबदेही की मांग कर सकता है।

2. क्या एक विधायक जो एक निश्चित दिशा में वोट डालने या कुछ मुद्दों के बारे में बोलने के लिए रिश्वत लेता है, उसे संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित किया जाएगा? यह संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न है जिस पर इस न्यायालय को निर्णय लेने के लिए कहा गया है।

(क). हवाला

3. यह आपराधिक अपील झारखंड उच्च न्यायालय के 17 फरवरी 2014 के एक फैसले से उत्पन्न होती है।[1] झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के दो सदस्यों का चुनाव करने के लिए 30 मार्च 2012 को चुनाव हुआ था। अपीलकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है,[2] झारखंड की विधान सभा के सदस्य थे। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसने अपना वोट डालने के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार से रिश्वत ली। हालांकि, राज्यसभा सीट के लिए खुले मतदान के बाद, उन्होंने कथित रिश्वत देने वाले के पक्ष में अपना वोट नहीं डाला और इसके बजाय अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डाला। उक्त चुनाव के दौर को रद्द कर दिया गया और एक नया चुनाव आयोजित किया गया जहां अपीलकर्ता ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में फिर से मतदान किया।

4. अपीलकर्ता ने आरोप पत्र और उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के तहत संरक्षण का दावा किया, जो 1996 में इस न्यायालय की संविधानपीठ के फैसले पर निर्भर था। *पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सीबीआई/एसपीई)[3] उच्च न्यायालय ने इस

आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया कि अपीलकर्ता ने कथित रिश्वत देने वाले के पक्ष में अपना वोट नहीं डाला था और इस प्रकार, अनुच्छेद 194 (2) के तहत संरक्षण का हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय के तर्क ने मुख्य रूप से इस न्यायालय के फैसले को बदल दिया। *पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त)। *पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) और वर्तमान मामला में जो विवाद है वह संविधान के अनुच्छेद 105 (2) के प्रावधानों (जो संसद सदस्यों और संसदीय समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है) और संविधान के अनुच्छेद 194 (2) में समकक्ष प्रावधान की व्याख्या को चालू करता है जो राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को समान प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

5. 23 सितंबर 2014 को, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ, जिसके समक्ष अपील की गई थी, का विचार था कि चूंकि विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा "पर्याप्त और सामान्य सार्वजनिक महत्व" का है, इसलिए इसे इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। 7 मार्च 2019 को, अपील की सुनवाई करने वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि सटीक प्रश्न को 1995 में पांच-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में निपटाया गया था। *पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) . पीठ का विचार था कि "जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है, उसके व्यापक प्रभाव, उठाए गए संदेह और यह मुद्दा सार्वजनिक महत्व का मामला है" के संबंध में, मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।

6. अंत में, 20 सितंबर 2023 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने दर्ज किया प्रत्यक्षतः में निर्णय की शुद्धता पर संदेह करने के कारण पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) और मामले को सात जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया। आदेश के ऑपरेटिव भाग के रूप में रिपोर्ट किया गया सीता सोरेन बनाम भारत संघ[4], नीचे दर्शाया गया है:

“24. हम सहमत होने के इच्छुक हैं। पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले में बहुमत के फैसले में जो विचार व्यक्त किया गया है, उस पर एक बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमारे कारण प्रथम दृष्टया नीचे दिए गए हैं:

सबसे पहले, अनुच्छेद 105(2) और संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के तदनुरूपी प्रावधानों की व्याख्या पाठ, संदर्भ और प्रावधान में अंतर्निहित उद्देश्य और उद्देश्य द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 105(2) में अंतर्निहित मूलभूत प्रयोजन और उद्देश्य यह है कि संसद सदस्य अथवा यथास्थिति, राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को परिणामों के भय

के बिना सभा में अथवा सभा में अथवा सभा की समितियों के सदस्यों के रूप में अपने विचार व्यक्त करने अथवा मत देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जबकि संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (क) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता देता है, अनुच्छेद 105 (2) विधानमंडल के सदस्यों के महत्व को पहचानते हुए उस अधिकार को संस्थागत बनाता है, जिसमें प्रतिशोध या परिणामों के डर के बिना खुद को व्यक्त करने और अपने मतपत्र डालने की स्वतंत्रता होती है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 105 (2) या अनुच्छेद 194 (2) का उद्देश्य प्रथम दृष्टया आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से प्रतिरक्षा प्रदान करना प्रतीत नहीं होता है जो संसद सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल के रूप में अधिकारों और कर्तव्यों के प्रयोग से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकता है;

दूसरा, पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले में फैसले के दौरान, न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल ने एक गंभीर विसंगति का उल्लेख किया यदि रिश्वत लेने वाले के लिए अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रतिरक्षा के समर्थन के विचार को स्वीकार किया जाए: एक सदस्य को इस तरह के आरोप के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी यदि सदस्य बोलने या संसद में एक विशेष तरीके से अपना वोट देने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है और वास्तव में बोलता है या वोट देता है संसद में। दूसरी ओर, कोई प्रतिरक्षा संलग्न नहीं होगी, और विधायिका के सदस्य पर रिश्वतखोरी के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है यदि वे सदन के समक्ष विचाराधीन मामले पर नहीं बोलने या अपना वोट नहीं देने के लिए रिश्वत स्वीकार करते हैं, लेकिन वे इसके विपैरीत कार्य करते हैं। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा कि इस विसंगति से बचा जा सकता है यदि अनुच्छेद 105 (2) में "के संबंध में" शब्दों का अर्थ 'से उत्पन्न' माना जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में, प्रतिरक्षा केवल तभी उपलब्ध होगी जब जो भाषण दिया गया है या जो वोट दिया गया है वह कानून को जन्म देने वाली कार्यवाही के लिए कार्रवाई के कारण के लिए एक आवश्यक और अभिन्न अंग है; और

तीसरा, न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल के फैसले ने विशेष रूप से इस सवाल पर विचार किया है कि रिश्वत का अपराध कब पूरा होगा। निर्णय में कहा गया है कि अपराध धन की स्वीकृति के साथ या समाप्त किए जा रहे धन को स्वीकार करने के समझौते पर पूरा हो गया है और रिसीवर द्वारा अवैध वादे के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। रिश्वत के प्राप्तकर्ता को अपराध करने के लिए दोषी माना जाएगा, भले ही वह रिश्वत की स्वीकृति के अंतर्निहित सौदेबाजी को पूरा करने में विफल रहता है। रिश्वत के अपराध के घटक तत्वों पर असर डालने वाला

यह पहलू न्यायमूर्ति अग्रवाल के फैसले में विस्तार से जगह पाता है लेकिन बहुमत के फैसले में इस पर विचार नहीं किया जाता है।

26. उपरोक्त कारणों से, प्रथम दृष्टया, इस स्तर पर, हमारा विचार है कि पी. वी. नरसिम्हा राव के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण की शुद्धता पर सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

7. वर्तमान निर्णय का दायरा इस न्यायालय के दिनांक 20 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा किए गए संदर्भ तक सीमित है, जिसमें इसकी शुद्धता पर संदेह किया गया है पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त। अपीलकर्ता के मामले की योग्यता और क्या उसने कथित अपराध किया है, इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इस निर्णय में निहित किसी भी बात को मुकदमे या उससे उत्पन्न होने वाली किसी अन्य कार्यवाही के गुणों पर असर डालने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(ख). पी. वी. नरसिम्हा राव में फैसले का अवलोकन

8. दसवीं लोक सभा के लिए आम चुनाव 1991 में हुए। कांग्रेस (आई) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और श्री पी. वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के रूप में एक अल्पमत सरकार बनाई। सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। अविश्वास प्रस्ताव को हराने के लिए चौदह सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। प्रस्ताव के समर्थन में दो सौ इक्यावन सदस्यों के मतदान और प्रस्ताव के खिलाफ दो सौ पैंसठ सदस्यों के मतदान के साथ प्रस्ताव गिर गया। संसद सदस्यों का एक समूह[5] झामुमो और जनता दल (अजीत सिंह) समूह के प्रति निष्ठा के कारण[6] अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। विशेष रूप से, जद (एएस) से संबंधित एक सांसद, अजीत सिंह ने मतदान में भाग नहीं लिया।

9. केंद्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी[7] आरोप लगाया कि एक आपराधिक साजिश रची गई जिसके द्वारा झामुमो और जद (एएस) के उपरोक्त सदस्यों ने एक समझौता किया और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के लिए रिश्वत ली।[8] आरोप है कि पी. वी. नरसिम्हा राव और कई अन्य सांसद आपराधिक इस साजिश में शामिल थे और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने के लिए कथित रिश्वत लेने वालों को लाखों रुपये दिए।[9]

10. कथित रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया गया था और दिल्ली के विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया गया था। आरोपियों ने आरोपों को

रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस न्यायालय में अपील की गई और इसकी परिणति पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के निर्णय के रूप में सामने आया। न्यायालय के समक्ष विचार के लिए दो प्रमुख प्रश्न आए . पहला, संविधान के अनुच्छेद 105 के आधार पर एक सांसद फौजदारी अदालत में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा कर सकता दूसरा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य के अभियोजन के लिए मंजूरी प्राधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? वर्तमान फैसले में, हम केवल पहले प्रश्न पर पांच न्यायाधीशों की पीठ की विचार से चिंतित हैं, अर्थात, अनुच्छेद 105 (2) के तहत अभियोजन से प्रतिरक्षा का दायरा जब एक सांसद पर रिश्वत का आरोप लगाया जाता है।

11. इस मामले में तीन राय लिखी गई थीं- एस.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्ति (खुद के लिए और डॉ ए.एस. आनंद, न्यायमूर्ति), एसपी भरूचा, न्यायमूर्ति (खुद के लिए और एस राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्ति के लिए) और जीएन रे, न्यायमूर्ति द्वारा एक राय।

12. न्यायमूर्ति एस.पी. भरूचा (उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट डालने वाले कथित रिश्वत लेने वालों को संविधान के अनुच्छेद 105 (2) के तहत कानून की अदालत में अभियोजन से छूट प्राप्त है। हालांकि, अजीत सिंह (जिन्होंने मतदान से परहेज किया) और कथित रिश्वत देने वालों को समान प्रतिरक्षा का आनंद नहीं लेने के लिए विचार किया गया था। न्यायमूर्ति भरूचा ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन और इसकी अवमानना के लिए, संसद कथित रिश्वत लेने वालों और रिश्वत देने वालों दोनों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। न्यायमूर्ति भरूचा ने कहा:

12.1. अनुच्छेद 105(1) और अनुच्छेद 105(2) के प्रावधान सुझाव देते हैं कि सांसदों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में निहित भाषण की स्वतंत्रता और इसके अपवादों से स्वतंत्र है। सांसदों को संसद में जो कुछ भी कहना है, उसे लेकर सभी बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। एक वोट को भाषण के विस्तार के रूप में माना जाता है और इसे बोले गए शब्द का संरक्षण दिया जाता है;

12.2. अभिव्यक्ति "के संबंध में" अनुच्छेद 105 (2) में एक "व्यापक अर्थ" प्राप्त करना चाहिए और इस बात पर जोर देता है कि एक सांसद को कानून की अदालत में किसी भी कार्यवाही से संरक्षित किया जाता है जो संसद में उसके द्वारा कही गई किसी भी बात या वोट से संबंधित, चिंता या संबंध या सांठगांठ है;

12.3. कथित रिश्वत लेने वाले अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रतिरक्षा के हकदार हैं क्योंकि कथित साजिश और रिश्वत की स्वीकृति अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट के संबंध में थी। कथित साजिश और समझौते का घोषित उद्देश्य अविश्वास प्रस्ताव को विफल करना था और कथित रिश्वत लेने वालों ने इसे हराने के मकसद या इनाम के रूप में रिश्वत ली। कथित साजिश, रिश्वत और अविश्वास प्रस्ताव के बीच सांठगांठ स्पष्ट थी;

12.4. अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत संरक्षण का उद्देश्य संसद में सांसदों को इस भय के बिना स्वतंत्र रूप से बोलने और मतदान करने में समर्थ बनाना है कि उन्हें न्यायालय में जवाबदेह बनाया जाएगा। यह पर्याप्त नहीं है कि सांसदों को कार्यवाही के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए जहां कार्रवाई का कारण उनका भाषण या वोट है। संसदीय बहसों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए, सांसदों को उन सभी नागरिक और आपराधिक कार्यवाहियों के खिलाफ प्रतिरक्षा की व्यापक सुरक्षा की आवश्यकता है जो उनके भाषण या वोट से जुड़ी हुई हैं। एक सांसद के लिए कल्पना करना मुश्किल नहीं है, जिसने एक भाषण दिया है या वोट डाला है जो "शक्तियों की पसंद" नहीं है, कानूनी अभियोजन से परेशान हो रहा है कि उसे संसद में एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए रिश्वत का भुगतान किया गया था;

12.5. रिश्वत लेने वालों द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए संविधान के संकीर्ण निर्माण की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के निर्माण से प्रभावी संसदीय लोकतंत्र की गारंटी को नुकसान पहुंचने का खतरा है;

12.6. अनुच्छेद 105(2) के तहत प्रतिरक्षा केवल तभी तक लागू होती है जब तक कि यह जो कहा गया या मतदान किया गया है, उससे संबंधित है। इसलिए, मतदान से अनुपस्थित रहने वाले सांसद अजीत सिंह को प्रतिरक्षा द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था और उनके खिलाफ अभियोजन आगे बढ़ेगा;

12.7. इस संबंध में कि क्या रिश्वत देने वालों को प्रतिरक्षा प्राप्त है, चूंकि अजीत सिंह के खिलाफ अभियोजन आगे बढ़ेगा, साजिश के रिश्वत देने वालों के खिलाफ आरोप और अजीत सिंह के साथ एक गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत होने का आरोप भी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 105 (2) यह प्रदान नहीं करता है कि जो अन्यथा अपराध है वह अपराध नहीं है जब यह एक सांसद द्वारा किया जाता है। इस प्रावधान में सिर्फ यह प्रावधान किया गया है कि किसी सांसद को किसी ऐसी बात के लिए अदालत में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, जिसका संसद में उसके भाषण या वोट से कोई लेना-देना हो। जिन लोगों

ने उस अपराध को करने में सांसद के साथ साजिश रची है, उन्हें ऐसी कोई छूट नहीं है। इसलिए, रिश्वत देने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें अनुच्छेद 105 (2) का संरक्षण प्राप्त नहीं है।

13. दूसरी ओर, एस.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्ति ने कहा कि न तो कथित रिश्वत लेने वालों और न ही कथित रिश्वत देने वालों ने अनुच्छेद 105 (2) के संरक्षण का आनंद लिया। अनुच्छेद 105 (2) के तहत किसी सांसद को ऐसे अपराध के लिए मुकदमा चलाने से छूट प्राप्त नहीं है, जिसमें बोलने या संसद या किसी समिति में वोट देने के लिए रिश्वत की पेशकश या स्वीकार करना शामिल है। उनकी राय में, न्यायमूर्ति अग्रवाल ने इस प्रकार कहा:

13.1. अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रतिरक्षा का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिए विधायक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 105 (2) की व्याख्या जो एक सांसद को रिश्वत के अपराध के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा का दावा करने में सक्षम बनाती है, उन्हें कानून से ऊपर रखेगी। यह संसदीय लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के प्रतिकूल और कानून के शासन के विध्वंसक होगा;

13.2. अभिव्यक्ति "के संबंध में" अनुच्छेद 105 (2) में "कुछ भी कहा या दिया गया कोई भी वोट" शब्दों से पहले आता है। शब्द "कुछ भी कहा या दिया गया कोई वोट" का अर्थ केवल वह भाषण हो सकता है जो दिया जा चुका है या एक वोट जो पहले ही दिया जा चुका है और उन मामलों तक विस्तारित नहीं होता है जहां भाषण नहीं दिया गया है या वोट नहीं डाला गया है। इसलिए, अभिव्यक्ति की व्याख्या करना "के संबंध में" व्यापक रूप से एक विरोधाभाषी स्थिति में परिणाम होगा। एक संसद सदस्य यदि किसी मामले पर न बोलने या अपना मत नहीं देने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है तो उस पर रिश्वतखोरी का मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन यदि वह किसी विशेष तरीके से बोलने या अपना मत देने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है और वास्तव में बोलता है या उस तरीके से अपना मत देता है तो उसे छूट प्राप्त होगी। यह संभावना नहीं है कि संविधान के निर्माताओं ने ऐसा भेद करने का इरादा किया था;

13.3. वाक्यांश "के संबंध में" "से उत्पन्न" का अर्थ करने के लिए व्याख्या की जानी चाहिए। अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रतिरक्षा केवल एक ऐसे कार्य के लिए दायित्व के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए उपलब्ध है जो किसी सांसद द्वारा भाषण देने या वोट देने के परिणामस्वरूप सफल होता है और ऐसे कार्य के लिए नहीं जो भाषण या वोट से पहले होता है और दायित्व को जन्म देता है जो भाषण या वोट से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है;

13.4. आपराधिक साजिश का अपराध रिश्वत के अपराध को करने के लिए एक समझौते के निष्कर्ष पर किया जाता है और समझौते के अनुसार अधिनियम का प्रदर्शन किसी भी परिणाम का नहीं होता है। इसी तरह, प्रस्ताव के खिलाफ बोलने या वोट देने के लिए रिश्वत की स्वीकृति का कार्य सांसद द्वारा भाषण देने या वोट देने से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है। इसलिए, अपराध के लिए दायित्व को "संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में" के रूप में नहीं माना जा सकता है; और

13.5. संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति, इस स्थिति को दर्शाती है कि विधायक को उनकी विधायी गतिविधियों के संबंध में रिश्वत के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। अधिकांश राष्ट्रमंडल देश विधायिका के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को आपराधिक अपराध मानते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी इस संबंध में कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत में विधायक को रिश्वत और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाले कानूनों द्वारा कवर नहीं किया जाना चाहिए, जब अन्य सभी सार्वजनिक पदाधिकारी ऐसे कानूनों के अधीन हैं।

14. जी.एन. रे, न्यायमूर्ति ने एक अलग राय में अग्रवाल, न्यायमूर्ति के तर्क से सहमति व्यक्त की कि एक सांसद भ्रस्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एक लोक सेवक है और भ्रस्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मंजूरी प्राधिकरण के बारे में के सवाल पर। हालांकि, अनुच्छेद 105 (2) की व्याख्या पर, जी.एन. रे, न्यायमूर्ति ने भरूचा, न्यायमूर्ति के फैसले के साथ सहमति व्यक्त की। इसलिए, अनुच्छेद 105 (2) की व्याख्या पर भरूचा, न्यायमूर्ति द्वारा लिखित राय का प्रतिनिधित्व करती है इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के बहुमत के दृष्टिकोण।[10] दूसरी ओर एस.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्ति द्वारा लिखित राय, अल्पसंख्यक के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है।[11]

ग. प्रस्तुतियाँ

15. सुनवाई के दौरान, हमने अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन, भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमानी, भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील श्री पी एस पटवालिया, अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील को सुना। एमिकस क्यूरी, श्री गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ वकील, और श्री विजय हंसारिया, वरिष्ठ वकील, हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश हुए। यह न्यायालय एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते, विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ संक्षेप में नीचे सूचीबद्ध हैं।

16. अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने प्रस्तुत किया कि पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) वर्तमान मामले पर पूरी तरह से लागू होता है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि बहुमत का निर्णय अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है और कानून की स्थापित स्थिति पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है। इस संबंध में, उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी:

16.1. लंबे समय से स्थापित कानून का फैसला पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) न्यायिक मिसालों को पलटने पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पैरीक्षणों के अनुसार अनुचित है;[12]

16.2. सांसदों और विधायक को छूट देने के पीछे का उद्देश्य उन्हें 'ताज की ताकत के दमन से बचाना' था. संसद में वास्तविक मतदान या भाषण देने से कुछ समय पहले या बाद में सांसदों को गिरफ्तार किए जाने की आशंका (कार्यपालिका के खिलाफ निर्देशित ऐसा वोट या भाषण) विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की अवधारणा को पेश करने का सटीक कारण था;

16.3. संवैधानिक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की अवधारणा कानून के शासन का अनादर नहीं करती है, बल्कि यह हमारे संवैधानिक ढांचे की एक विशिष्ट विशेषता है। बहुमत का फैसला बरकरार है सांसदों और विधायक के विशेषाधिकार को विधायक के रूप में उनकी गरिमा की रक्षा करने के लिए और कानून के शासन का विरोध नहीं है;

16.4. बहुमत के फैसले ने अपने सदस्यों द्वारा भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए संसद की विशेष शक्तियों को उचित सम्मान और मान्यता दी, जैसे कि संसद सदन में चर्चा की सीमाओं को पहचानती है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 121 के तहत संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने में असमर्थता;

16.5. भारत और ब्रिटेन में संसदीय विशेषाधिकार पर वर्तमान स्थिति इस बात पर जोर देती है कि यह एक लोकतांत्रिक राजनीति के लिए मौलिक है और अदालतों ने न्यायिक संयम का प्रयोग किया है; और विशेषाधिकार आवश्यक रूप से "विधायी कार्यों" के अभ्यास से संबंधित होना चाहिए, जो भारत में मतदान और भाषण देने से संबंधित है। यह निर्धारित करते समय कि क्या कोई अधिनियम न्यायिक जांच से प्रतिरक्षा है, 'आवश्यकता पैरीक्षण' लागू किया जाना है, अर्थात, क्या प्रश्न में अधिनियम और मतदान/भाषण देने की विधायी प्रक्रिया के बीच कोई संबंध है;

16.6. बहुमत के फैसले में तथाकथित "विसंगति" अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) की सरल भाषा से बहती है और जो प्रतीत होता है कि "तार्किक", "निष्पक्ष" या "उचित" का पालन

करने के लिए उनके सुरक्षात्मक दायरे को कम करने का कोई भी प्रयास संवैधानिक रूप से अनुचित होगा। हालांकि, प्रत्युत्तर में अपनी मौखिक प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाते हुए, श्री रामचंद्रन ने स्वीकार किया कि यह विचार कि मतदान से अनुपस्थित को अनुच्छेद 105 (2) के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा, गलत था और मतदान से दूर रहना, वास्तव में, वोट डालना है;

16.7. अल्पसंख्यक निर्णय पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) ने पढ़ने में गलती की है "के संबंध में " "से उत्पन्न" के रूप में। इस तरह के पठन को या तो सरल भाषा या प्रावधान के इरादे से वारंट नहीं किया जाता है;

16.8. तथ्य यह है कि आपराधिक कानून में रिश्वत का अपराध तब पूरा हो जाता है जब रिश्वत दी जाती है और वादा किए गए पक्ष के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के तहत संवैधानिक प्रतिरक्षा के लिए कोई परिणाम नहीं है। एक बार भाषण दिया जाता है या वोट दिया जाता है, गठजोड़, अर्थात, "के संबंध में", पूरा हो जाता है;

16.9. बहुमत के फैसले को पलटने के गंभीर अनपेक्षित परिणाम होंगे। राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए, यदि सांसदों/विधायक को दी गई संसदीय प्रतिरक्षा को कम कर दिया जाता है, तो यह सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा कानून के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ाएगा; और

16.10, राज्यसभा चुनावों में मतदान अनुच्छेद 194 (2) के संरक्षण के दायरे में है क्योंकि इसमें विधायिका में किसी भी अन्य कानून बनाने की प्रक्रिया के सभी "बंधन" हैं।

17. श्री वेंकटरमणी, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल ने प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण दिया कि निर्णय जो पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले में तत्काल मामले पर लागू नहीं होता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्यसभा चुनाव में विधान सभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा मताधिकार का प्रयोग अनुच्छेद 194 (2) के दायरे में नहीं आता है, और इस प्रकार, पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) वर्तमान मामले में कोई समानता नहीं है। वह प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद 194 (2) का उद्देश्य विधायिका के कार्यों के संबंध में भाषण और आचरण की रक्षा करना है। इसलिये कोई भी आचरण जो विधायी कार्यों से संबंधित नहीं है, जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, अनुच्छेद 194(2) के दायरे से बाहर होगा। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसी अन्य चुनाव प्रक्रिया के समान है और इसे विधायिका के कार्य या कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

18. अटॉर्नी जनरल की इस दलील के जवाब में कि राज्यसभा के लिए मतदान को सदन की कार्यवाही नहीं माना जा सकता है, श्री रामचंद्रन ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, उन्हें ऐसे संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया था जहां संसदीय विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा को लागू करने की मांग की गई थी और 'विधायी कार्यवाही' की अवधारणा का संदर्भ पूरी तरह से अलग संदर्भ में था। इसके अतिरिक्त, कतिपय विधायी प्रक्रियाएं जैसे तदर्थ समितियां, स्थायी समितियां, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सदस्यों के संवैधानिक कार्यालयों के चुनाव आवश्यक रूप से सदन के सत्र के दौरान सदन में नहीं होते हैं। हालांकि, उनके पास 'विधायी प्रक्रिया' को पूरा करने के सभी 'ट्रैपिंगस' हैं।

19. श्री पी एस पटवालिया, एमिकस क्यूरी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निवेदन किया है कि बहुमत के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और अल्पमत का दृष्टिकोण कानून की सही स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। इस संबंध में, श्री पटवालिया ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

19.1. बहुमत के फैसले ने गलती से अभिव्यक्ति "के संबंध में" की व्यापक व्याख्या की है और सांसदों को आपराधिक अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान की जब वे संसद में वोट डालने के लिए रिश्वत स्वीकार करते हैं। अनुच्छेद 105 का उद्देश्य सांसदों को कानून से ऊपर रखना नहीं है जब संसद के सदन में सांसद के प्रवेश करने से पहले अपराध किया गया हो;

19.2. इस न्यायालय के निर्णयों का अनुपात निम्नलिखित है पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) वोट डालने के लिए रिश्वत लेने के लिए सांसदों को प्रतिरक्षा प्रदान करने के खिलाफ है;[13]

19.3. अल्पमत के फैसले में सही ढंग से यह नोट किया गया है कि रिश्वतखोरी का अपराध सदस्य के सदन में प्रवेश करने से पहले ही पूरा हो जाता है और इसलिए, अपराध का उस वोट से कोई संबंध या संबंध नहीं है जो वह संसद में डाल सकता/सकती है। अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के तहत संरक्षण तब उपलब्ध नहीं होता है जब कथित आपराधिक कृत्य संसद के बाहर किए जाते हैं;

19.4. यह प्रस्ताव कि संसद में अपने वोटों के संबंध में सांसदों को रिश्वत के अपराध के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा है, कानून के शासन का उल्लंघन है;

19.5. बहुमत के फैसले के परिणामस्वरूप एक विशेष स्थिति होती है, जहां एक सांसद जो रिश्वत लेता है और अपना वोट नहीं डालता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि वोट डालने वाले सदस्य को प्रतिरक्षा दी जाती है;

19.6. यूनाइटेड किंगडम में कानून की स्थिति, जैसा कि वर्षों से विकसित हुआ है, इस प्रस्ताव की पुष्टि करता है कि विशेषाधिकार के दावे को रिश्वत के अपराध के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है; और

19.7. अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति (विशेषरूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में) यह है कि संसदीय विशेषाधिकार रिश्वत के अपराध तक विस्तारित नहीं है। अल्पमत के फैसले में इस प्रवृत्ति पर सही ढंग से भरोसा किया गया है, जबकि बहुमत का निर्णय उन निर्णयों पर निर्भर करता है जिन्हें बाद में उनके मूल अधिकार क्षेत्र में भी कम कर दिया गया है।

20. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायण ने न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

20.1. जबकि बहुमत के फैसले पर कई मौकों पर संदेह किया गया है, इस न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक निर्णय पर बड़े पैमाने पर भरोसा किया गया है;

20.2. शब्द "कोई भी" संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में नियोजित को एक संकीर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए और यांत्रिक रूप से 'सब कुछ' के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, खासकर जब यह एक असाधारण प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है;

20.3. "के संबंध में" को संकीर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इसे 'वैध कृत्यों' से जोड़ा जाना चाहिए जो विधायी प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं जिसमें संसद में या समिति के समक्ष भाषण या वोट शामिल हैं। कोई अन्य व्याख्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता और जनता द्वारा विधायक में रखे गए विश्वास का उल्लंघन करेगी;

20.4. भ्रष्टाचार से निपटने वाले कानूनों की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए जो सार्वजनिक हित को प्रभावित करते हैं;

20.5. रिश्वतखोरी का अपराध संसद में मतदान दिए जाने या भाषण दिए जाने से पहले ही रिश्वत प्राप्त करने पर पूरा हो जाता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (और धारा 13) के तहत अपराध के लिए 'प्रदर्शन' की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, परिणामों का वितरण स्थापित किए जा रहे अपराध के लिए अप्रासंगिक है और बहुमत द्वारा बनाया गया भेद कृत्रिम है;

20.6. बहुमत के फैसले का प्रभाव यह है कि यह लोक सेवकों का एक नाजायज वर्ग बनाता है जिसे असाधारण सुरक्षा प्रदान की जाती है जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, साथ ही स्पष्ट रूप से मनमाना भी होगा; और

20.7. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में कानूनी स्थिति अल्पसंख्यक निर्णय का समर्थन करती है।

21. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने संसदीय विशेषाधिकारों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुद्दा संसदीय विशेषाधिकारों की रूपरेखा नहीं है, बल्कि यह है कि क्या रिश्वत का अपराध विधायिका के बाहर पूरा हो गया है। मेहता ने प्रस्तुत किया कि 2018 के संशोधन से पहले और बाद में भ्रस्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वत का अपराध, रिश्वत की स्वीकृति पर पूरा हो गया है और यह आधिकारिक कार्य के वास्तविक प्रदर्शन या गैर-प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है, जिससे रिश्वत संबंधित है।

22. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया ने बहुमत के फैसले का विरोध करते हुए तर्कों को पूरक बनाया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संसदीय विशेषाधिकार के सिद्धांत की व्याख्या राजनीति के अपराधीकरण के संदर्भ में और संवैधानिक नैतिकता के चश्मे से की जानी चाहिए। अपने लिखित प्रस्तुतियों में, श्री ए वेलन, हस्तक्षेपकर्ता के वकील ने इस सबमिशन का समर्थन किया कि बहुमत का फैसला पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

घ. पी. वी. नरसिम्हा राव पर पुनर्विचार करना स्टेयर डेसीसिस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है।

23. हम श्री राजू रामचंद्रन के प्रारंभिक तर्क को संबोधित करते हुए शुरू करते हैं, जो कि 1977 में लंबे समय से तय कानून को खत्म कर देता है। पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) न्यायिक मिसाल को पलटने पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित पैरीक्षणों के

प्रासंगिकता के पैरीक्षण से अनुचित है। संदर्भ का क्रम इसके लिए कारण प्रदान करता है प्रत्यक्षतः में पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) निर्णय की शुद्धता पर संदेह करना जो "राजनीति और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के संरक्षण" पर इसके प्रभाव से सम्बंधित है। तथापि, चूंकि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 1999 में निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्रारंभिक आपत्ति को दोहराया है। पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) सात न्यायाधीशों की इस पीठ के समक्ष, तर्क को नीचे संबोधित किया गया है।

24. बड़ी संख्या वाली बेंच द्वारा दिया गया निर्णय कम या सह-समान ताकत वाली किसी भी बाद की बेंच पर बाध्यकारी है। कम संख्या वाली पीठ बड़ी संख्या वाली पीठ द्वारा लिए गए कानून के दृष्टिकोण से असहमत या असहमत नहीं हो सकती है। हालांकि, समान ताकत की एक बेंच एक समन्वय बेंच द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठा सकती है। ऐसी स्थितियों में, मामले को बड़ी ताकत की बेंच के समक्ष रखा जाता है।[14]

25. वर्तमान मामले में, मामले को पहले दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया था। तीन जजों की बेंच ने मामले को पांच जजों की बेंच के पास भेज दिया। न्यायिक अनुशासन के अनुरूप, पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) में लिए गए निर्णय की शुद्धता पर इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की सह-समान पीठ ने एक विस्तृत आदेश में केवल संदेह व्यक्त किया था। इसी के तहत मामले को सात जजों की इस बेंच के सामने रखा गया है।

26. पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) निर्णय की शुद्धता के बारे में संदेह इस न्यायालय द्वारा पिछले कई निर्णयों में भी उठाया गया है। उदाहरण के लिए, कल्पना मेहता बनाम भारत संघ,[15] (डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति) ने रेखांकित किया।

“221. अल्पसंख्यक मत का विचार यह था कि रिश्वत लेने वाले के खिलाफ रिश्वत लेने का अपराध या तो एक निश्चित तरीके से कार्य करने के वादे के लिए पैसे लेने या लेने के लिए सहमत होने पर किया जाता है। इस तर्क के बाद, एस.सी. अग्रवाल, न्यायमूर्ति. ने कहा कि संसद में बोलने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले संसद सदस्य का आपराधिक दायित्व भाषण देने या वोट देने से स्वतंत्र होता है और इसलिए संसद में "कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में" दायित्व नहीं है। बहुमत के फैसले में दृष्टिकोण की शुद्धता वर्तमान मामले में विचार के लिए नहीं आती है। यदि भविष्य में किसी उपयुक्त मामले में यह आवश्यक हो जाता है, तो एक बड़ी पीठ को इस मुद्दे पर विचार करना पड़ सकता है। ” (महत्त्व पर जोर दिया गया)

27. इसी प्रकार की टिप्पणियां इस न्यायालय द्वारा 1996 में की गई हैं। राजा राम श्री पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोक सभा।[16] इस न्यायालय ने कई निर्णयों में अल्पमत के फैसले पर भरोसा किया है, विशेषरूप से कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ.[17] और अमरिंदर सिंह बनाम पंजाब विधानसभा।[18] पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले में लिए गए निर्णय की शुद्धता सीधे इन मामलों में उत्पन्न नहीं हुआ, न्यायालय ने इस निर्णय की शुद्धता के बारे में संदर्भ या निर्णायक टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि, वर्तमान मामला लगभग पूरी तरह से 1995 में निर्धारित कानून पर मुड़ता है। पी. वी. नरसिम्हा(उपरोक्त)

28. पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) इस मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से उत्पन्न होता है जो उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय से स्पष्ट हो जाता है। उच्च न्यायालय ने विचार के लिए प्रश्न तैयार किया कि "क्या भारत के संविधानका अनुच्छेद 194 (2) विधान सभा के सदस्यों को रिश्वत की पेशकश या स्वीकार करने से जुड़े अपराध के आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाने के लिए कोई प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह सटीक प्रश्न है जिस पर इस न्यायालय ने 1999 में निर्णय दिया था। पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) साथ ही, अनुच्छेद 105 (2) के संदर्भ में।

29. इसके अलावा, अपीलकर्ता के वकील और सीबीआई के वकील दोनों ने पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले के तर्क से सहमति जाहिर की। उच्च न्यायालय ने अपने विश्लेषण में कहा कि चूंकि अनुच्छेद 194 (2) पैरी मटेरिया अनुच्छेद 105(2) के अनुसार, पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले के निर्णय के क्षेत्र को कवर करता है। उच्च न्यायालय ने भरोसा किया पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले पर यह धारण बनाने में कि एक सांसद जिसने अपना वोट नहीं डाला है, वह प्रतिरक्षा द्वारा कवर नहीं किया गया है। चूंकि अपीलकर्ता ने सहमति के अनुसार मतदान नहीं किया, इसलिए उसे अनुच्छेद 194 (2) के तहत प्रतिरक्षा से संरक्षित नहीं किया गया था।

30. उच्च न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठा वह पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले में पलट गया। इसलिए, यह कार्यवाही एक बार और सभी के लिए कानून को निपटाने का सही अवसर प्रदान करती है। पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सात न्यायाधीशों के संदर्भ में कोई कमी नहीं है।

31. अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने तर्क दिया है कि कानून की स्थिति जो 1998 से अबाधित है, उसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हम इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं समझते हैं कि वह खुद को स्टेयर डेसीसिस

कानून के जैविक विकास और न्याय की उन्नति के लिए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने की इस न्यायालय की क्षमता को कम करके आंके है। यदि इस न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है, तो संवैधानिक न्यायशास्त्र का विकास लगभग रुक जाएगा। अतीत में, इस न्यायालय ने संविधान के पूर्व निर्माण पर पुनर्विचार करने से परहेज नहीं किया है यदि यह असंगत, अव्यावहारिक या सार्वजनिक हित के विपरीत साबित होता है। इस नाजुक संतुलन को एच.आर. खन्ना, न्यायमूर्ति द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया गया था मगनलाल छगनलाल (पी.) लिमिटेड बनाम म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफ़ ग्रेटर बॉम्बे[19] निम्नलिखित शब्दों में:

" 22. [...] न्यायालय को निश्चितता और निरंतरता की आवश्यकता और कानून की वृद्धि और विकास की वांछनीयता के बीच संतुलन रखना होगा। यह न तो न्यायिक घोषणाओं द्वारा कानून को जीवाश्म कठोरता में बदलने की अनुमति दे सकता है और न ही यह क्रांतिकारी मूर्तिकला को स्थापित सिद्धांतों को दूर करने की अनुमति दे सकता है। एक ओर आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की है कि न्यायिक अविष्कार को समाप्त या अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, दूसरी ओर यह आवश्यक है कि सामान्य मामलों में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के प्रतिस्थापन में नए और नए सिद्धांतों को निर्धारित करने के प्रलोभन पर अंकुश लगाया जाए और समय बीतने से पहले उनकी पवित्रता की पुष्टि होने से पहले नए सिद्धांतों को बहुत जल्दी संत घोषित करने की तत्परता पर अंकुश लगाया जाए। [...]"

32. इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य[20] के सिद्धांत के मद्देनजर अपने स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए इस न्यायालय की शक्तियों को स्टेयर डेसीसिस की अवधारणा के अनुरूप चित्रित किया। एसआर दास, मुख्य न्यायमूर्ति और भगवती, न्यायमूर्ति दोनों ने अपनी अलग-अलग राय में, अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए इस न्यायालय की शक्ति का विस्तार किया, खासकर जब वे संवैधानिक महत्व के मुद्दों को उठाते हैं। एसआर दास, न्यायमूर्ति ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न न्यायालयों में दिए गए निर्णयों का पता लगाया ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इस न्यायालय को अपने पिछले निर्णयों से हटने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, विशेषरूप से संविधान की व्याख्या के सवालों पर। न्यायालय ने कहा कि संविधान की गलत व्याख्या के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति हो सकती है जहां त्रुटि को लंबे समय तक ठीक नहीं किया जाता है, जिससे आम जनता को नुकसान होता है। न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण "जनता के

सामान्य हितों" पर पिछले निर्णय के "हानिकारक प्रभाव" को स्थापित करने में निहित था। यह देखा गया:

“15. [...] एक संघीय संविधान द्वारा शासित देश में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत संघ हैं, संविधान में संशोधन करना किसी भी तरह से आसान नहीं है यदि इस न्यायालय द्वारा इसकी गलत व्याख्या की जाती है। (हमारे संविधान का अनुच्छेद 368 देखें)। संविधान की एक गलत व्याख्या काफी बोधगम्य रूप से कायम रह सकती है या किसी भी दर पर काफी समय तक असुधारित रह सकती है जो सार्वजनिक कल्याण के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ... हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पिछले निर्णय से हटने से रोकता है यदि हम इसकी त्रुटि और जनता के सामान्य हितों पर इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में आश्वस्त हैं। अनुच्छेद 141 जो यह बताता है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के अलावा अन्य अदालतों को संदर्भित करता है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तदनुरूपी उपबंध से यह भी स्पष्ट होता है कि विचाराधीन न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय हैं. ”

(महत्त्व दिया गया)

एनएच भगवती, न्यायमूर्ति ने वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और संविधान की व्याख्या से संबंधित निर्णय से विचलित होने के बीच अंतर पर भी जोर दिया, जबकि यह मानते हुए कि जबकि एक क़ानून की गलत व्याख्या को विधायिका द्वारा ठीक किया जा सकता है, एक अव्यावहारिक व्याख्या को सही करने के लिए संविधान में संशोधन करना उतना आसान नहीं है। एसआर दास, न्यायमूर्ति द्वारा व्याख्या के समान, भगवती, न्यायमूर्ति की राय में पिछले निर्णयों पर पुनर्विचार करने का परिक्षण यह है कि क्या पिछला निर्णय "स्पष्ट रूप से गलत या गलत" है या "सार्वजनिक हित" पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

33. स्टेयर डेसीसिस का सिद्धांत यह प्रावधान करता है कि न्यायालय को मिसाल से हल्के ढंग से असहमति नहीं देनी चाहिए। हालाँकि, इस न्यायालय ने मामलों की एक सुसंगत प्रक्रिया में कई वादों में इसे अभिनिर्धारित किया है,[21] यह सिद्धांत कानून का एक अनम्य नियम नहीं है, और इसके परिणामस्वरूप जनता के सामान्य कल्याण के लिए एक त्रुटि को बनाए नहीं रखा जा सकता है। यह न्यायालय अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है यदि उसे लगता है कि कोई त्रुटि है, या निर्णय का प्रभाव जनता के हितों को नुकसान पहुंचाएगा या यदि "यह संविधान के कानूनी दर्शन के साथ असंगत है"। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों में, यह न्यायालय कानून की अन्य शाखाओं की तुलना में अधिक

तत्परता से ऐसा करेगा क्योंकि प्रकट त्रुटि को नहीं सुधारना सार्वजनिक हित और राजनीति के लिए हानिकारक होगा। जिस समय तक मामले क्षेत्र में रहा है, उसका प्राथमिक परिणाम नहीं है।

इस न्यायालय ने उन निर्णयों को खारिज कर दिया है जिनमें संविधान की व्याख्या शामिल है, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र में कब्जा किया है जब वे संविधान की भावना को ठेस पहुंचाते हैं।

34. पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) में बहुमत का फैसला संवैधानिक व्याख्या के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है जो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को प्रभावित करता है। वर्ष 1998 में फैसले दिए जाने के बाद से इस न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा इस निर्णय को असहमति की टिप्पणियों के साथ देखा गया है। इस मामले में कानून बनाने और असंगति को हल करने का अवसर उत्पन्न हुआ है। यह इस न्यायालय द्वारा मिसाल से हल्के ढंग से उल्लंघन करने का उदाहरण नहीं है। वास्तव में, यह मामला न्यायालय द्वारा मिसाल के नियम को उचित सम्मान देने और 1998 में निर्णय पर पुनर्विचार करने से परहेज करने का एक उदाहरण है जो पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले में जब तक यह विचार के लिए पूरी तरह से उत्पन्न नहीं हुआ।

35. अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। शंकर राजू बनाम भारत संघ[22] , शाह फैसल बनाम भारत संघ[23] , केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी[24] और कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ[25]। ये निर्णय इस प्रस्ताव को दोहराते हैं कि (i) स्टेयर डेसीसिस का सिद्धांत कानून में निश्चितता और स्थिरता को बढ़ावा देता है; (ii) न्यायालय को लापरवाह तरीके से पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए संदर्भ नहीं देना चाहिए; और (iii) कानून की एक स्थापित स्थिति को केवल इसलिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण उपलब्ध है। हालाँकि, ये सभी निर्णय कुछ परिस्थितियों में अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए इस न्यायालय की शक्ति को पहचानते हैं - जिसमें "सार्वजनिक नीति" के लोकाचार शामिल हैं; "जनता की भलाई" और "निरंतर अन्याय को दूर करने के लिए"। उन मामलों में सामने आए तथ्यों में, इस न्यायालय ने पाया कि इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं था।

36. शंकर राजू (उपरोक्त), यह न्यायालय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2006 की व्याख्या और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति से

निपट रहा था। दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह इसी तरह के मुद्दे पर फैसला करने वाली बड़ी संख्या वाली पीठ के फैसले से बंधी हुई है और उस फैसले में लिए गए दृष्टिकोण पर केवल इसलिए पुनर्विचार नहीं कर सकती क्योंकि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण उपलब्ध है।

37. शाह फैसल (उपरोक्त), इस न्यायालय की एक संविधान पीठ इस सवाल पर निर्णय दे रही थी कि क्या याचिकाओं को इस आधार पर सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए कि पांच न्यायाधीशों की पीठों द्वारा कथित रूप से दो विरोधाभाषी निर्णय थे। न्यायालय ने कहा कि बड़ी पीठों का संदर्भ लापरवाही से या दो निर्णयों के बीच मामूली विसंगतियों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। उस संदर्भ में, न्यायालय ने पाया कि निर्णय एक-दूसरे के साथ असंगत नहीं थे और न ही निर्णयों में से एक थे जिन पर पिछली अदालत के फैसले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान या मिसाल पर ध्यान देने में विफल रहे। स्टेयर डेसीसिस के सिद्धांत पर कानून बनाते समय, न्यायालय ने कहा कि कुछ मामलों में न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, खासकर जब वे "असाध्य" या "अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के विपरीत " साबित होते हैं। न्यायालय ने यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रक्रिया में आ रहे संक्रमण का भी उल्लेख किया, पिछले निर्णयों पर पुनर्विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध से लेकर वर्तमान स्थिति तक, जो कुछ परिस्थितियों में निर्णयों को रद्द करने की अनुमति देता है। न्यायालय ने इस आशय की कनाडाई स्थिति का भी हवाला दिया कि जबकि मिसाल को नियमित रूप से पुनर्विचार करने से विचलित नहीं किया जाना चाहिए, पिछले निर्णयों की अनुमति है जब यह "सार्वजनिक हित" में आवश्यक हो।

38. केशव मिल्स (उपरोक्त) में निर्णय ने आयकर अधिनियम, 1922 के प्रावधानों की व्याख्या की और उस मामले की परिस्थितियों में, न्यायालय को कानून के समान बिंदु पर पिछले निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं मिला। न्यायालय ने माना कि यह उन परिस्थितियों में स्वीकार्य है जहां यह "जनता के हितों" में है या यदि कोई अन्य "वैध" या "बाध्यकारी" कारण हैं, तो पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि अपने निर्णयों की समीक्षा करने में न्यायालय के दृष्टिकोण को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करना बुद्धिमानी नहीं होगी क्योंकि यह कई विचारों पर आधारित है, जिसमें "कानून के सामान्य प्रशासन" या "सार्वजनिक भलाई" पर त्रुटि का प्रभाव शामिल है। यह व्याख्या, वास्तव में, उसी कंडिका में निहित है जिस पर अपीलकर्ता स्टेयर डेसीसिस की अवधारणा की कठोर समझ को आगे बढ़ाने के लिए निर्भर करता है। इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने (गजेंद्रगडकर, मुख्य न्यायमूर्ति के माध्यम से बोलते हुए) कहा:

" 23. [...] अपने पहले के फैसले की समीक्षा और संशोधन करते समय, इस न्यायालय को खुद से पूछना चाहिए चाहे वह जनहित में हो या किसी अन्य वैध और बाध्यकारी कारणों से, यह आवश्यक है कि पहले के निर्णय को संशोधित किया जाए। जब यह न्यायालय कानून के प्रश्नों का फैसला करता है, तो अनुच्छेद 141 के तहत इसके निर्णय भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, और इसलिए, देश में कानून की व्याख्या में निश्चितता और निरंतरता के तत्व को पेश करना और बनाए रखना इस न्यायालय का निरंतर प्रयास और चिंता होनी चाहिए। इस न्यायालय द्वारा अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा करने की अपनी शक्ति का बार-बार इस आधार पर प्रयोग करना कि बाद में न्यायालय के समक्ष दबाया गया दृष्टिकोण अधिक उचित प्रतीत होता है, संयोग से कानून को अनिश्चित बना सकता है और भ्रम पैदा कर सकता है जिससे लगातार बचा जाना चाहिए। यह कहना नहीं है कि यदि बाद के अवसर पर, न्यायालय संतुष्ट है कि उसका पहले का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था, तो उसे त्रुटि को ठीक करने में संकोच करना चाहिए; लेकिन इससे पहले कि पिछले निर्णय को स्पष्ट रूप से गलत घोषित किया जाए, न्यायालय को अपने सदस्यों के बीच उचित मात्रा में सर्वसम्मति से संतुष्ट होना चाहिए कि उक्त दृष्टिकोण का संशोधन पूरी तरह से उचित है। यह संभव या वांछनीय नहीं है, और किसी भी मामले में, किसी भी सिद्धांत को निर्धारित करना अनुचित होगा जो अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन के सवाल से निपटने में न्यायालय के दृष्टिकोण को नियंत्रित करे। यह हमेशा कई प्रासंगिक विचारों पर निर्भर करेगा: - दुर्बलता या त्रुटि की प्रकृति क्या है जिस पर पहले के दृष्टिकोण की समीक्षा और संशोधन के लिए एक दलील आधारित है? पहले के अवसर पर, क्या प्रश्न के कुछ पेटेंट पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया था, या न्यायालय का ध्यान किसी प्रासंगिक और भौतिक वैधानिक प्रावधान की ओर आकर्षित नहीं किया गया था, या इस न्यायालय के किसी भी पिछले निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया था? क्या न्यायालय इस तरह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है कि पहले के दृष्टिकोण में ऐसी त्रुटि है? कानून के सामान्य प्रशासन या सार्वजनिक भलाई पर त्रुटि का क्या प्रभाव होगा? क्या पहले के निर्णय का बाद के अवसरों पर या तो इस न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया गया है? और, क्या पहले के निर्णय को पलटने से जनता को अव्यवस्था, कठिनाई या शरारत होगी? इन और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब भी इस न्यायालय को अपने पहले के निर्णयों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। ये विचार तब और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब पहले का निर्णय इस न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ का सर्वसम्मत निर्णय होता है। (महत्त्व दिया गया)

39. इसी तरह कृष्ण कुमार (उपरोक्त) सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन के बारे में एक मामला था। वहाँ भी, हालांकि न्यायालय को उस तथ्यात्मक संदर्भ में अपने पिछले निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए सम्मोहक कारण नहीं मिले, उसने माना कि न्यायालय के पास "निरंतर अन्याय को दूर करने" या "सार्वजनिक नीति के विचारों" के कारण ऐसा करने की शक्ति है।

40. अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत उपरोक्त मामलों में संदर्भ वर्तमान मामले के साथ तुलनीय नहीं है। जैसा कि संदर्भ के क्रम में और इस निर्णय के दौरान निर्धारित किया गया है, पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) का निर्णय का लोकहित, सार्वजनिक जीवन में शुचिता और संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। बहुमत के फैसले में कई स्पष्ट त्रुटियां हैं अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 105 के पाठ की अपनी व्याख्या में; संसदीय विशेषाधिकार के दायरे और उद्देश्य की इसकी अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के प्रति इसका दृष्टिकोण, जिसके परिणामस्वरूप एक विरोधाभाषी परिणाम सामने आया है। वर्तमान मामला वह है जहां इस न्यायालय को एक आसन्न खतरा है कि यदि पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के निर्णय में त्रुटि को बनाए रखने की अनुमति दी जाती है और उस पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है।

41. अंत में, अपीलकर्ता इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करता है जो अजीत मोहन बनाम विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली[26] , जहां इस न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक विशेषज्ञों के बीच "अलग-अलग विचार" हैं कि "क्या विधायी निकायों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए, जैसा कि मूल रूप से संविधान में परिभाषित किया गया है, या (क्या यह) प्रतिबंधित किया जाना है। हालांकि, यह आग्रह किया गया है कि इस न्यायालय ने इस आधार पर इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करने से इनकार कर दिया कि इस तरह की राय संसद पर छोड़ दी जानी चाहिए। अपीलकर्ता प्रस्तुत करता है कि इसी तरह, इस मामले में, न्यायालय को निर्णायक दृष्टिकोण लेने से बचना चाहिए और इस मुद्दे को संसद के निर्धारण के लिए छोड़ देना चाहिए यह तर्क गलत है।

42. यह निर्णय संविधान में परिभाषित संविधान की "शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों" को निर्धारित या प्रतिबंधित करने की कोशिश नहीं करता है। बल्कि, इस निर्णय का एक सीमित अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 की सही

व्याख्या पर निर्णय देने के लिए है। इसलिए, यह न्यायालय संविधान की व्याख्या पर निर्णय दे रहा है, न कि इस सवाल पर कि क्या विशेषाधिकारों को "प्रभाव" दिया जाना चाहिए।

43. एक अलग लेकिन सहमति राय में मार्क ग्रेव्स बनाम न्यूयॉर्क के लोग राज्य[27] संवैधानिक महत्व के प्रश्न पर संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट के पिछले दो फैसलों को खारिज करते हुए, फ्रैंकफर्टर, न्यायमूर्ति ने सारगर्भित रूप से अवलोकन किया:

"न्यायिक व्याख्या हमारे संविधान जैसे अधिनियम के संदर्भ में अपरिहार्य है, जिसे उद्देश्यपूर्ण अस्पष्टता के साथ तैयार किया गया है ताकि विरोधाभाष के लिए जगह छोड़ी जा सके। लेकिन संवैधानिकता की अंतिम कसौटी स्वयं संविधान है, न कि वह जो हमने इसके बारे में कहा है. " (महत्त्व दिया गया)

44. उपरोक्त सूत्रीकरण भारत के संविधान के लिए भी सही है, जो एक परिवर्तनकारी दस्तावेज है जो संवैधानिक व्याख्या के नाजुक मुद्दों को उठाता है। बहुमत के निर्णय के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, हम अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के प्रेषण के रूप में "स्वयं विधान मंडल" द्वारा कही गई बातों के प्रति सच्चे बने रहने का प्रयास करते हैं, भले ही यह अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के संदर्भ में कही गई बातों से दूर जाने की कीमत पर ही क्यों न हो। पी. वी. नरसिम्हा राव (उपरोक्त) मामले में हमारा मानना है कि हमें संविधान की गलत व्याख्या को कायम नहीं रखना चाहिए, केवल इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पिछली राय के प्रति कठोर निष्ठा के कारण।

45. पृष्ठभूमि, प्रस्तुतियाँ और प्रारंभिक मुद्दों पर ध्यान देने के बाद, हम उस विषय की ओर मुड़ते हैं जो विचार के लिए उठता है।

(ड). भारत में संसदीय विशेषाधिकार का इतिहास

46. एक गतिशील लोकतंत्र में, लोगों की आकांक्षाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रवचन द्वारा पूरी की जाती हैं। इन संस्थाओं में संसद और राज्य विधान मंडल सर्वाधिक प्रमुख हैं। लोगों की आकांक्षाओं को जीवन और अर्थ देने के लिए संविधान का उद्देश्य विधायी कार्य, विचार - विमर्श और संवाद के माध्यम से इसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। संसद को "भव्य मंच " कहा जाता है। न केवल तत्कालीन सरकार के कार्यों और विधायी प्राथमिकताओं की जांच की जा सकती है और इसे जवाबदेह ठहराने के लिए आलोचना की जा सकती है, बल्कि संसद व्यक्तियों, नागरिक समाज और सार्वजनिक हितधारकों की शिकायतों को जगह देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करती है। जब संविधान में विचार-विमर्श के लिए जगह

सिकुड़ जाती है, तो लोग संविधान के बाहर बातचीत और लोकतांत्रिक कार्यों का सहारा लेते हैं। संसद में कार्यवाही की जांच करने का नागरिकों का यह विशेषाधिकार एक विचारशील लोकतंत्र का सहवर्ती अधिकार है जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। हमारे संविधान का उद्देश्य ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना है जहां लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के लिए विचार-विमर्श, विचार और प्रतिपक्ष स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए जा सकें।

47. संसद एक सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक संस्था है जो सभी भारतीयों की आकांक्षाओं को साकार करने पर विचार-विमर्श करती है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संसदीय विशेषाधिकारों का आधार विधायकों को सदन के समक्ष कार्य पर स्वतंत्र रूप से विचार करने की सुविधा प्रदान करना है। इसलिए संविधान में भाषण की स्वतंत्रता प्रत्येक विधायी निकाय के लिए एक आवश्यक विशेषाधिकार है।

48. एक विचारशील लोकतंत्र विचार-विमर्श को सुशासन की नैतिकता के रूप में मानता है और यह केवल संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति का अवलोकन राजीव सूरी बनाम डीडीए,[28] के मामले में विचारशील लोकतंत्र की रूपरेखा को इस प्रकार स्पष्ट करता है:

“ 653. विचारशील लोकतंत्र विचार-विमर्श, निर्णय लेने और सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रतियोगिता में भागीदारी के अधिकार पर जोर देता है। निर्णय या कानून के बाद अदालतों के समक्ष प्रतिस्पर्धा भागीदारी का एक रूप है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और न्यायिक समीक्षा की आदरपूर्ण शक्ति के कानूनी सिद्धांतों द्वारा संरचित अदालतों द्वारा अधिनिर्णय, निर्णय लेने के चरण से पहले और उस समय सार्वजनिक भागीदारी का विकल्प नहीं है। एक गणतंत्रात्मक या प्रतिनिधि लोकतंत्र में, नागरिक निर्वाचित सरकार को कानून बनाने और निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जो उनकी ओर से निर्णय लेती है। यह अपरिहार्य और आवश्यक है क्योंकि छोटे समूहों में विचार-विमर्श और निर्णय लेना अधिक कुशल है। इस प्रक्रिया में विशेष रूप से विवादास्पद मामलों में जानकारी एकत्र करने, प्रसंस्करण और निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। निहित स्वार्थों की जांच की जा सकती है। कठिन, फिर भी लाभकारी निर्णयों को लागू किया जा सकता है। सरकारी अधिकारी, कुशल, सूचित और मुद्दों से परिचित और चुनाव और जनादेश द्वारा समर्थित और मतदाताओं से जुड़े राजनीतिक कार्यकारी, निर्णय लेने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित और तैनात हैं। यह निर्वाचित राजनीतिक कार्यकारी को अपनी नीतियों और वादों को वास्तविक व्यवहार में लाने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं और

उनके माध्यम से प्रस्ताव विधानों और नीतिगत उपायों के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हैं। फिर भी, जब आवश्यक होता है, कानूनों के मसौदे को विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श करने के लिए संसदीय समितियों को भेजा जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्राथमिक विधान बनाने की प्रक्रिया सर्वसम्मति प्राप्त करने के तत्व से प्रभाव व मत विभिन्न विचारों और विकल्पों की संभावना, परामर्श और विचार-विमर्श द्वारा संरचित होती है।

656. हालांकि, निर्वाचित प्रतिनिधियों को कानून बनाने और शासन करने की शक्ति का प्रत्यायोजन नागरिकों के जानने और सूचित होने के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं है। लोकतंत्र, लोगों द्वारा, आवधिक जनमत संग्रह का अधिकार नहीं है; या मतदान के अधिकार का प्रयोग करना, और इस तरह निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन करना, संतुष्टि, निराशा व्यक्त करना, अनुमानित नीतियों को अनुमोदित या अस्वीकृत करना। नागरिकों के जानने का अधिकार और सूचित करने का सरकार का कर्तव्य शासन के लोकतांत्रिक रूप के साथ-साथ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में अंतर्निहित है। पारदर्शिता और ग्रहणशीलता दो प्रमुख प्रणोदक हैं क्योंकि यहां तक कि सबसे सक्षम और ईमानदार निर्णय लेने वालों को निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों के बारे में जानकारी के साथ-साथ मौजूदा नीतियों और निर्णयों को व्यवहार में कैसे काम कर रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोनों दिशाओं में सूचना के मुक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है। जब सूचना को रोका/अस्वीकार किया जाता है, तो संदेह और शक को मजबूती मिलती है और मुख्यधारासे कटे हुए लोग और निहित स्वार्थ समूह लाभ उठाते हैं। इससे सामाजिक अस्थिरता हो सकती है। [ओल्सन के 7 वें निहितार्थ के संदर्भ में, "7. वितरणात्मक गठबंधन ..आर्थिक विकास की दर को कम करें ..."' राष्ट्रों का उत्थान और पतन ' मंकुर ओल्सन और उसके बाद के अध्ययनों द्वारा। (महत्त्व दिया गया)

निर्वाचित विधायकों को सदन के पटल पर इस समय के मामलों पर चर्चा और बहस करने की स्वतंत्रता सरकार के संसदीय रूप में एक विचार-विमर्श लोकतंत्र का एक प्रमुख घटक है। विधायकों की अपने कार्यों को एक ऐसे वातावरण में संचालित करने की क्षमता जो जबरदस्ती या भय से अभिभूत हुए बिना ऐसा करने की उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है, संवैधानिक रूप से सुरक्षित है। नागरिकों के रूप में, विधायकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। इससे आगे बढ़ते हुए, संविधान संघ और राज्यों दोनों के विधानसभाओं में बोलने और बहस करने की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। यह व्यक्तिगत विधायकों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है। इस अधिकार को मान्यता संवाद,

वाद-विवाद और आलोचना के प्रमुख घटकों के रूप में संसद और राज्य विधानसभाओं की संस्थागत नींव को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर आधारित है जो लोकतंत्र को बनाए रखता है।

49. भारतीय संदर्भ में, विचारशील लोकतंत्र के साथ-साथ विधायिकाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आवश्यक विशेषाधिकार को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के संघर्ष के बाद के इतिहास और विकास के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। भारत इतिहास में एक उदाहरण प्रदान करता है जहां प्रतिनिधि संस्थान चरणों में विकसित हुए हैं। भारत में विधानमंडलों के विशेषाधिकार इन संस्थानों के इतिहास के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। इस इतिहास को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में संसदीय विशेषाधिकारों के इतिहास के साथ-साथ औपनिवेशिक शासन के तहत इन विशेषाधिकारों का दावा करने के लिए भारतीय विधानमंडलों के संघर्ष में खोजा जा सकता है। भारत में राजनीतिक और संसदीय शासन लाने के लिए औपनिवेशिक शासन के तहत जो कदम उठाए गए थे, वे हमेशा भारतीयों की आकांक्षाओं से कम थे। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि ब्रिटिश शासन भारतीयों की स्वतंत्र होने की इच्छा के लिए प्रतिरोधी था। इसलिए, भारतीय विधायिकाओं को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के तुलनीय विशेषाधिकार प्राप्त होने के लिए स्वीकार नहीं किया गया था। कीली बनाम कार्सन[29] के मामले में प्रिवी काउंसिल ने प्रतिपादित किया था कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स ने प्राचीन उपयोग द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे और औपनिवेशिक विधायिकाओं के पास नहीं था *लेक्स एट कंसुएटुडो पार्लियामेंट* या संसद के कानून और रिवाज के रूप में उनके अधिकार एक क़ानून से निकले थे। इसका अर्थ यह था कि औपनिवेशिक शासन के तहत विधायिकाओं को कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं दिए गए थे।

50. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत, कानून बनाना 1833 तक कार्यकारी के अनन्य क्षेत्राधिकार में था। भारत सरकार अधिनियम 1833 ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को विशेष विधायी शक्तियों के साथ भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया था। गवर्नर-जनरल में चार सदस्य होने थे, जिनमें से एक कानून सदस्य होगा जो विधायी उद्देश्यों को छोड़कर परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं था। यह भारत में विधायिकाओं के लिए एक परिचयात्मक उपाय था क्योंकि गवर्नर-जनरल की परिषद अपने कार्यकारी कार्यों और विधायी कार्यों को करने के लिए अलग-अलग बैठकें आयोजित करेगी। इस प्रक्रिया की परिकल्पना भारत में विशाल और विविध सामाजिक परिवेश में कानूनों को लागू करने में सुविधा के लिए की गई थी, न कि बेहतर कानूनों को तैयार करने के साधन

के रूप में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की इच्छा के लिए। हालांकि, विधायकों के कर्तव्यों को पूरा करने में विधायी विशेषाधिकारों की आवश्यकता को दर्शाते हुए, पहले कानून सदस्य, लॉर्ड मैकाले ने अपने मसौदा स्थायी आदेशों द्वारा शक्तियों की प्रकृति में कुछ विशेष सुविधाओं को सुरक्षित करने के प्रयास किए। इन विशेष सुविधाओं में कानून के विषय पर पूरी जानकारी प्रदान करना, गवर्नर-जनरल की परिषद की सभी बैठकों में उपस्थित होने का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता और मतदान की स्वतंत्रता शामिल थी।[30]

51. गैर-विधायी व्यवसाय में भी उपस्थिति और मतदान के विशेषाधिकार चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा बढ़ाए गए थे। इसने कार्यकारी और विधायी कार्यों के एक और पृथक्करण को चिह्नित किया। विधान परिषद में विधायी कार्य को करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त सदस्य होने चाहिए थे और जांच के तहत कानूनों पर अपना स्वतंत्र विचार देना था। विधान परिषद में इन सदस्यों को क़ानून द्वारा कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति को उन्हें निहित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने के रूप में माना गया था। इसलिए परिषद ने ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के आसपास एक मिनी संसद के समान शक्तियों को ग्रहण करने का प्रयास किया। 1833 और 1853 के अधिनियमों के तहत विधान परिषद के पास प्रक्रिया के अपने नियम बनाने की शक्ति थी।

52. यह शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में छीन ली गई थी। हालांकि, 1861 के अधिनियम की धारा 10 ने विधान परिषदों में छह से बारह गैर-सरकारी सदस्यों के बीच पेश किया, जो ब्रिटिश हो सकते थे या भारतीय। इन अतिरिक्त सदस्यों की बोलने और वोट देने की स्वतंत्रता की एक अंतर्निहित मान्यता थी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषदों के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार के अस्तित्व को मान्यता दी थी, जिसकी पुष्टि भारत के राज्य सचिव ने भी की थी।[31] फिर भी, 1861 अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त रूप से कड़े थे और परिषद को अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमित दायरे से परे कोई गतिविधि करने की अनुमति नहीं देते थे। इसके अलावा, आधिकारिक सदस्यों और मनोनीत भारतीय सदस्यों द्वारा प्रभावी रूप से प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक स्पष्ट अंतर था।[32]

53. भारत सरकार अधिनियम 1909 ने भारत की राजनीतिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। अधिनियम ने अधिक भारतीयों को विधान परिषदों का हिस्सा बनने की अनुमति दी और उनके कार्यों का विस्तार किया। सदस्यों को कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। यह अधिनियम परिषद में

भारतीयों के अप्रत्यक्ष चुनाव को निर्धारित करके चुनावी और प्रतिनिधि शासन के लिए एक रास्ता था। तथापि, इन परिषदों में भी कतिपय विषयों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई थी। गैर-आधिकारिक सदस्यों ने परिषद में मुक्त भाषण के विशेषाधिकार का दावा करना जारी रखा। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने के बावजूद, भारत में विधायिकाओं के भारतीय सदस्यों ने भारत में औपनिवेशिक शासन की कठोरता को कम कर दिया। आधिकारिक समर्थन के अभाव में, विशेषाधिकार कानून के बजाय एक सम्मेलन के रूप में विकसित हुए। कार्यपालिका ने विधान परिषद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता महसूस की और किसी भी दर पर यह सुनिश्चित किया कि भारत में परिषदों के पास यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के समान कोई विशेषाधिकार नहीं है।[33]

54. भारत सरकार अधिनियम 1919 ने विधायिका को कार्यकारी नियंत्रण से अलग कर दिया। इसने प्रशासकों के दो वर्गों को निर्धारित करके द्शासन की शुरुआत की - कार्यकारी पार्षद जो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं थे और मंत्री जो विधायिका के विश्वास का आनंद लेंगे। इस अधिनियम ने विधायिकाओं को पहले की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान कीं। हालांकि, सदस्यों को उन विषयों की श्रेणी पर प्रतिबंधित किया गया था, जिन पर वे चर्चा कर सकते थे, भाग ले सकते थे और वोट दे सकते थे। 1919 के अधिनियम या सदन की प्रक्रिया के नियमों में कई विशेषाधिकार निर्दिष्ट नहीं किए गए थे। फिर भी, विधायिका ने विधायिका के निहित अधिकार के रूप में विशेषाधिकारों का दावा किया एक अनिच्छुक कार्यकारी के रूप में। भारत की औपनिवेशिक सरकार की हिचकिचाहट का कारण यह था कि एक विदेशी शक्ति द्वारा संचालित सरकार भारतीय विधायकों को उनकी संप्रभु शक्तियों को रखने की मान्यता के रूप में संसदीय विशेषाधिकार देने के लिए तैयार नहीं थी।[34] 1919 के अधिनियम ने विधानमंडल के सदनों को बोलने की स्वतंत्रता का एक योग्य विशेषाधिकार दिया। 1919 अधिनियम की धारा 24(7) इस प्रकार है:

"(7) राज्य सभा को प्रभावित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, राज्यपालों की विधान परिषदों में वाक् स्वातंत्र्य होगा। कोई व्यक्ति ऐसी किसी परिषद् में अपने भाषण या मत के कारण या ऐसी किसी परिषद् की कार्यवाहियों की किसी शासकीय रिपोर्ट में अंतवष्ट किसी बात के कारण किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रांतीय विधान परिषदों के संबंध में अधिनियम की धारा 11 7) में संगत प्रावधान किया गया था। विधान परिषदों में भाषण की स्वतंत्रता गवर्नर-जनरल द्वारा प्रख्यापित नियमों के अधीन थी। इसलिए, जबकि भाषण की स्वतंत्रता को विधान परिषदों तक बढ़ाया गया था, उन्हें अंततः विधायिका के नियम बनाने की शक्ति के लिए गवर्नर-जनरल और भारत के राज्य सचिव की खुशी के अधीन बनाया गया था। इसलिए अधिनियम ने भारतीय विधायिकाओं को बोलने की स्वतंत्रता देने के प्रावधान नहीं किए, बल्कि इसका उद्देश्य सदन में बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना था। इन प्रतिबंधों ने सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने और कानून पेश करने के लिए विधायिकाओं की क्षमता को भौतिक रूप से बाधित किया। हालाँकि, अधिनियम ने विधायिका को अपने विशेषाधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की।

55. भारत सरकार अधिनियम 1919 की शुरुआत के कुछ वर्षों के भीतर 1924 में एक समिति की स्थापना की गई थी। समिति को 1919 के अधिनियम में कठिनाइयों या दोषों की जांच करने और उन्हें सुरक्षित करने के उपायों की खोज करने का काम सौंपा गया था। 1924 की सुधार समिति ने भारतीय विधायी निकायों के विशेषाधिकारों का संदर्भ दिया और कहा कि:

"... वर्तमान में ऐसी कार्रवाई असामयिक होगी। साथ ही, हम यह भी महसूस करते हैं कि विधायिका और उनके सदस्यों को भारत सरकार अधिनियम द्वारा वे सभी सुरक्षा नहीं दी गई हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। कानून के तहत सभी विधानसभाओं में भाषण की स्वतंत्रता है और भाषणों या वोटों के संबंध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से प्रतिरक्षा है। नियमों के तहत राष्ट्रपतियों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वहां मामला समाप्त हो जाता है।"[35]

56. दिलचस्प बात यह है कि समिति ने सुझाव दिया कि भारतीय विधायिकाओं को कुछ अतिरिक्त विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। समिति ने विधायिका के भीतर वोटों को प्रभावित करने के लिए एक दंड प्रावधान शुरू करने की सिफारिश की जो अन्य बातों के साथ-साथ रिश्वतखोरी से सम्बंधित थी। रिपोर्ट में कहा गया है:

"हमें यह समझने के लिए दिया गया है कि वर्तमान में विधायिका के भीतर वोटों के भ्रष्ट प्रभाव से निपटने का कोई साधन नहीं है। हमारी सर्वसम्मत राय है कि रिश्वतखोरी, धमकी और इस तरह के अन्य तरीकों से सदस्यों के वोटों को प्रभावित करने के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए। यहां भी हम यह सिफारिश नहीं करते हैं कि इस मामले को

विशेषाधिकार हनन के रूप में निपटाया जाना चाहिए। हम वकालत करते हैं कि इन अपराधों को सामान्य कानून के तहत दंडनीय बनाया जाना चाहिए।“

57. सरकार ने एक विधायी निकाय भ्रष्ट आचरण विधेयक पेश किया जिसमें (i) अपने कार्यों के संबंध में विधायिका के सदस्य को रिश्वत की पेशकश; और (ii) विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा अपने कार्यों के संबंध में रिश्वत की मांग पर रसीद।[36] विधेयक अंततः व्यपगत हो गया और इसे पुनः पुनर्स्थापित नहीं किया गया।

58. 1919 अधिनियम के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 28(1) में काफी हद तक बरकरार रखा गया था। धारा 28(1) इस प्रकार पढ़ें:

"(1) इस अधिनियम के उपबंधों और संघीय विधान-मंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, विधान-मंडल में वाक् की स्वतंत्रता होगी और विधान-मंडल का कोई सदस्य विधान-मंडल या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए दायी नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति किसी रिपोर्ट, कागज, मत या कार्यवाही के विधानमंडल के किसी भी चैम्बर के अधिकार के तहत प्रकाशन के संबंध में इतना उत्तरदायी नहीं होगा।“

प्रांतीय विधानमंडलों के संबंध में 1935 के अधिनियम की धारा 71(1) में संगत प्रावधान किया गया था। सदन को कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। हालांकि, उन्हें हमेशा सदन के लिए गवर्नर-जनरल द्वारा बनाए गए नियमों को रास्ता देना था। भारत में संसदीय विशेषाधिकारों ने जड़ें जमा ली थीं क्योंकि सांसदों ने भारतीय जरूरतों के हिसाब से उचित समायोजन के साथ ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ समानता की मांग की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत में विधायकों ने महसूस किया कि इन विशेषाधिकारों के अभाव में उनके विधायी कार्यों का निर्वहन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। विधायकों की मांगों में सदन की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, सदन के मामलों में अध्यक्ष की सर्वोच्चता, भाषण की स्वतंत्रता और सदस्यों को कार्यवाही में भाग लेने और अपने कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति देने के लिए गिरफ्तारी से स्वतंत्रता शामिल थी।

59. किसी भी बिंदु पर इन विशेषाधिकारों को आपराधिक कानून से एक कंबल प्रतिरक्षा के रूप में नहीं मांगा गया था। औपनिवेशिक अनिच्छा के बावजूद भी, भारत में संसदीय विशेषाधिकारों की मांग हमेशा उस रिश्ते से जुड़ी रही जो उसने उन कार्यों से बोर की थी जिन्हें भारतीय विधायकों ने निर्वहन करने की मांग की थी।

60. यह पृष्ठभूमि तब बनी जब संविधान सभा संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 85 और 169 के भाग्य का फैसला कर रही थी, जो तब से संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 बन गए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं का इरादा था कि संविधान 'आधुनिकीकरण' करने वाली शक्ति बने। लोकतंत्र का संसदीय स्वरूप संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित इस आधुनिकीकरण प्रभाव का पहला स्तर था।[37] इसलिए संविधान का जन्म आदर्शवाद के वातावरण और स्वतंत्रता के संघर्ष से पैदा हुए उद्देश्य की ताकत में हुआ था। संविधान निर्माताओं का इरादा एक ऐसा संविधान बनाने का था जो आधुनिक भारत का मार्ग प्रशस्त करे।[38]

61. जब संविधान सभा ने संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 85 पर चर्चा के लिए बुलाया, तो श्री एचवी कामथ ने ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटाने और संविधान के लागू होने से ठीक पहले इसे भारत में डोमिनियन विधानमंडल के साथ बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया। इस संशोधन का विरोध करते हुए श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा, "जहां तक मुझे पता है कि हमारे पास कोई विशेषाधिकार नहीं है और यदि वह चाहते हैं कि हमारे सभी विशेषाधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो उनका स्वागत है।[39] इसलिए संविधान सभा के सदस्य इस बात से अच्छी तरह अवगत थे कि औपनिवेशिक शासन के तहत उनके विशेषाधिकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह 'प्राचीन और निस्संदेह' नहीं थे, बल्कि एक वैधानिक अनुदान था जो लगातार अधिनियमों और विधायिकाओं द्वारा जोर देकर किया गया था।

(च). भारत में संसदीय विशेषाधिकार का अभिप्राय

1. कार्यात्मक विश्लेषण

62. अनुच्छेद 105 जो संविधान के भाग V अध्याय II में स्थित है, संसद, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। राज्य विधानमंडलों से संबंधित एक समान प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 194 में है। अनुच्छेद 105 इस प्रकार है:

“105. संसद के सदनों की और उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।

1. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद में वाक् स्वातंत्र्य होगी।

2. संसद का कोई सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उतरदायी नहीं होगा और कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार उतरदायी नहीं होगा जो वोट या कार्यवाही से सम्बंधित है।

3. अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वे होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा विधि द्वारा परिभाषित की जाएं, और जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती हैं, तब तक वे संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की होंगी, 1978।

4. खंड(1), खंड(2) और खंड(3) के उपबंध उन व्यक्तियों के संबंध में लागू होंगे जिन्हें इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है जैसा कि वे संसद सदस्यों के संबंध में लागू करते हैं।

63. संविधान के अनुच्छेद 105 में चार खंड हैं। खंड (1) घोषणा करता है कि संसद में वाक् की स्वतंत्रता होगी। यह स्वतंत्रता संविधान और संसद में प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है। इसलिए, संसद में भाषण की स्वतंत्रता उन प्रावधानों के अधीन होगी जो अनुच्छेद 118 के तहत तैयार की गई प्रक्रिया को विनियमित करते हैं। यह अनुच्छेद 121 के अधीन भी है जो संसद को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से

प्रतिबंधित करता है, सिवाय उस प्रस्ताव के जो न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करते हुए राष्ट्रपति को एक अभिभाषण प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर है। अनुच्छेद 105 (1) के तहत संसद में गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता से अलग है। अलगापुरम आर मोहनराज बनाम तमिलनाडु विधान सभा[40] इस न्यायालय ने इन स्वतंत्रताओं में अंतर को निम्नानुसार चित्रित किया:

(क). जबकि अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत गारंटीकृत भाषण का मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक में निहित है, अनुच्छेद 105 और 194 के तहत अपेक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि केवल विधायिका के एक सदस्य के लिए उपलब्ध है;

(ख). अनुच्छेद 105 केवल उन निकायों के सदस्यों के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध है। दूसरी ओर, के तहत मौलिक अधिकार - अनुच्छेद 19 (1) (क) अपरिहार्य है;

(ग). अनुच्छेद 105 विधायी निकायों के परिसर तक सीमित है। अनुच्छेद 19 (1) (क) में ऐसी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है; और

(घ). अनुच्छेद 19 (1) (क) उचित प्रतिबंधों के अधीन है जो अनुच्छेद 19 (2) के अनुरूप हैं। हालांकि, अनुच्छेद 105 या 194 के तहत एक विधायक को उपलब्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ऐसी सीमाओं के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 105 के खंड (1) में संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया गया है, यह बताता है कि यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त भाषण की स्वतंत्रता से स्वतंत्र है और उसमें निहित अपवादों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

64. अनुच्छेद 105 के खंड (2) के दो अंग हैं। पहली यह निर्धारित करती है कि संसद का कोई सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में उनके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी अदालत के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा अंग विहित करता है कि कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किसी रिपोर्ट, कागज, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। संसद के एक सदस्य द्वारा दिया गया वोट भाषण का विस्तार है। इसलिए, संसद के सदस्य की वोट डालने की स्वतंत्रता भी संसद में भाषण की स्वतंत्रता द्वारा संरक्षित है। तेज किरण जैन बनाम एन संजीव रेड्डी,[41] इस न्यायालय की छह-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि अनुच्छेद 105 (2) "कुछ भी कहा" के संबंध में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जब तक कि यह "संसद में" है। इसलिए, प्रतिरक्षा इस तथ्य से योग्य है कि

इसे संसद में कार्य के संचालन के दौरान भाषण के लिए आकर्षित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने माना कि "कुछ भी" शब्द सबसे व्यापक आयात का है और "सब कुछ" के बराबर है। यह केवल "संसद में" शब्द द्वारा सीमित है।

65. खंड (1) और (2) संसद में वाक् स्वतंत्रता की स्पष्ट गारंटी देते हैं। खंड (1) एक सकारात्मक अभिधारणा है जो भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है जबकि खंड (2) उसी स्वतंत्रता का विस्तार है जिसे नकारात्मक रूप से पोस्ट किया गया है। यह भाषण की रक्षा करके, और एक वोट के विस्तार से, अदालत के समक्ष कार्यवाही से ऐसा करता है। संसद के सदनों और उनकी समितियों में भाषण की स्वतंत्रता एक आवश्यक विशेषाधिकार है, जो सदन के कामकाज के लिए आवश्यक है। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, संसद या विधानमंडल के सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विशेषाधिकार को भारतीय विधायकों के संघर्ष में खोजा जा सकता है और औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रगति पर प्रदान किया गया था। यह विशेषाधिकार न केवल संसद और उसके सदस्यों की अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक विधायी संस्था के कार्य के मूल में भी है। संसद और संविधान के सदस्य लोगों की इच्छा और उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान को आधुनिक प्रभाव डालने के लिए अपनाया गया था। संविधान का उद्देश्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव पर आधारित अन्यायपूर्ण समाज से बचना और एक समतावादी समाज की ओर बढ़ने का मार्ग सुगम बनाना है। संसद और विधानसभाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ही आकांक्षा का एक अंग है ताकि सदस्य अपने मतदाताओं की शिकायतों को व्यक्त कर सकें, विविध दृष्टिकोण व्यक्त कर सकें और अपने मतदाताओं के दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकें। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि सरकार को सदन द्वारा जवाबदेह ठहराया जाए। कल्पना मेहता (उपरोक्त) में हम में से एक (डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति) को इस विशेषाधिकार के महत्व को स्पष्ट करने का अवसर मिला था:

“ 181. […] संसद अपने सदस्यों के प्रतिनिधि स्वरूप के माध्यम से लोगों की आवाज और आकांक्षाओं का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करती है। संसद के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन के लिए महत्वपूर्ण है। यह उनके विचारों की निडर अभिव्यक्ति के माध्यम से है कि सांसद उन लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पीछा करते हैं जो उन्हें चुनते हैं। भाषण की शक्ति निर्वाचित सरकारों से लोकतांत्रिक जवाबदेही को सटीक करती है। संवाद का मुक्त प्रवाह यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने और सरकारी नीतियों की

देखरेख करने में, संसद मतदाताओं के विविध विचारों को दर्शाती है जो एक निर्वाचित संस्था का प्रतिनिधित्व करती है।

182. संविधान अनुच्छेद 19 (1) (क) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 105(1) में इस अधिकार की अलग से अभिव्यक्ति से पता चलता है कि संसद में बहस और विचारों की अभिव्यक्ति को प्रारूपकारों ने कितना महत्वपूर्ण माना है। अनुच्छेद 105(1) साधारण पुनरावृत्ति या अधिशेष नहीं है। यह इस मूलभूत मूल्य का प्रतीक है कि संसद में आलोचना की स्वतंत्र और निडर व्याख्या लोकतंत्र का सार है। संसद के निर्वाचित सदस्य नागरिकों की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिकों की चिंताओं को अभिव्यक्ति देने में, संसदीय भाषण लोकतंत्र को बढ़ाता है। [...]"

(महत्त्व दिया गया)

66. उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह भारत के पास 'प्राचीन और निस्संदेह' अधिकार नहीं हैं जो संसद और नरेश के बीच संघर्ष के बाद निहित किए गए थे। इसके विपरीत, भारत में विशेषाधिकार हमेशा क़ानून द्वारा शासित होते थे। संविधान के प्रारंभ के बाद वैधानिक विशेषाधिकार एक संवैधानिक विशेषाधिकार में परिवर्तित हो गया। हालाँकि, जबकि संविधान के प्रारूपकारों ने संसद में बोलने की स्वतंत्रता की स्पष्ट रूप से परिकल्पना की, उन्होंने अन्य विशेषाधिकारों को कानून के माध्यम से संसद द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया। अनुच्छेद 105 के खंड (3) में कहा गया है कि अनुच्छेद 105 के खंड (1) और (2) के तहत नहीं आने वाले विशेषाधिकारों के संबंध में, संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जा सकती हैं। जब तक संसद इन विशेषाधिकारों को परिभाषित नहीं करती है, तब तक वे वही होंगे जो सदन और उसके सदस्यों और समितियों को संविधान (चवालीसवें संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के लागू होने से ठीक पहले प्राप्त थे। धारा 15 इस प्रकार है:

"15. अनुच्छेद 105 का संशोधन– संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (3) में, "इस संविधान के प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडम की संसद के हाउस ऑफ कामन्स और उसके सदस्यों और समितियों के होंगे" शब्दों के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन के और उसके सदस्यों और समितियों के होंगे। 1978" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

67. संविधान में चवालीसवें संशोधन की धारा 15 के लागू होने से ठीक पहले सदन और उसके सदस्यों और समितियों को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, वे भारत के संविधान के प्रारंभ में ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा प्राप्त किए गए थे। यह अनुच्छेद 194 के खंड (3) के मामले में भी था जिसे संविधान के चवालीसवें संशोधन की धारा 26 द्वारा संशोधित किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को संविधान सभा ने दो कारणों से स्वीकार किया था। पहला, संविधान के लागू होने से पहले भारतीय विधायकों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था और इसलिए डोमिनियन संसद का संदर्भ सदन को वस्तुतः बिना किसी विशेषाधिकार के छोड़ देगा। दूसरा, उस समय विशेषाधिकारों की एक विस्तृत सूची बनाना संभव नहीं था और न ही संविधान की अनुसूची के रूप में इतनी लंबी सूची को सूचीबद्ध करना बेहतर था।[42]

68. खंड (3) संसद को समय-समय पर अपने विशेषाधिकारों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में यू.. नए विशेषाधिकार नहीं बनाता है।[43] इसके विशेषाधिकार वे हैं जो सभा द्वारा व्यवहार में लाए गए हैं और प्राचीन और निस्संदेह हो गए हैं।

69. इसके अलावा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के विपरीत, भारत में संसद अपनी स्वयं की संरचना की शक्ति का दावा नहीं कर सकती है। भारत में विशेषाधिकारों की सीमा संविधान की सीमाओं के भीतर होनी चाहिए। इस योजना के भीतर, न्यायालयों के पास यह निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या संसद या विधानमंडल के सदन द्वारा दावा किया गया विशेषाधिकार वास्तव में मौजूद है और क्या उनका सही ढंग से प्रयोग किया गया है। दृष्टांत की एक सतत पंक्ति में, इस न्यायालय ने माना है कि विशेषाधिकारों पर कानून की अनुपस्थिति में, संसद या विधानमंडल केवल ऐसे विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं जो संविधान के प्रारंभ के समय हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित था और सदन अपने विशेषाधिकार का फैसला करने वाला एकमात्र न्यायाधीश नहीं है।

70. जब संसद या विधानमंडल विशेषाधिकारों पर कानून बनाते हैं, तो ऐसा कानून संविधान के भाग III की जांच के अधीन होगा। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 105(3) के बीच परस्पर क्रिया इस न्यायालय के 1996 के निर्णय में उत्पन्न हुई। एमएसएम शर्मा बनाम श्रीकृष्ण सिन्हा,[44] जहां एक संविधान पीठ ने एसआर दास, मुख्य न्यायमूर्ति के माध्यम से बोलते हुए कहा कि अनुच्छेद 105 के खंड (3) के तहत संसद के सदन के विशेषाधिकार वे हैं जो संविधान के प्रारंभ में ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित थे, जो संविधान के

अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रबल होंगे। हालाँकि, यदि संसद को अपने विशेषाधिकार को संहिताबद्ध करने के लिए एक कानून बनाना था, तो यह संविधान के अनुच्छेद 13 के आधार पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। के सुब्बा राव, न्यायमूर्ति (जैसा कि उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने बहुमत से असहमति जताई और कहा कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा आयोजित विशेषाधिकारों का आयात केवल एक क्षणिक प्रावधान था जब तक कि संसद या विधायिका अपने संबंधित विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने वाला कानून नहीं बनाती हैं। इसलिए, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अपनी असहमति में कहा कि विधायिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किसी तरह से नहीं चल सकती है, जिन्होंने सिद्धांत रूप में अपने अधिकारों को बरकरार रखा है और केवल विधायिका को इसका एक हिस्सा दिया है।

71. 1964 का विशेष रिफेंस नंबर 1 ,[45] इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों पर राय दी। यह संदर्भ यूपी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की गिरफ्तारी और पेशी का निर्देश देने के बाद था। दोनों न्यायाधीशों ने एक ऐसे व्यक्ति को फटकार लगाने के प्रस्ताव में हस्तक्षेप किया था जिसने विधानसभा के सदस्यों में से एक को बदनाम करने वाला एक पर्चा प्रकाशित किया था। बहुमत के लिए बोलने वाले मुख्य न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने 1995 में इस फैसले से असहमति नहीं जताई। एमएसएम शर्मा (उपरोक्त) जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 105 (3) और अनुच्छेद 194 (3) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) पर प्रबल होंगे। हालाँकि, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 105 (3) और 194 (3) पर दोनों के बीच संघर्ष में प्रबल होना था। न्यायालय ने माना कि संसद या विधानमंडल अपने विशेषाधिकारों का एकमात्र न्यायाधीश नहीं है और अदालतों के पास यह जांचने की शक्ति है कि क्या वास्तव में विधायिका द्वारा दावा किया गया कोई विशेष विशेषाधिकार वास्तव में मौजूद है या नहीं, कॉमन्स के विशेषाधिकारों से परामर्श करके। विशेषाधिकारों का निर्धारण, न्यायालय ने कहा, और क्या वे संविधान के मापदंडों के अनुरूप हैं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अदालतों द्वारा दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने कहा कि:

“37. अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, वह श्री सीरवई द्वारा उठाए गए प्रारंभिक विवाद से उत्पन्न होता है कि सदन की ओर से हमारे समक्ष उपस्थित होने से, सदन को अनुच्छेद 194 (3) को बाध्य करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, उनका दृष्टिकोण यह है कि विशेषाधिकारों के मामले में, सभा सभी चरणों में एकमात्र और अनन्य न्यायाधीश है। […]

42. इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अनुच्छेद 194 (3) की सामग्री अंततः अदालतों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, न कि विधायिका द्वारा हम संविधान के अंतर्गत विधायिका को सौंपे गए कार्य की भव्यता और वैभव से अनभिज्ञ नहीं हैं। मोटे तौर पर बोलते हुए, आज हमारे देश के सभी विधायी कक्ष एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिसे संविधान द्वारा हमारे देश के समक्ष रखा गया है, और यह स्वाभाविक रूप से आज इतिहास के निर्माण में विधायी कक्षों को उच्च स्थान देता है। [...]"

(महत्त्व दिया गया)

72.1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1 (उपरोक्त) की पुष्टि इस न्यायालय की एक अन्य सात-न्यायाधीश पीठ ने 1995 में की थी। की स्थिति कर्नाटक बनाम भारत संघ[46] जिसमें कहा गया था कि जब भी कोई सवाल उठता है कि क्या सदन के पास अपने विशेषाधिकारों के तहत किसी मामले पर अधिकार क्षेत्र है, तो इस तरह के दावे का निर्णय विशेष रूप से अदालतों में निहित है। 1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1 (उपरोक्त) पर भरोसा और कर्नाटक राज्य (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ राजा राम पाल (उपरोक्त) ने माना कि अदालत के पास यह जांचने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र है कि क्या सदन (या विस्तार से एक सदस्य) द्वारा दावा किया गया विशेषाधिकार वास्तव में संविधान के तहत अर्जित होता है। इसके अलावा, में अमरिंदर सिंह (उपरोक्त) इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना कि अदालतों को सदन द्वारा विशेषाधिकारों के प्रयोग की जांच करने का अधिकार है।[47] नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संसद या विधानमंडल के सदनों के विशेषाधिकारों के बीच परस्पर संबंध इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष 1995 में लंबित है। एन रवि बनाम अध्यक्ष, विधान सभा चेन्नई।[48]

73. अनुच्छेद 105 का खंड (4) उपरोक्त खंडों में उन सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करता है जिन्हें संविधान के आधार पर संसद में बोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 105 और 194 में चार खंड एक समग्र संपूर्ण बनाते हैं जो एक दूसरे को रंग देते हैं और एक साथ संसद या विधानमंडल के सदनों, और सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का कोष बनाते हैं।

74. हमने संसदीय विशेषाधिकारों के प्रक्षेपवक्र का पता लगाया है, विशेष रूप से भारतीय विधायिकाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। विधायकों का यह कालातीत आग्रह रहा है कि उनके आवश्यक विधायी कार्यों को करने के लिए उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित और पवित्र किया जाए। जबकि हमारे संविधान के प्रारूपकारों ने संसद और विधायिका में

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्पष्ट गारंटी दी है, उन्होंने अन्य विशेषाधिकारों को असंहिताबद्ध छोड़ दिया है।

75. एक सुसंगत दृष्टांत में इस न्यायालय ने माना है कि - सबसे पहले, संसद या राज्य विधानमंडल इस बात का एकमात्र न्यायाधीश नहीं है कि उसे कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं और दूसरा, संसद या विधानमंडल केवल उन विशेषाधिकारों का दावा कर सकते हैं जो सदन के कामकाज के लिए आवश्यक और आवश्यक हैं। हमने ऊपर इन अंगों में से पहले का पता लगाया है। अब हम संसद के सदन, उसके सदस्यों और समितियों द्वारा विशेषाधिकारों के अस्तित्व, विस्तार और प्रयोग पर न्यायशास्त्र का विश्लेषण करेंगे।

2. सदन के सामूहिक अधिकार के रूप में संसदीय विशेषाधिकार

76. एर्स्किन के अनुसार, संसदीय विशेषाधिकार प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से "संसद के उच्च न्यायालय" के एक घटक भाग के रूप में और प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कुछ अधिकारों का योग है, जिसके बिना वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे, और जो अन्य निकायों या व्यक्तियों के पास अधिक हैं।[49] 'संसद का उच्च न्यायालय' शब्द उस समय का है जब कानून बनाने और न्याय देने की सभी शक्तियां सम्राट में निहित थीं, जिन्होंने बदले में उन्हें एक निकाय में विभाजित कर दिया जो संसद के उच्च न्यायालय में बैठे राजा के रूप में विधायिका के कार्य को पूरा करेगा। उस सीमा तक, यह शब्द भारतीय संदर्भ में निरर्थक है जहां संविधान सर्वोच्च है और इसके अधिकार क्षेत्र में संसद की शक्ति संविधान से प्रवाहित होती है और उसके द्वारा परिभाषित की जाती है। हालांकि, परिभाषा संसदीय विशेषाधिकारों के अर्थ और प्रेषण को समझने के लिए एक आधिकारिक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। परिभाषा स्पष्ट रूप से विशेषाधिकारों को दो घटक तत्वों में विभाजित करती है। पहला संसद के सदन द्वारा प्राप्त अधिकारों का योग है और दूसरा व्यक्तिगत रूप से सदन के सदस्यों द्वारा प्राप्त अधिकारों का योग है। अधिकार और उन्मुक्तियां जैसे कि अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति, सदन की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति या सदन के शेष सत्र के लिए किसी सदस्य को निष्कासित करने की शक्ति, सदन द्वारा अपने उचित कार्य, सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक सामूहिक निकाय के रूप में रखे गए विशेषाधिकारों के पहले तत्व से संबंधित हैं, और अपने स्वयं के अधिकार और गरिमा की पुष्टि। सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों के दूसरे तत्व में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से स्वतंत्रता शामिल है।

77. व्यक्तिगत रूप से सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विशेषाधिकार बदले में इसकी आवश्यकता से योग्य है, जिसमें विशेषाधिकार ऐसा होना चाहिए कि "जिसके बिना वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। हम इस निर्णय के दौरान बाद में इस अंग को स्पष्ट करेंगे। सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त ये विशेषाधिकार सदन के सामूहिक कार्यों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने और सुविधाजनक बनाने का एक साधन हैं।[50] इसलिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि सदन के सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार अन्य निकायों या व्यक्तियों के पास मौजूद विशेषाधिकार से अधिक हैं, वे पूर्ण या अयोग्य नहीं हैं। किसी व्यक्तिगत सदस्य का विशेषाधिकार केवल तब तक विस्तारित होता है जब तक कि यह सदन को कार्य करने में सहायता करता है और जिसके बिना सदन सामूहिक रूप से अपने कार्यों को करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

78. सुभाष सी. कश्यप ने संसदीय विशेषाधिकारों की व्याख्या की है क्योंकि उन्हें भारतीय संदर्भ में समझा जा सकता है।[51] संसदीय प्रक्रिया पर अपनी पुस्तक में लेखक ने इस प्रकार विचार व्यक्त किया है-

"[...] संसदीय बोलचाल में विशेषाधिकार शब्द का अर्थ है संसद के प्रत्येक सदन और उसकी समितियों को सामूहिक रूप से तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियां जिनके बिना वे अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद और उसके सदस्यों की संस्था की स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा की रक्षा करना है। उन्हें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। संसदीय विशेषाधिकार सदस्यों को समाज के प्रति उन दायित्वों से छूट नहीं देते हैं जो अन्य नागरिकों पर लागू होते हैं। संसद के विशेषाधिकार किसी संसद सदस्य को देश के कानूनों के लागू होने के मामले में एक सामान्य नागरिक से अलग पायदान पर नहीं रखते हैं जब तक कि ऐसा करने के लिए संसद के हित में अच्छे और पर्याप्त कारण न हों। मूल सिद्धांत यह है कि संसद सदस्यों सहित सभी नागरिकों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सदस्यों को विशेषाधिकार तभी उपलब्ध होते हैं जब वे संसद सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहे हों और अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन कर रहे हों। (महत्त्व दिया गया)

79. जो समझ स्पष्ट रूप से उभरती है, वह इस दावे का समर्थन करती है कि सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वे अपने आप में अंत नहीं हैं।

विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि वे सदन और उसकी समितियों के कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, हम संसदीय विशेषाधिकारों को उन अधिकारों और उन्मुक्तियों के रूप में समझ सकते हैं जो संसद के व्यवस्थित, लोकतांत्रिक और सुचारू संचालन की अनुमति देते हैं और जिनके बिना सदन के आवश्यक कामकाज का उल्लंघन होगा।

80. संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र स्थापित करना था। एक दमनकारी औपनिवेशिक सरकार के इतिहास को देखते हुए, जिसके अधीन भारत था, इस तरह के लोकतंत्र का मूल्य और महत्व संविधान के निर्माताओं पर भारी पड़ा। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार ने भारत को एक जिम्मेदार सरकार से वंचित कर दिया था, जहां शुरू में भारतीयों को उन कानूनों पर कानून बनाने से बाहर रखा गया था जो इसके विविध सामाजिक संरचना पर लागू किए जाएंगे। यहां तक कि जब भारतीयों को विधायिका में अनुमति दी गई थी, तब भी एक उत्तरदायी सरकार जो सार्थक तरीके से लोगों के प्रति जवाबदेह हो सकती थी, औपनिवेशिक काल में एक दूर की वास्तविकता थी। कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने के लिए विधायिका की क्षमता समाप्त हो गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1919 में सदन के सदस्यों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वैधानिक गारंटी के बावजूद, गारंटी इस हद तक भ्रामक बनी रही कि कई विषयों पर विधानसभाओं में चर्चा करने से प्रतिबंधित किया गया था।

81. इस अर्थ में, जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रतिनिधित्व पर आधारित एक विचारशील लोकतंत्र की नींव यह सुनिश्चित करने की मांग करती है कि उस समय की कार्यकारी सरकार संसद या विधानसभाओं द्वारा चुनी जाती है और उसके लिए जिम्मेदार होती है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये प्रतिनिधि नागरिकों की ओर से अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार उनकी आकांक्षाओं, शिकायतों और शिकायतों पर ध्यान दे। सभा के कार्यकरण का यह पहलू एक सार्थक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि सदन के सदस्य सदन में उपस्थित हो सकें और उसके बाद अपने कर्तव्यों के अभ्यास में सदन के सदस्यों के रूप में अपने कार्यों के आधार पर कार्यपालिका या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा परेशान किए जाने के डर के बिना अपने मन की बात कह सकें। इस विशेषता के अभाव में संसद और राज्य विधानसभाएं लोकतांत्रिक राजनीति में अपने प्रतिनिधि चरित्र का सार खो देंगी।

82. संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत निहित विशेषाधिकार व्यापक आयाम के हैं, लेकिन इस हद तक कि वे उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जिनके लिए उन्हें प्रदान किया गया है। संविधान के निर्माताओं का इरादा विधायिका को वे अधिकार प्रदान करने का नहीं होगा जो सदन के समुचित कामकाज के लिए किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार व्यक्तिगत रूप से सदन की क्षमता के लिए एक कार्यात्मक संबंध रखते हैं ताकि वह सामूहिक रूप से अपने कामकाज को पूरा कर सके और अपने अधिकार और गरिमा को सही ठहरा सके। दूसरे शब्दों में, ये स्वतंत्रताएं एक विचार-विमर्श, महत्वपूर्ण और उत्तरदायी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। केरल राज्य बनाम के. अजीत,[52] हम में से एक (डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति) ने माना कि विधायिका के एक सदस्य, विपक्ष को शामिल किया गया है, को विधायिका के पटल पर विरोध करने का अधिकार है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 105 (1) के तहत गारंटीकृत उक्त अधिकार सदन के सदस्य के रूप में व्यक्ति के कर्तव्यों के प्रत्यक्ष अभ्यास में नहीं होने वाले कृत्यों के खिलाफ सामान्य आपराधिक कानून के आवेदन को बाहर नहीं करेगा। इस न्यायालय ने माना कि संविधान एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मान्यता देता है जिसमें सदन के सदस्य अपने कार्यों का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सकते हैं। ये विशेषाधिकार एक विधायक के कार्यों के निर्वहन के लिए एक कार्यात्मक संबंध रखते हैं। वे स्थिति का निशान नहीं हैं जो विधायकों को एक असमान कुरसी पर खड़ा करता है।

83. एमएन कौल और एसएल शकधर ने संसद की प्रथा और प्रक्रिया पर अपने प्रसिद्ध कार्य में यह कहते हुए इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि[53]

"आधुनिक समय में, संसदीय विशेषाधिकार को कार्यकारी प्राधिकरण के खिलाफ संसद के संघर्ष के शुरुआती दिनों की तुलना में एक अलग कोण से देखा जाना चाहिए। उस समय विशेषाधिकार को संसद के सदस्यों के संरक्षण के रूप में एक कार्यकारी प्राधिकरण के खिलाफ माना जाता था जो संसद के लिए जिम्मेदार नहीं था। संसद के विशेषाधिकारों को अब जिस संपूर्ण पृष्ठभूमि में देखा जाता है, वह बदल गई है क्योंकि कार्यपालिका अब संसद के प्रति उत्तरदायी है। जिस नींव पर वे टिकी हुई हैं वह सदन और इसके सदस्यों की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखना है। " (महत्त्व दिया गया)

सदन के सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार सामूहिक रूप से सदन के कामकाज के लिए आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। संसद या विधानमंडल का एक सदन अपने व्यक्तिगत सदस्यों

की सामूहिक इच्छा के माध्यम से कार्य करता है। सदन के घटक के रूप में कार्य करने वाले ये सदस्य किसी भी विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं जो पूरे सदन के कामकाज से संबंधित नहीं है।

84. जबकि भाषण की स्वतंत्रता सहित सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग की जाने वाली कुछ पोषित स्वतंत्रताओं को निर्विवाद रूप से सदन के कामकाज के लिए आवश्यक समझा गया है, अन्य अभ्यास जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या हिंसा करना प्रतिरक्षा नहीं है और न ही माना जा सकता है। संसद के सदनों और विधानमंडलों, उनके सदस्यों और समितियों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में निहित विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां क्रमशः सदन से संबंधित हैं। सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से विशेषाधिकारों के प्रयोग का पैरीक्षण इस निहाई पर किया जाना चाहिए कि क्या यह सदन के स्वस्थ और आवश्यक कामकाज से जुड़ा हुआ है।

3. विशेषाधिकार का दावा करने और प्रयोग करने के लिए आवश्यकता पैरीक्षण

85. यह स्थापित करने के बाद कि सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को सदन के कामकाज से जोड़ा जाना चाहिए, अब हमें यह पता लगाना चाहिए कि सदन को सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत सदस्यों को विस्तार से कौन से विशेषाधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। कर्नाटक राज्य (उपरोक्त) में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने एमएच बेग, सीजे के माध्यम से बोलते हुए कहा कि अनुच्छेद 194 (साथ ही अनुच्छेद 105) के तहत शक्तियां वे हैं जो प्रत्येक सदन के व्यवसाय के संचालन के लिए निर्भर करती हैं और आवश्यक हैं। इस अर्थ में, ये शक्तियां उन सभी विशेषाधिकारों पर भी लागू नहीं हो सकती हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त होती हैं लेकिन सदन के कामकाज के लिए आवश्यक नहीं हो सकती हैं। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा:

“57. जिस अध्याय में अनुच्छेद 194 का उल्लेख है, साथ ही शीर्षक और उसके सीमांत नोट से यह स्पष्ट है कि यहां इंगित की जाने वाली "शक्तियां" स्वतंत्र नहीं हैं। वे ऐसी शक्तियाँ हैं जो प्रत्येक सदन के कार्य संचालन के लिए निर्भर करती हैं और आवश्यक हैं। उन्हें सभी उद्देश्यों के लिए इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी विस्तारित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के पास विधायी शक्ति का उतना ही हिस्सा है जितना कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास पूरी तरह से संप्रभु विधायिका के एक घटक भाग के रूप में है। हमारे कानून के अंतर्गत संविधान

संप्रभु या सर्वोच्च है। संसद के साथ-साथ भारत में एक राज्य के प्रत्येक विधानमंडल को केवल वही विधायी शक्तियां प्राप्त हैं जो संविधान उसे प्रदान करता है। इसी प्रकार, संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का विधायी शक्ति में उतना हिस्सा होता है जितना कि संविधान द्वारा उसे सौंपा गया है। [...]" (महत्त्व दिया गया)

86. इस न्यायालय ने माना कि भारत में प्राधिकरण का स्रोत संविधान है जो लोगों से अपनी संप्रभुता प्राप्त करता है। किसी सदन द्वारा जिन शक्तियों और विशेषाधिकारों का दावा किया जाता है, वे संविधान के तहत अनुमेय शक्तियों और विशेषाधिकारों से आगे नहीं बढ़ सकते। संविधान केवल उन शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के प्रयोग की अनुमति देता है जो सदन या उसकी एक समिति के कामकाज के लिए आवश्यक हैं।

एमएन कौल और एसएल शकधर ने कहा है कि[54]

"अतः इन विशेषाधिकारों की व्याख्या करते समय इस सामान्य सिद्धांत का ध्यान रखा जाना चाहिए कि संसद के विशेषाधिकार सदस्यों को इस प्रकार प्रदान किए जाते हैं कि "वे संसद में अपने कर्तव्यों का निर्वाह बिना किसी बाधा के कर सकें। वे व्यक्तिगत सदस्यों पर लागू होते हैं "केवल जहां तक वे हैं यह आवश्यक है कि सभा स्वतंत्र रूप से अपने कृत्यों का पालन कर सके। वे सदस्य को समाज के प्रति दायित्वों से मुक्त नहीं करते हैं जो उस पर उतना ही और शायद अधिक निकटता से लागू होते हैं, जितना कि वे अन्य विषयों पर लागू होते हैं। विशेषाधिकार संसद के सदस्य को विधियों को लागू करने के मामले में किसी संसद सदस्य को साधारण नागरिक से भिन्न दर्जा नहीं देते हैं जब तक कि ऐसा करने के लिए स्वयं संसद के हित में अच्छे और पर्याप्त कारण न हों। (महत्त्व दिया गया)

87. संसदीय विशेषाधिकारों के विकास के साथ-साथ इस न्यायालय के न्यायशास्त्र से यह स्थापित होता है कि सदन के सदस्य या वास्तव में सदन स्वयं विशेषाधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं जो अनिवार्य रूप से उनके कामकाज से संबंधित नहीं हैं। संसद या विधानमंडल के कामकाज से असंबद्ध किसी भी विशेषाधिकार को आवश्यकता से देने के लिए नागरिकों का एक वर्ग बनाना है जो कानून के सामान्य अनुप्रयोग से अनियंत्रित छूट प्राप्त करता है। यह न तो संविधान का इरादा था और न ही संसद और विधानमंडल को शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करने का लक्ष्य था।

88. अमरिंदर सिंह (उपरोक्त) में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना कि विशेषाधिकारों के प्रयोग की जांच करने का परीक्षण यह है कि क्या वे विधायी कार्यों की अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक थे। केजी बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश ने इस विषय

पर सामग्री के स्रोत की खोज करने के बाद कहा कि विशेषाधिकार सदन की अखंडता की रक्षा के विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इस न्यायालय ने माना कि विशेषाधिकार अपने आप में एक अंत नहीं हैं, लेकिन विधायी कार्यों के प्रभावी अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि:

" 35. विधायी विशेषाधिकारों के विकास का पता मध्ययुगीन इंग्लैंड में लगाया जा सकता है जब सम्राट और संसद के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। ज्यादातर मामलों में, संसद सदस्यों को दूसरों के बीच सम्राट द्वारा अनुचित दबाव या प्रभाव से बचाने के लिए विशेषाधिकारों का प्रयोग किया गया था। इसके विपरीत, संसद के धीरे-धीरे मजबूत होने के साथ विधायी विशेषाधिकारों के नाम पर कुछ ज्यादतियां भी हुईं। हालाँकि, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले विचारों में तब से भारी बदलाव आया है। आधुनिक संसदीय लोकतंत्रों में, यह विधायिका है जिसमें लोगों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिनसे कार्यकारी कार्यों की निगरानी करने की उम्मीद की जाती है। यह "सामूहिक जिम्मेदारी" के विचार को मूर्त रूप देकर प्राप्त किया जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि जो लोग कार्यकारी शक्ति का उपयोग करते हैं वे विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं।

36. हालांकि, विधायी विशेषाधिकार एक अलग उद्देश्य की सेवा करते हैं। उनका प्रयोग उन अवरोधों के खिलाफ विधायी कार्यों की अखंडता की रक्षा के लिए किया जाता है जो सदन के सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों के कारण हो सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, यह बोधगम्य है कि कुछ मामलों में कार्यकारी पद धारण करने वाले व्यक्ति संभावित रूप से विधायी कार्यों में बाधा पैदा कर सकते हैं। इसलिए, उन ऑपरेटिव सिद्धांतों पर जोर देने की आवश्यकता है जिन पर वर्तमान मामले में विधायी विशेषाधिकारों के प्रयोग की वैधता का परीक्षण करने के लिए भरोसा किया जा सकता है।

47. [...] विधायी विशेषाधिकारों का प्रयोग अपने आप में एक अंत नहीं है। उनका प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि विधायी कार्यों को बिना किसी अनुचित बाधा के प्रभावी ढंग से किया जा सके। इन कार्यों में सदस्यों के बोलने और सदन के पटल पर मतदान करने के अधिकार के साथ-साथ विभिन्न विधायी समितियों की कार्यवाही शामिल है। इस संबंध में, प्रशासनिक कर्मचारियों के रूप में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। विधायी विशेषाधिकारों के प्रयोग की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण विचार यह है कि क्या विधायी कार्यों की अखंडता की रक्षा के लिए यह आवश्यक था। [...]." (महत्त्व दिया गया)

89. लोकायुक्त में, न्यायमूर्ति रिपुसूदन दयाल बनाम मप्र राज्य,[55] इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सदन और उसके सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार के दायरे को सदन के स्वतंत्र कामकाज के लिए विशेषाधिकार की आवश्यकता के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने आगे कहा कि सदन के सदस्य संविधान के तहत सदन के सदस्यों के रूप में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों की आड़ में सामान्य आपराधिक कानून के आवेदन से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। पी सदाशिवम, मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि

"51. प्राप्त विशेषाधिकारों का दायरा विशेषाधिकारों की आवश्यकता पर निर्भर करता है अर्थात उन्हें क्यों प्रदान किया गया है। सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों का मूल आधार यह है कि उन्हें सदस्यों के रूप में अपने कार्यों का निष्पादन करने दिया जाए और सभा के कार्यकरण में कोई बाधा उत्पन्न न हो। [...]

52. यह स्पष्ट है कि मूल अवधारणा यह है कि विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जिनके बिना सदन अपने विधायी कार्यों का प्रदर्शन नहीं कर सकता है. वे सदस्यों को किसी भी कानून के तहत उनके दायित्वों से छूट नहीं देते हैं जो आम नागरिकों पर लागू होने वाले किसी अन्य कानून की तरह उन पर लागू होते रहते हैं। इस प्रकार, विधान सभा के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच या जांच को विधानसभा के विधायी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता है। आपराधिक अभियोजन के खिलाफ किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।

76. यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेषाधिकार केवल तभी तक उपलब्ध हैं जब तक वे आवश्यक हों ताकि सदन स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का पालन कर सके. कानूनों के लागू होने के लिए, विशेष रूप से, लोकायुक्त अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के लिए, लोकायुक्त या मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना का अधिकार क्षेत्र सभी लोक सेवकों (लोकायुक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर) के लिए है और अधिकारियों को कोई विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है और, किसी भी मामले में, वे एक सामान्य नागरिक, जिस पर उक्त अधिनियमों के प्रावधान लागू होते हैं, से अधिक किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते। विशेषाधिकार सदन के बाहर की जाने वाली गतिविधियों तक विस्तारित नहीं होते हैं, जिन पर विधायी प्रावधान बिना किसी भेदभाव के लागू होंगे। (महत्त्व दिया गया)

90. संसदीय विशेषाधिकारों का पता लगाने के लिए आवश्यकता परीक्षण ने भारतीय संदर्भ में गहरी जड़ें जमा ली हैं। हमें इस समय इस विषय पर भारतीय न्यायशास्त्र की उपर्युक्त

व्याख्या से परे अन्य न्यायालयों में आवश्यकता परीक्षण पर अच्छी तरह से स्थापित न्यायशास्त्र का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न संसदीय न्यायालयों में संसदीय विशेषाधिकारों के विकास ने एक सुसंगत पैटर्न दिखाया है कि जब विशेषाधिकारों से संबंधित कोई मुद्दा उठता है, तो लागू परीक्षण यह है कि क्या दावा किया गया विशेषाधिकार सदन या इसकी समिति के व्यवस्थित कामकाज के लिए आवश्यक और आवश्यक है। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि इस बात को संतुष्ट करने का भार कि विशेषाधिकार मौजूद है और सभा के लिए सामूहिक रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करना आवश्यक है, विशेषाधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति या निकाय के पास है। संसद या विधानसभाओं के सदन, और समितियां द्वीप नहीं हैं जो सामान्य कानूनों के आवेदन से अंदर के लोगों को बचाने के लिए एन्क्लेव के रूप में कार्य करती हैं। कानून बनाने वाले उसी कानून के अधीन हैं जो कानून बनाने वाला निकाय उन लोगों के लिए लागू करता है जिन्हें वह नियंत्रित करता है और प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है।

91. हम मानते हैं कि संसद या विधानमंडल के किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का दावा दो गुना परीक्षण द्वारा शासित होगा। सबसे पहले, दावा किए गए विशेषाधिकार को सदन के सामूहिक कामकाज से जोड़ा जाना चाहिए, और दूसरा, इसकी आवश्यकता को एक विधायक के आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक कार्यात्मक संबंध होना चाहिए।

(छ). रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है

1. रिश्वत किसी भी कही गई बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में नहीं है

प्रश्न यह है कि क्या ये विशेषाधिकार संसद या विधानमंडलों के किसी सदस्य को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं जो अपने भाषण या वोट के संबंध में रिश्वत में संलग्न हैं। सदन के कामकाज के आंतरिक संबंध का पैरीक्षण और अनुच्छेद 105 (3) और 194 (3) के तहत विशेषाधिकारों के प्रेषण का निर्धारण करने के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा विकसित आवश्यकता परीक्षण को प्रावधानों के खंड (1) और (2) के तहत विशेषाधिकारों को चित्रित करते समय तौलना चाहिए। जब इस न्यायालय को संविधान के एक प्रावधान की व्याख्या के सवाल का जवाब देने के लिए कहा जाता है, तो उसे पाठ की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जो संविधान के ताने-बाने के लिए हिंसा न करे। पी वी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) में इस न्यायालय की राय संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (2) में दो वाक्यांशों पर टिका है। ये वाक्यांश "के संबंध में" और निम्नलिखित शब्द "कुछ भी" थे। खंड (2) लेख इस प्रकार है

"(2) संसद का कोई सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किसी प्रतिवेदन के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार उतरदायी नहीं होगा, कागज, वोट या कार्यवाही के सम्बन्ध में।

93. राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम भारत संघ,[56] में दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय को एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करनी चाहिए और पाठ में विशिष्ट शब्दों के अर्थ को उस संदर्भ में समझना चाहिए जिसमें उक्त प्रावधान के अन्य शब्दों का उल्लेख करते हुए शब्द होते हैं। इस न्यायालय ने उस मामले में कहा कि "कोई भी" शब्द का अर्थ उस संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है जिसमें यह प्रकट होता है और "किसी भी मामले" शब्द को "हर मामले" के रूप में नहीं समझा जाना था।

94. निर्णय - तेज किरण जैन (उपरोक्त) ने अनुच्छेद 105 के खंड (1) में "कुछ भी" शब्द की व्याख्या सबसे व्यापक आयाम के रूप में की और केवल इसके बाद आने वाले शब्दों के अधीन जो "संसद में" थे। यह खंड संसद में अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता प्रदान करता है। 'कुछ भी' शब्द की व्याख्या यह निर्धारित करने में अदालत के हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए नहीं की जा सकती है कि क्या भाषण उस विषय से संबंधित था जिस पर भाषण दिया गया था। तेज किरण जैन (उपरोक्त) में अस्पृश्यता पर भाषण देने वाले एक धार्मिक प्रमुख के अनुयायियों ने उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जिसमें भाषण पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में कथित रूप से की गई मानहानि के लिए हर्जाने की मांग की गई। इस न्यायालय ने माना कि न्यायालय संसद में दिए गए भाषण का विश्लेषण नहीं कर सकता है और निर्णय नहीं दे सकता है कि भाषण का उसके समक्ष विषय वस्तु से सीधा संबंध है या नहीं। संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है कि वह किन मामलों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करती है और उसके बाद बोलने के लिए स्वतंत्र सदस्यों या व्यक्तियों को सदन में कही गई किसी भी बात के खिलाफ मुकदमा चलाने के डर के अधीन नहीं किया जा सकता है।

95. यह संदर्भ स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 105 के खंड (2) में बदलता है जो सदन के सदस्यों और समितियों को किसी भी अदालत में "कुछ भी" कहा या सदन में दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी कार्यवाही में प्रतिरक्षा देता है। एमएच बेग, मुख्य न्यायमूर्ति में कर्नाटक राज्य (उपरोक्त) ने एक ऐसी स्थिति का पूर्वाभास किया था जहां सदन में एक

आपराधिक कृत्य किया जा सकता है और यह देखा था कि इसे संविधान के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि:

" 63. [...] संसद या राज्य विधानमंडल का एक सदन किसी को या किसी भी मामले को सीधे नहीं देख सकता है, जैसा कि न्याय न्यायालय कर सकता है, लेकिन यह अपने अधिकार की अवमानना के मामलों में अर्ध-न्यायिक रूप से आगे बढ़ सकता है और अपने "विशेषाधिकारों" और "उन्मुक्तियों" से संबंधित प्रस्तावों को ले सकता है, क्योंकि ऐसा करने में, यह केवल अपने विधायी कार्यों के उचित प्रदर्शन के लिए बाधाओं को हटाने की मांग करता है। लेकिन, यदि क्षेत्राधिकार का कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला यहां आता है या नहीं, तो इसका निर्णय सामान्य न्यायालयों द्वारा उचित कार्यवाही में किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी सदन के भीतर किए गए हत्या जैसे आपराधिक अपराध पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र साधारण आपराधिक अदालतों में निहित होता है, न कि सदन में। संसद या राज्य विधानमंडल में . [...]" (महत्त्व दिया गया)

96. के. अजित (उपरोक्त) के मामले में केरल विधान सभा के एक सदस्य पर राज्य के वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने के दौरान अध्यक्ष के मंच पर चढ़ने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या सदस्य पर विधानमंडल के सदन के भीतर उसके आचरण के लिए न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है। इस न्यायालय ने ब्रिटेन में इस संबंध में कानून के विकास की खोज के बाद हम में से एक (डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति) के माध्यम से बोलते हुए कहा कि:

" 36. यह स्पष्ट है कि सदन की सीमा के भीतर आपराधिक अपराध करने वाला व्यक्ति पूर्ण विशेषाधिकार नहीं रखता है। इसके बजाय, उसके पास एक योग्य विशेषाधिकार होगा, और प्रतिरक्षा प्राप्त होगी केवल तभी जब कार्रवाई का संबंध सभा में सदस्य की प्रभावी भागीदारी से हो ."

97. इस न्यायालय ने आगे कहा कि विधायिका के अंदर अर्जित विशेषाधिकार कानून के सामान्य अनुप्रयोग से छूट का दावा करने का प्रवेश द्वार नहीं हैं:

" 65. विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा भूमि के सामान्य कानून से छूट का दावा करने के लिए प्रवेश द्वार नहीं हैं, विशेष रूप से इस मामले में, आपराधिक कानून जो प्रत्येक नागरिक की कार्रवाई को नियंत्रित करता है। आपराधिक कानून के आवेदन से छूट का दावा करना उस विश्वास को धोखा देना होगा जो कानून के निर्माताओं और निर्माताओं के रूप में निर्वाचित

प्रतिनिधियों के चरित्र पर प्रभावित होता है। लोक अभियोजक द्वारा धारा 321 के तहत वापसी के लिए आवेदन जिस पूरी नींव पर पेश किया गया था, वह अनुच्छेद 194 में निहित संवैधानिक प्रावधानों की मूलभूत गलत धारणा पर आधारित है। ऐसा लगता है कि लोक अभियोजक विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अस्तित्व से प्रभावित हुए हैं जो अभियोजन पक्ष के रास्ते में खड़े होंगे। इस तरह की समझ संवैधानिक प्रावधान को धोखा देती है और एक गलत धारणा पर आगे बढ़ती है कि विधायिका के निर्वाचित सदस्य आपराधिक कानून के सामान्य अनुप्रयोग से ऊपर खड़े होते हैं। (महत्त्व दिया गया)

98. लोकायुक्त मामले में, न्यायमूर्ति रिपुसूदन दयाल (उपरोक्त) भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता में कथित रूप से संलग्न होने के लिए मध्य प्रदेश विधान सभा के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने लोकायुक्त और सतर्कता अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू की। इस न्यायालय ने यह मानते हुए कि भ्रष्टाचार के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करना विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता है, यह कहा था कि:

“48. यह स्पष्ट है कि कानूनों के आवेदन के मामले में, विशेष रूप से, लोकायुक्त अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों में, जहां तक लोकायुक्त या मध्य प्रदेश विशेष स्थापना के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, लोकायुक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी लोक सेवक एक ही श्रेणी में आते हैं और अधिक विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं एक साधारण नागरिक की तुलना में जिस पर उक्त अधिनियमों के प्रावधान लागू होते हैं। […].

49. जैसा कि भारत में श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा ठीक ही प्रस्तुत किया गया है, कानून का शासन है और पुरुषों का नहीं है और इस प्रकार, विधायिका द्वारा अधिनियमित कानूनों की प्रधानता है जो उन व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करती है जिन पर ऐसे कानून लागू होंगे। कानून ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जब तक कि कानून स्वयं एक वैध वर्गीकरण पर अपवाद नहीं बनाता है। कोई भी व्यक्ति कानूनों के आवेदन के खिलाफ और निषिद्ध अधिनियम के कमीशन पर बांधी गई देनदारियों के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। (महत्त्व दिया गया)

99. उपरोक्त मामलों से जो सिद्धांत उभरता है वह यह है कि सदन, उसके सदस्यों और समितियों का विशेषाधिकार न तो केवल स्थान पर आकस्मिक है और न ही वे केवल विचाराधीन अधिनियम पर आकस्मिक हैं। संसद या विधानमंडल में दिए गए भाषण को

किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक कृत्यों जैसे अन्य कृत्यों को सदन की सीमा के भीतर होने के बावजूद अभियोजन के अधीन किया जा सकता है। अनुच्छेद 105 का खंड (2) "किसी भी चीज के संबंध में" कहा गया या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इस प्रतिरक्षा की सीमा का परीक्षण ऊपर निर्धारित परीक्षणों की कसौटी पर किया जाना चाहिए। किसी सदस्य की बोलने की क्षमता अनिवार्य रूप से सभा के सामूहिक कार्यकरण से जुड़ी होती है और सभा के कार्यकरण के लिए आवश्यक होती है। एक वोट, जो भाषण का विस्तार है, खुद को न तो सवाल किया जा सकता है और न ही कानून की अदालत में आगे बढ़ाया जा सकता है। वाक्यांश "के संबंध में" अनुच्छेद 105 के खंड (2) के तहत दी गई प्रतिरक्षा के दायरे को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

100. पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) का मामला बहुमत का निर्णय वाक्यांश "के संबंध में" की व्याख्या एक व्यापक अर्थ के रूप में करता है और किसी भी चीज का जिक्र करता है जो दिए गए वोट या दिए गए भाषण के साथ सांठगांठ या संबंध रखता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि संसद के सदस्य के वोट खरीदने के लिए दी गई रिश्वत अनुच्छेद 105 के खंड (2) के तहत अभियोजन से प्रतिरक्षा थी। इस तर्क से, बहुमत के फैसले ने निष्कर्ष निकाला कि एक रिश्वत स्वीकार करने वाला सदस्य जिसने अनुपालन नहीं किया क्विड प्रो क्वो अभियोजन पक्ष से प्रतिरक्षा नहीं थी क्योंकि उनके कार्यों का उनके वोट के साथ संबंध नहीं था। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, एक वाक्यांश की व्याख्या जो एक प्रावधान में प्रकट होती है, उसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो प्रावधान के उद्देश्य के लिए हिंसा करता है। बहुमत ने पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले में अनुच्छेद 105 का उद्देश्य यह लिया है कि संसद के सदस्यों को सदन में अपना कार्य करने में सक्षम होने के लिए कानून के तहत व्यापक संरक्षण होना चाहिए। प्रावधान की यह समझ व्यापक है और सदन के सदस्यों के बेहतर कामकाज में अनुवाद करने वाले बढ़े हुए विशेषाधिकारों की परिकल्पना की गई है।

101. सरकार के संसदीय रूप में विशेषाधिकार अपने आप में एक अंत नहीं है जैसा कि बहुमत ने उन्हें समझा है। संसद या विधानमंडल का एक सदस्य सदन या उसकी एक समिति में अपने कार्यों के प्रदर्शन में मुकदमा चलाने से प्रतिरक्षा है क्योंकि दिया गया भाषण या वोट डाला गया कार्यात्मक रूप से विधायिका के सदस्यों के रूप में उनके प्रदर्शन से संबंधित है। इस प्रतिरक्षा के लिए एक सदस्य का सदन या समिति के कामकाज के साथ इसका महत्वपूर्ण संबंध है। संसद में बोलने और मतदान की स्वतंत्रता की गारंटी देने का

कारण यह है कि इसके बिना संसद या विधायिका कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए, किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार की सीमा को इस निर्णय के भाग एफ में निर्धारित दो गुना परीक्षण को पूरा करना चाहिए, अर्थात् सदन के सामूहिक कामकाज और इसकी आवश्यकता के लिए इसका संबंध।

102. अनुच्छेद 105 के खंड (2) में "के संबंध में" शब्द "कुछ भी कहा या दिया गया कोई वोट" वाक्यांश पर और बाद के भाग में सदन द्वारा या उसके प्राधिकार से प्रकाशन पर लागू होते हैं। हम "कुछ भी" या "कोई" शब्दों की व्याख्या उस ऑपरेटिव शब्द को पढ़े बिना नहीं कर सकते हैं जिस पर यह लागू होता है यानी क्रमशः "कहा" और "वोट दिया गया"। शब्द "कुछ भी कहा" और "दिया गया कोई भी वोट" उस कार्रवाई पर लागू होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिसे सदन या उसकी समिति में बोलने या वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि किसी सदस्य या व्यक्ति ने बोलने के अपने अधिकार का प्रयोग किया होगा या अवसर आने पर सदन या समिति के अंदर बोलने से परहेज किया होगा। इसी तरह, किसी व्यक्ति या सदस्य को अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के तहत प्रतिरक्षा का दावा करने के लिए पक्ष में, खिलाफ या अनुपस्थित रहने के अपने विकल्प का प्रयोग करना चाहिए।

103. शब्द "कुछ भी" और "कोई भी" जब उनके संबंधित ऑपरेटिव शब्दों के साथ पढ़ा जाता है तो इसका अर्थ है कि एक सदस्य सदन के समक्ष किसी भी मामले पर अपनी इच्छानुसार कहने और मतदान करने के लिए प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है। ये न्यायालयों के हस्तक्षेप के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं। उनके साथी शब्दों के साथ पढ़े गए "कुछ भी" और "किसी भी" का व्यापक अर्थ सदन या समिति के अंदर भाषण या मतदान के कार्यों को दर्शाता है जो निरपेक्ष हैं। वाक्यांश "के संबंध में" सामूहिक वाक्यांश "कुछ भी कहा या दिया गया कोई वोट" पर लागू होता है। "के संबंध में" शब्द का अर्थ है स्पष्ट संबंध से उत्पन्न या असर करना। यह अतिव्यापी नहीं हो सकता है या इसका अर्थ किसी भी चीज़ से नहीं लगाया जा सकता है जिसका भाषण या वोट के साथ दूरस्थ संबंध भी हो सकता है। इसलिए, हम में बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं हो सकते। पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त)।

2. संविधान में सार्वजनिक जीवन में शुचिता की परिकल्पना की गई है

104. संविधान में संसद में जिस उद्देश्य और उद्देश्य के लिए शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति निर्धारित की गई है, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। विशेषाधिकार अनिवार्य रूप से सामूहिक रूप से सदन से संबंधित हैं और इसके कामकाज के लिए आवश्यक हैं। इसलिए,

वाक्यांश "के संबंध में" विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा के उद्देश्य के अनुरूप अर्थ होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 एक भयमुक्त वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के भीतर बहस, विचार-विमर्श और विचारों का आदान-प्रदान हो सकता है। इस प्रक्रिया के सार्थक होने के लिए, जिन सदस्यों और व्यक्तियों को सदन या किसी समिति के समक्ष बोलने का अधिकार है, उन्हें किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रेरित भय या पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। विधायिका के सदस्यों और विधायिका की समितियों के काम में शामिल व्यक्तियों को सदन के कार्यों को समृद्ध करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा और विवेक का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यह वही है जो तब छीन लिया जाता है जब किसी सदस्य को किसी मुद्दे पर उनके विश्वास या स्थिति के कारण नहीं बल्कि सदस्य द्वारा ली गई रिश्वत के कारण एक निश्चित तरीके से मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को नष्ट कर देती है। यह संविधान के आकांक्षात्मक और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी है और एक ऐसी राजनीति का निर्माण करता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करती है।

105. अल्पसंख्यक निर्णय - पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) में माना कि "के संबंध में" शब्दों को "से उत्पन्न" के रूप में समझा जाना चाहिए और सदन के किसी सदस्य द्वारा ली गई रिश्वत को उसके वोट से उत्पन्न नहीं माना जा सकता है। अल्पसंख्यक मत ने कहा कि:

“46. [...] अतः अनुच्छेद 105(2) में "के संबंध में" अभिव्यक्ति का अर्थ अनुच्छेद 105(2) के उद्देश्य और उस उपबंध में अभिव्यक्ति के प्रकट होने के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए।

47.अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रदत्त प्रतिरक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत विधायकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। संविधान में अपनाई गई संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली के स्वस्थ संचालन के लिए ऐसी स्वतंत्रता आवश्यक है। संसदीय लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 105 (2) के प्रावधानों की एक व्याख्या जो संसद के एक सदस्य को उसके द्वारा कही गई किसी बात या संसद या किसी समिति में उसके द्वारा दिए गए वोट के संबंध में रिश्वत के अपराध के लिए आपराधिक अदालत में अभियोजन से प्रतिरक्षा का दावा करने में सक्षम बनाएगी और इस तरह ऐसे सदस्यों को कानून से ऊपर रखेगी यह न केवल संसदीय लोकतंत्र के स्वस्थ कार्यकरण के प्रतिकूल होगा बल्कि विधि के शासन के प्रतिकूल भी होगा जो संविधान के मूल ढांचे का अनिवार्य अंग भी है। यह स्थापित कानून है

कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय अदालत को एक ऐसे निर्माण को अपनाना चाहिए जो संविधान की मूलभूत विशेषताओं और मूल संरचना को मजबूत करता है। (देखें: न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति बनाम भारत संघ [(1991) 4 एससीसी 699] एससीसी पृष्ठ 719 पर। [...]"

(महत्त्व दिया गया)

106. अल्पसंख्यक तब विरोधाभासी परिणाम बताते हैं जो तब उभरेगा जब सदस्यों को उनके भाषण या वोट के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा दी गई थी, लेकिन अगर रिश्वत नहीं बोलने या मतदान न करने के लिए प्राप्त की गई थी तो उन्हें संरक्षित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक यह मानते हैं कि:

" 47. [...] ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति से बचा जा सकता है यदि अनुच्छेद 105(2) में "के संबंध में" शब्दों का अर्थ "से उत्पन्न" है। यदि अभिव्यक्ति "के संबंध में" इस प्रकार लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 105 (2) के तहत प्रदत्त प्रतिरक्षा उस दायित्व तक सीमित होगी जो संसद या किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा दिए गए किसी वोट से उत्पन्न होती है या उसके कारण होती है। प्रतिरक्षा केवल तभी उपलब्ध होगी जब जो भाषण दिया गया है या जो वोट दिया गया है वह दायित्व को जन्म देने वाली कार्यवाही के लिए कार्रवाई के कारण का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है। उन्मुक्ति किसी ऐसे कार्य के लिए दायित्व के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो संसद में किसी सदस्य द्वारा भाषण देने या मत देने से पहले होता है, भले ही इसका सदस्य द्वारा दिए गए भाषण या मत से संबंध हो सकता है यदि ऐसा कार्य एक दायित्व को जन्म देता है जो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है और भाषण देने या वोट देने पर निर्भर नहीं करता है सदस्य द्वारा संसद में। इस तरह के स्वतंत्र दायित्व को संसद में सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या वोट के संबंध में दायित्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद 105 (2) के तहत जिस दायित्व के लिए प्रतिरक्षा का दावा किया जा सकता है, वह दायित्व है जो संसद में दिए गए भाषण या वोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है।

107. रिश्वत का अपराध धन की स्वीकृति पर या धन स्वीकार करने के समझौते पर समाप्त हो गया है। अपराध उस वादे के प्रदर्शन पर आकस्मिक नहीं है जिसके लिए पैसा दिया गया है या दिए जाने के लिए सहमत है। अल्पसंख्यक राय पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) मामले में अपने दृष्टिकोण को एक अन्य परिप्रेक्ष्य पर आधारित किया जिस पर बहुमत द्वारा विचार नहीं किया गया था। अल्पसंख्यक राय ने कहा कि रिश्वत का कार्य

सदन के अंदर भाषण या वोट देने से पहले अवैध परितोषण की प्राप्ति थी। वाक्यांश "के संबंध में" का अर्थ "से उत्पन्न" के अर्थ में व्याख्या करते हुए, अल्पसंख्यक ने निष्कर्ष निकाला कि रिश्वत का अपराध अवैध वादे के प्रदर्शन पर आकस्मिक नहीं है। अल्पसंख्यक ने देखा कि:

"50. ...अनुच्छेद 105(2) में अभिव्यक्ति से यह प्रश्न उठता है क्या सभा के समक्ष विचाराधीन किसी मामले पर संसद में किसी विशेष रीति से बोलने या अपना मत देने के प्रयोजन के लिए संसद सदस्य द्वारा रिश्वत स्वीकार करने से उत्पन्न अभियोजित होने वाला दायित्व एक स्वतंत्र दायित्व है जिसे संसद में सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत से उत्पन्न नहीं कहा जा सकता है? हमारी राय में, इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाना चाहिए। रिश्वतखोरी का अपराध रिसीवर के खिलाफ बनाया जाता है यदि वह एक निश्चित तरीके से कार्य करने के वादे के लिए पैसे लेता है या लेने के लिए सहमत होता है। अपराध धन की स्वीकृति के साथ या संपन्न किए जा रहे धन को स्वीकार करने के समझौते पर पूरा हो गया है और रिसीवर द्वारा अवैध वादे के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। धन प्राप्त करने वाले को अवैध सौदेबाजी में चूक करने पर भी अपराध करने वाला माना जाएगा। रिश्वतखोरी के अपराध को साबित करने के लिए जो कुछ भी स्थापित किया जाना आवश्यक है वह यह है कि अपराधी ने एक निश्चित तरीके से कार्य करने के वादे के लिए धन प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमत है और आगे जाकर यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि उसने वास्तव में उस तरह से काम किया है।

108. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने किहोटो होलोहान बनाम ज़चिल्हू ,[57] संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की वैधता पर निर्णय लेते समय, जिसने संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की दसवीं अनुसूची को पुर्नस्थापित किया। भारतीय संविधान ने कहा कि अनुच्छेद 105 के खंड (2) के तहत संसद में भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाता है। इस न्यायालय ने प्रावधान को आवश्यक रूप से समझा कि फ्लोर क्रॉसिंग का राजनीतिक रूप से पापी कार्य न तो स्वीकार्य है और न ही संविधान के तहत प्रतिरक्षित है। इस न्यायालय ने कहा कि:

"40. किसी सदस्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इसके अलावा, दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का अभिप्राय किसी सदन के सदस्य को संसद में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी बनाना नहीं है। यह

कल्पना करना मुश्किल है कि अनुच्छेद 105 (2) कैसे सिद्धांतहीन फ्लोर-क्रॉसिंग के परिणामों से प्रतिरक्षा का एक स्रोत है।

43. संसदीय लोकतंत्र में यह परिकल्पना की गई है कि सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन से जुड़े मामलों पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए, बहस, चर्चा और अनुनय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साधन और सार हैं। वाद-विवाद के दौरान सदस्यों ने विभिन्न दृष्टिकोण रखे। एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों के बीच भी किसी मामले पर मतभेद हो सकते हैं और वे इसे व्यक्त कर सकते हैं। सभा में सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के परिणामस्वरूप विचाराधीन प्रस्तावों में पर्याप्त संशोधन और यहां तक कि उन्हें वापस लेना भी पड़ा है। इस प्रकार, विभिन्न दृष्टिकोणों की बहस और अभिव्यक्ति संसदीय लोकतंत्र के कामकाज में एक आवश्यक और स्वस्थ उद्देश्य की पूर्ति करती है। कभी-कभी सदन में बहस के दौरान विचारों की ऐसी अभिव्यक्ति से सदन में मतदान या मतदान से परहेज हो सकता है, अन्यथा पार्टी लाइनों पर।

3. न्यायालय और सदन समानांतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं रिश्वतखोरी का आरोप

109. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने तर्क दिया है कि सदन द्वारा रिश्वत को विशेषाधिकार हनन के रूप में माना गया है, जिसने रिश्वत लेने वाले सदस्यों पर अनुशासन देने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। उनका तर्क है कि संसद के सदन में मतदान, भाषण या आचरण के लिए प्रतिरक्षा किसी भी तरह से दोषी सदस्यों को निर्दोष या मंजूरी से मुक्त नहीं छोड़ती है। ऐसे सदस्यों को सदन से निष्कासित करने सहित दंडित किया गया है। रामचंद्रन ने सदन द्वारा अपने सदस्यों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के कई उदाहरण दिए, जिन्हें रिश्वत मिली थी। भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के इतिहास की व्याख्या करते हुए हमने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा शुरू में रिश्वत को विशेषाधिकार हनन माना गया था। ब्रिटेन में कानून की स्थिति के आधार पर, ब्रिटिश सरकार भारत में स्थिति के बारे में अनिश्चित थी, लेकिन एक स्पष्ट वैधानिक अधिनियमन के अभाव में इसे विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले के रूप में शासित माना जाता था। 1924 में सुधार जांच समिति की रिपोर्ट ने रिश्वत को दंडनीय अपराध बनाने की सिफारिश की थी ताकि सदस्यों पर कानून की अदालत के समक्ष अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सके।

110. घूसखोरी का मुद्दा सभा द्वारा अपने रिश्वत लेने वाले सदस्यों के क्षेत्राधिकार की विशिष्टता में से एक नहीं है। रिश्वत प्राप्त करने के लिए एक सदस्य द्वारा अवमानना के

खिलाफ कार्य करने वाले सदन का उद्देश्य एक आपराधिक अभियोजन से अलग उद्देश्य को पूरा करता है। सदन द्वारा संचालित की जाने वाली कार्यवाही का उद्देश्य इसकी गरिमा को बहाल करना है। इस तरह की कार्यवाही के परिणामस्वरूप सदन की सदस्यता से निष्कासन और अन्य परिणाम हो सकते हैं जो कानून की परिकल्पना करते हैं। एक अपराध के लिए अभियोजन एक आपराधिक क़ानून के उल्लंघन से जुड़े एक अलग क्षेत्र में संचालित होता है। आपराधिक गलत काम के लिए दंडित करने की शक्ति आपराधिक कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य की शक्ति से निकलती है। उत्तरार्द्ध भूमि के आपराधिक कानून के प्रतिबंधों के अधीन सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। दोनों न्यायालयों का उद्देश्य, परिणाम और प्रभाव अलग-अलग हैं। एक आपराधिक मुकदमा सदन की अवमानना से अलग है क्योंकि यह पूरी तरह से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, साक्ष्य के नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ तैयार किया गया है।

111. इसलिए हम श्री रामचंद्रन से असहमत हैं कि सदन के अधिकार क्षेत्र में देश के आपराधिक कानून के तहत अपराध चलाने के लिए आपराधिक अदालत को शामिल नहीं किया गया है। हम इसे ऊपर हमारे निष्कर्ष के कारण मानते हैं कि अनुच्छेद 105 के खंड (2) के तहत रिश्वत प्रतिरक्षा नहीं है। रिश्वत में संलग्न एक सदस्य एक अपराध करता है जो मतदान करने या उनके वोट पर निर्णय लेने की उनकी क्षमता से संबंधित नहीं है। यह कार्रवाई संसद या विधानमंडल के सदन में अपमान ला सकती है और अभियोजन को भी आकर्षित कर सकती है। यह जो आकर्षित नहीं करता है वह संसद या विधानमंडल के सदस्य के आवश्यक और आवश्यक कार्यों के लिए दी गई प्रतिरक्षा है।

112. हम एससी अग्रवाल, न्यायमूर्ति की राय का उल्लेख कर सकते हैं जो उसी दृष्टिकोण पर पहुंचे जिसमें वह अल्पमत में थे:

“ 45. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस सदस्य को संसद के कार्य के संबंध में रिश्वत स्वीकार करते हुए पाया जाता है, उसे अवमानना के लिए सभा द्वारा दंडित किया जा सकता है। लेकिन यह संतोषजनक समाधान नहीं है। अवमानना के लिए दंडित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, हाउस ऑफ कॉमन्स किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है और सदन की सेवा से निष्कासन या निलंबन का आदेश भी दे सकता है। जुर्माना लगाने की शक्ति नहीं है। प्रतिबद्ध की शक्ति सत्र की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है और व्यक्ति, यदि सदन द्वारा जल्द ही छुट्टी नहीं दी जाती है, तो तुरंत सत्रावसान पर कारावास से मुक्त हो जाता है। (देखें: मई की संसदीय प्रथा , 21 वां संस्करण, पीपी 103, 109 और

111) भारत में संसद के सदन उच्च शक्ति का दावा नहीं कर सकते। सैल्मन आयोग ने कहा है कि "जबकि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की सदन की सैद्धांतिक शक्ति निस्संदेह मौजूद है, कोई भी सौ साल या उससे भी अधिक समय तक संसद की अवमानना के लिए जेल में नहीं गया है, और यह सबसे अधिक संभावना नहीं है कि संसद आधुनिक परिस्थितियों में इस शक्ति का उपयोग करेगी"। (पैरा 306) सैल्मन आयोग ने यह भी विचार व्यक्त किया है कि इस प्रकार की जांच के लिए आवश्यक विशेष विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, विशेषाधिकार समिति पुलिस जांच की तुलना में एक जांच तंत्र प्रदान नहीं करती है।" (महत्त्व दिया गया है)

113. इसलिए, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 105 का खंड (2) किसी भी व्यक्ति को रिश्वत के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है क्योंकि अवैध परितोषण प्राप्त करने के लिए रसीद या समझौता सदन में बोलने या मतदान करने के लिए सदस्य के कार्य के संबंध में नहीं है। रिश्वतखोरी के लिए अभियोजन को आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से केवल इसलिए बाहर नहीं रखा गया है क्योंकि इसे सदन द्वारा अवमानना या इसके विशेषाधिकार का उल्लंघन भी माना जा सकता है।

4. परिणाम प्रदान करना रिश्वतखोरी के अपराध के लिए अप्रासंगिक है

114. एक अन्य पहलू जो विचार के लिए उठता है वह वह चरण है जिस पर रिश्वत का अपराध क्रिस्टलीकृत होता है। सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह आग्रह किया गया है कि अपराध विधायिका के बाहर पूरा हो गया है और भाषण या वोट से 'स्वतंत्र' है। इसलिए, विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता और इस प्रश्न का उत्तर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के उपबंधों द्वारा दिया जाता है। इसी तरह, श्री गोपाल शंकरनारायण, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि रिश्वत का अपराध वोट दिए जाने या संसद में दिए गए भाषण से पहले रिश्वत प्राप्त करने पर पूरा हो गया है। यह आग्रह किया गया है कि वादे का प्रदर्शन अपराध के लिए अप्रासंगिक है, और इसलिए, पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) का मामला में किया गया भेद पूरी तरह से कृत्रिम है।

115. दिलचस्प बात यह है कि बहुमत का फैसले ने पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले में इस सवाल पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। दूसरी ओर, अल्पमत निर्णय इस पहलू पर चर्चा करता है और नोट करता है कि अपराध धन की स्वीकृति के साथ या संपन्न किए जा रहे धन को स्वीकार करने के समझौते पर पूरा हो गया है और रिसीवर द्वारा अवैध वादे के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। अग्रवाल, न्यायमूर्ति ने देखा:

“50. अनुच्छेद 105(2) में "के संबंध में" अभिव्यक्ति पर हमारे द्वारा रखा गया निर्माण प्रश्न उठाता है: क्या संसद के सदस्य द्वारा सभा के समक्ष विचाराधीन किसी मामले पर संसद में किसी विशेष रीति से बोलने या अपना मत देने के प्रयोजन से अभियोजित अभियोजन, एक स्वतंत्र दायित्व है जिसे किसी कही गई बात या द्वारा दिए गए किसी मत से उत्पन्न नहीं कहा जा सकता है संसद में सदस्य? हमारी राय में, इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाना चाहिए। रिश्वतखोरी का अपराध रिसीवर के खिलाफ बनाया जाता है यदि वह एक निश्चित तरीके से कार्य करने के वादे के लिए पैसे लेता है या लेने के लिए सहमत होता है। अपराध धन की स्वीकृति के साथ या संपन्न किए जा रहे धन को स्वीकार करने के समझौते पर पूरा हो गया है और रिसीवर द्वारा अवैध वादे के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। धन प्राप्त करने वाले को अवैध सौदेबाजी में चूक करने पर भी अपराध करने वाला माना जाएगा। रिश्वतखोरी के अपराध को साबित करने के लिए जो कुछ भी स्थापित किया जाना आवश्यक है वह यह है कि अपराधी ने एक निश्चित तरीके से कार्य करने के वादे के लिए धन प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमत है और आगे जाकर यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि उसने वास्तव में उस तरह से काम किया है। ”

(महत्त्व दिया गया)

116. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 इस प्रकार है:

"7. लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध। – कोई भी लोक सेवक जो, -

(क). प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है किसी भी व्यक्ति से, एक अनुचित लाभ, के साथ प्रदर्शन करने का इरादा या सार्वजनिक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से पालन करना या स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिए सहनशीलता या कारित करना; नहीं तो

(ख). किसी व्यक्ति से किसी लोक कर्तव्य के अनुचित या बेईमानी से किए गए प्रदर्शन के लिए पुरस्कार के रूप में या स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा ऐसे कर्तव्य का पालन करने के लिए सहनशील होने के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है; नहीं तो

(ग). किसी अन्य लोक सेवक को अनुचित रूप से या बेईमानी से सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने या किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ स्वीकार करने की प्रत्याशा में या उसके परिणामस्वरूप ऐसे कर्तव्य के पालन को रोकने के लिए करता है या प्रेरित करता है, वह

कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1. – इस धारा के प्रयोजन के लिए, अनुचित लाभ प्राप्त करना, स्वीकार करना या प्राप्त करने का प्रयास स्वयं एक अपराध का गठन करेगा, भले ही लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य का प्रदर्शन अनुचित नहीं है या नहीं है।

उदाहरण। – लोक सेवक, क एक व्यक्ति ख से अपने राशन कार्ड आवेदन को समय पर संसाधित करने के लिए पांच हजार रुपए की राशि देने के लिए कहता है। 'ध' इस धारा के तहत अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण 2.- इस खंड के प्रयोजन के लिए, -

(i). अभिव्यक्ति "प्राप्त करता है" या "स्वीकार करता है" या "प्राप्त करने का प्रयास" उन मामलों को कवर करेगा जहां एक लोक सेवक होने के नाते, एक व्यक्ति लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके या किसी अन्य लोक सेवक पर अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ प्राप्त करता है या "स्वीकार करता है" या प्राप्त करने का प्रयास करता है; या किसी अन्य भ्रष्ट या अवैध तरीके से;

(ii). इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोक सेवक होने के नाते ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(महत्त्व दिया गया)

117. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत, अपराध को पूरा करने के लिए केवल "प्राप्त करना", "स्वीकार करना" या एक निश्चित तरीके से कार्य करने से रोकने के इरादे से अनुचित लाभ प्राप्त करने का "प्रयास" करना पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य के लिए रिश्वत दी गई है, वह वास्तव में किया जाए। प्रावधान की पहली व्याख्या इस तरह की व्याख्या को और मजबूत करती है जब यह स्पष्ट रूप से कहती है कि अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए "प्राप्त करना, स्वीकार करना या प्रयास करना" स्वयं एक अपराध का गठन करेगा, भले ही किसी लोक सेवक द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य का प्रदर्शन अनुचित न हो। इसलिए, एक लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने का अपराध अनुचित लाभ प्राप्त करने या

प्राप्त करने के लिए सहमत होने के लिए आंका गया है और उस अधिनियम का वास्तविक प्रदर्शन नहीं जिसके लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया जाता है।

118. यह ट्राइट लॉ है कि एक खंड में संलग्न उदाहरण एक वैधानिक प्रावधान के पाठ के निर्माण में मूल्य और प्रासंगिकता के हैं और उन्हें धारा के प्रतिकूल के रूप में आसानी से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।[58] पहले स्पष्टीकरण का दृष्टांत हमें प्रावधान का अर्थ यह निकालने में सहायता करता है कि रिश्वत का अपराध रिश्वत के आदान-प्रदान पर क्रिस्टलीकृत होता है और अधिनियम के वास्तविक प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जहां "एक लोक सेवक, 'क' एक व्यक्ति, 'ख' से उसे अपने नियमित राशन कार्ड आवेदन को समय पर संसाधित करने के लिए पांच हजार रुपये की राशि देने के लिए कहता है। क 'इस धारा के तहत एक अपराध का दोषी है। यह स्पष्ट है कि इस बात की परवाह किए बिना कि क वास्तव में राशन कार्ड आवेदन को समय पर संसाधित करता है, रिश्वत का अपराध बनता है। इसी तरह रिश्वत लेने वाले विधायक के फॉर्मूले में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सहमत दिशा में वोट देता है या वोट देता ही है। जिस समय वह रिश्वत स्वीकार करती है, उस समय रिश्वतखोरी का अपराध पूरा हो जाता है।

119. 2017 में पीसी अधिनियम में संशोधन से पहले भी, धारा 7 ने वास्तविक प्रदर्शन से रिश्वत के अपराध को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया था उस अधिनियम का जिसके लिए अनुचित लाभ प्राप्त होता है। प्रावधान इस प्रकार है:

"7. किसी शासकीय कार्य के संबंध में विधिक पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लेने वाला लोक सेवक जो कोई लोक सेवक होने की अपेक्षा करता है या किसी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण किसी शासकीय कार्य को करने या दिखाने या दिखाने के लिए दिखाने या सहनशील करने के प्रयोजन या पुरस्कार के रूप में स्वीकार करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, अपने आधिकारिक कार्यों के प्रयोग में, किसी भी व्यक्ति के पक्ष या अपमान या किसी भी व्यक्ति को कोई सेवा या असेवा प्रदान करने या प्रदान करने का प्रयास करने के लिए, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल के साथ या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सरकारी कंपनी के साथ धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट है, या किसी लोक सेवक के साथ, चाहे वह नामजद हो या

अन्यथा, कारावास से, दंडनीय होगा जो छह माह से कम नहीं होगा किंतु जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण। –

(घ) "करने का उद्देश्य या पुरस्कार। एक व्यक्ति जो ऐसा करने के लिए एक मकसद या इनाम के रूप में एक संतुष्टि प्राप्त करता है जो वह करने का इरादा नहीं रखता है या करने की स्थिति में नहीं है, या नहीं किया है, इस अभिव्यक्ति के भीतर आता है .

(महत्त्व दिया गया)

120. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 का असंशोधित पाठ यह भी इंगित करता है कि अवैध परितोषण को "स्वीकार करने", "प्राप्त करने", "स्वीकार करने के लिए सहमत" या "प्राप्त करने के लिए सहमत" करने का कार्य एक पर्याप्त शर्त है। जिस कार्य के लिए रिश्वत दी जाती है, उसे वास्तव में करने की आवश्यकता नहीं है। इसे प्रावधान के स्पष्टीकरण (घ) द्वारा आगे स्पष्ट किया गया था। 'करने के लिए एक मकसद या इनाम' वाक्यांश की व्याख्या करते हुए, यह स्पष्ट किया गया था कि परितोषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस कार्य या चूक को करने या न करने का इरादा रखने या न करने की आवश्यकता नहीं है जिसके लिए मकसद / इनाम प्राप्त हुआ है।

121. भगवानदास पटेल बनाम गुजरात राज्य[59] इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया कि रिश्वतखोरी के अपराध का गठन करने के लिए, एक लोक सेवक अवैध परितोषण निकालने के लिए अपने आधिकारिक पद का उपयोग करना एक पर्याप्त शर्त है। ऐसे मामले में न्यायालय के लिए यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या लोक सेवक वास्तव में पक्ष या पक्षपात का कोई आधिकारिक कार्य करने का इरादा रखता है। मामले के तथ्यों में, लोक सेवक ने शिकायतकर्ता को अपहरण के आरोप से छुटकारा पाने के लिए रिश्वत देने के लिए प्रेरित किया। बाद में यह पता चला कि कथित अपहरण के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की गई थी। हालांकि, न्यायालय ने माना कि अवैध परितोषण की मात्र मांग और स्वीकृति पर्याप्त थी, भले ही रिश्वत प्राप्त करने वाले ने वह कार्य किया हो जिसके लिए रिश्वत प्राप्त हुई थी।

122. हाल ही में, में नीरज दत्ता बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)[60] एक संविधान पीठ ने भ्रस्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत रिश्वत के अपराध के घटक तत्वों को

सूचीबद्ध किया (जैसा कि यह 2017 में संशोधन से पहले था)। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने अपराध का गठन करने के लिए तत्वों को तैयार किया:

"5. अधिनियम की धारा 7 के तत्व निम्नलिखित हैं:

1. अभियुक्त को लोक सेवक होना चाहिए या लोक सेवक होने की अपेक्षा करनी चाहिए;

2. उसे किसी भी व्यक्ति से स्वीकार या प्राप्त करना चाहिए या स्वीकार करने के लिए सहमत होना चाहिए या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए;

3. खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए;

4. कानूनी पारिश्रमिक के अलावा कोई भी संतुष्टि; और

5. किसी सरकारी कार्य को करने या करने के लिए या कोई एहसान या पक्षपात दिखाने के लिए एक मकसद या इनाम के रूप में।

नतीजतन, आधिकारिक कार्य वास्तविक "करने या करने के लिए सहनशील" है नहीं अपराध का एक घटक हिस्सा। केवल इस बात की आवश्यकता है कि अवैध परितोषण को इस तरह के कार्य या चूक के लिए "मकसद या इनाम" के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए - चाहे वह वास्तव में किया गया हो या नहीं, अप्रासंगिक है।

123. सुनवाई के दौरान इस संबंध में एक काल्पनिक सवाल उठा। ऐसी स्थिति में क्या होता है जब विधायिका के परिसर के भीतर रिश्वत का आदान-प्रदान किया जाता है? क्या अब यह अपराध संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में आएगा? यह प्रश्न गलत प्रतीत होता है। जब यह न्यायालय मानता है कि रिश्वत का अपराध अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने के प्रयास पर पूरा हो गया है और भाषण या वोट पर निर्भर नहीं है, तो यह स्वचालित रूप से अपराध को अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के दायरे से बाहर कर देता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अनुचित लाभ की स्वीकृति विधायिका के बाहर हुई, बल्कि इसलिए कि अपराध अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) द्वारा संरक्षित "वोट या भाषण" से स्वतंत्र है। संसदीय विशेषाधिकार का परिप्रेषण अधिनियम के 'वोट' या 'भाषण' और संसदीय कार्य के संचालन से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है।

124. बहुमत का फैसला - पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले में इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि रिश्वत का अपराध कब पूरा होता है या अपराध के घटक तत्व क्या हैं। हालांकि, मामले के तथ्यों पर, बहुमत ने माना कि जिन सांसदों ने सहमति के अनुसार

मतदान किया, वे प्रतिरक्षा द्वारा कवर किए गए थे, जबकि जिन लोगों ने मतदान नहीं किया था (अजीत सिंह) अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के तहत प्रतिरक्षा द्वारा कवर नहीं किए गए थे। यह गलती से रिश्वत के अपराध को अधिनियम के प्रदर्शन से जोड़ता है। वास्तव में, आक्षेपित निर्णय में भी, उच्च न्यायालय ने इस स्थिति पर भरोसा किया है कि अपीलकर्ता प्रतिरक्षा द्वारा कवर नहीं किया गया है क्योंकि उसने अंततः सहमति के अनुसार मतदान नहीं किया और अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया।

125. बहुमत के फैसले में कानून की समझ - पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) उन लोगों के बीच एक कृत्रिम अंतर बनाता है जो अवैध संतुष्टि प्राप्त करते हैं और सौदेबाजी का अपना अंत करते हैं और जो समान अवैध संतुष्टि प्राप्त करते हैं लेकिन सहमत कार्य को पूरा नहीं करते हैं। रिश्वत का अपराध सहमत कार्रवाई के प्रदर्शन के लिए अज्ञेयवादी है और अवैध परितोषण के आदान-प्रदान के आधार पर क्रिस्टलीकृत होता है। अल्पसंख्यक निर्णय ने भी प्रकाश डाला प्रत्यक्षतः बहुमत के फैसले से पैदा हुए विरोधाभास में बेरुखी। अग्रवाल, जन्यायमूर्ति ने देखा कि:

“47. […] यदि श्री राव द्वारा "के संबंध में" अभिव्यक्ति पर रखी गई संरचना को अपनाया जाता है, तो एक सदस्य पर रिश्वतखोरी के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है यदि वह सदन के समक्ष विचाराधीन मामले पर नहीं बोलने या अपना वोट नहीं देने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है, लेकिन यदि वह किसी विशेष में संसद में बोलने या अपना वोट देने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है तो उसे इस तरह के आरोप के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी वह संसद में इस तरीके से बोलता है या अपना मत देता है। यह कल्पना करना कठिन है कि संविधान निर्माताओं ने प्रतिरक्षा प्रदान करने के मामले में ऐसा भेद करने का इरादा किया था, जो संसद सदस्य के बीच प्रतिरक्षा प्रदान करने के मामले में ऐसा अंतर करना चाहता था, जो संसद में किसी विशेष तरीके से बोलने या अपना मत देने के लिए रिश्वत लेता है और उस तरीके से बोलता है या अपना मत देता है (ग) सरकार ने सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है और करार के अनुसार अपना मत नहीं दिया है ताकि पूर्व को रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान की जा सके लेकिन बाद वाले को ऐसी प्रतिरक्षा से वंचित किया जा सके। ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति से बचा जाएगा यदि अनुच्छेद 105 (2) में "के संबंध में" शब्दों का अर्थ "से उत्पन्न" […]" से उत्पन्न होने के अर्थ में लगाया जाता है। (महत्त्व दिया गया)

126. दरअसल, अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) को बहुमत के फैसले में प्रस्तावित तरीके से पढ़ने के लिए एक विरोधाभासी परिणाम होता है। इस तरह की व्याख्या के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति होती है जहां एक विधायक को प्रतिरक्षा के साथ पुरस्कृत किया जाता है जब वे रिश्वत स्वीकार करते हैं और सहमत दिशा में मतदान करके पालन करते हैं। दूसरी ओर, एक विधायक जो रिश्वत स्वीकार करने के लिए सहमत है, लेकिन अंततः स्वतंत्र रूप से मतदान करने का फैसला कर सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस तरह की व्याख्या न केवल अनुच्छेद 105 और 194 के पाठ को झुठलाती है, बल्कि विधायिका के सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करने के उद्देश्य को भी झुठलाती है।

(ज) विशेषाधिकारों की तुलना में रिश्वत पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

127. उपरोक्त व्याख्या में भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के विषय को नियंत्रित करने वाले कानून और रिश्वतखोरी में संलग्न विधायिका के सदस्य पर इसके निहितार्थ को स्पष्ट करने की मांग की गई है। भारत में संसदीय विशेषाधिकारों की स्थिति को रेखांकित करने से पहले अन्य न्यायालयों में कानून में तल्लीन करने के लिए भारत में इस विषय पर अधिकांश निर्णयों का सिद्धांत रहा है। भारत में संसदीय विशेषाधिकारों पर न्यायशास्त्र तब से अपने आप में विकसित हुआ है और हमने इस न्यायालय के समृद्ध न्यायशास्त्र और भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के इतिहास का उल्लेख किया है। हालांकि, बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों के फैसले के बाद से पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) ने विदेशी न्यायालयों में न्यायशास्त्र पर बहुत अधिक भरोसा किया है, विशेषाधिकारों पर कानून के विकास और स्थिति को संक्षेप में बताना उचित है क्योंकि यह अन्य न्यायालयों में संसद के सदस्य द्वारा प्राप्त रिश्वत के मुद्दे से संबंधित है। हम सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में कानून की स्थिति पर अपना ध्यान निर्देशित करेंगे और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का स्थान लेंगे।

1. <u>युनाइटेड किंगडम</u>

128. जैसा कि हमने ऊपर पता लगाया है, यूके में संसदीय विशेषाधिकारों पर कानून हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा ट्यूडर और स्टुअर्ट किंग्स के साथ संघर्ष के बाद विकसित किया गया था। में राजा बहुत। सर जॉन इलियट,[61]1629 में कॉमन्स और किंग के बीच टकराव के चरम पर, किंग्स बेंच ने हाउस ऑफ कॉमन्स के तीन सदस्यों, सर जॉन इलियट, डेनजेल हॉलिस और बेंजामिन वेलेंटाइन पर राजद्रोही भाषण देने, सार्वजनिक शांति भंग करने और सदन को स्थगित होने से रोकने के लिए स्पीकर को हिंसक रूप से अपनी स्थिति में रखने के लिए

मुकदमा चलाया। संसद के सदस्यों को दोषी पाया गया, जुर्माना लगाया गया और जेल में डाल दिया गया। सर जॉन इलियट को एक टॉवर में कैद करने के लिए भेजा गया था जहां उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और अंततः उनका निधन हो गया। मुकदमे की रिपोर्ट 1667 में प्रकाशित हुई और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा देखी गई। सदन ने संकल्प लिया कि निर्णय अवैध था और संसद के विशेषाधिकारों के खिलाफ था। डेनजेल हॉलिस द्वारा प्रस्तुत त्रुटि की एक रिट पर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किंग्स बेंच के फैसले को उलट दिया।

129. 1688 की गौरवशाली क्रांति के साथ, स्टुअर्ट किंग्स, जेम्स के अंतिम को निष्कासित कर दिया गया था और एक नया राजवंश स्थापित किया गया था। कड़वे संघर्ष ने हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ एक दृढ़ता से स्थापित संवैधानिक राजतंत्र का नेतृत्व किया, अंततः संप्रभुता और कुछ विशेषाधिकारों दोनों का दावा किया जो सदन की दृढ़ता और इसकी क्रमिक मान्यता के परिणामस्वरूप प्राचीन और निस्संदेह हो गए। Erskine मई नोट करता है कि:

"प्रत्येक संसद के प्रारंभ में यह अध्यक्ष के लिए, नाम पर, और कॉमन्स की ओर से, अपने प्राचीन और निस्संदेह अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए विनम्र याचिका द्वारा दावा करने का रिवाज रहा है; विशेष रूप से बहस में भाषण की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, जब भी अवसर की आवश्यकता होगी, महामहिम तक पहुंच की स्वतंत्रता; और यह कि सबसे अनुकूल निर्माण उनकी सभी कार्यवाहियों पर रखा जाना चाहिए।[62]

130. संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभियोजन से प्रतिरक्षा को निर्धारित करने वाला खंड अधिकार विधेयक 1689 से प्रवाहित होता है। यह अधिनियम इंग्लैंड में संसद द्वारा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल थी ताकि इसे क़ानून में आधार बनाकर अपनी स्थिति का दावा किया जा सके। क़ानून संसद को अदालतों में या उसके माध्यम से शाही हस्तक्षेप से सुरक्षित करना था। बिल ऑफ राइट्स के अनुच्छेद IX में कहा गया है:

"संसद में भाषण और बहस या कार्यवाही की स्वतंत्रता पर महाभियोग नहीं लगाया जाना चाहिए या किसी भी अदालत या संसद के बाहर जगह पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

यह खंड संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इसे किसी भी अदालत या संसद के बाहर "महाभियोग या सवाल" से बचाता है।

131. बिल ऑफ राइट्स के अनुच्छेद IX के दो पहलुओं को शुरुआत में रेखांकित किया जा सकता है। सबसे पहले, यूके में अनुच्छेद IX के तहत विशेषाधिकार केवल व्यक्तिगत सदस्यों से जुड़ा नहीं है। यह संसद में भाषण और बहस या कार्यवाही की स्वतंत्रता का प्रतिरक्षण

करता है और यह निर्धारित करता है कि इसे 'महाभियोग या प्रश्न' नहीं किया जाएगा। दूसरे, अनुच्छेद IX में कहा गया है कि संसद में कार्यवाही केवल संसद में 'महाभियोग या प्रश्न' की जा सकती है। इससे इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या संसदीय कार्यवाही से कोई सामग्री न्यायालयों के समक्ष रखी जा सकती है और क्या संसद का अधिकार क्षेत्र न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर देता है। जैसा कि हम नीचे स्पष्ट करेंगे, जैसा कि यह स्थिति है, यूके में संसदीय कार्यवाही से सामग्री को न्यायालय के समक्ष रखने की अनुमति देता है, बशर्ते कि इसका उपयोग इसका अर्थ या बहस करने के लिए नहीं किया जाता है दुर्भावना कार्रवाई के पीछे। यूके में अदालतों ने गैर-विधायी गतिविधियों के लिए आवश्यक सांठगांठ के लिए एक संकीर्ण दायरे की व्याख्या भी की है। इससे यह धारणा बनी है कि रिश्वत लेने के लिए किसी सदस्य को अनुशासित करने का संसद का अधिकार क्षेत्र स्वचालित रूप से अदालतों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करेगा।

132. संसद में दिए गए भाषण के प्रति आकर्षित संसदीय प्रतिरक्षा किसके मामले में लागू की गई? एक्स पार्टे वासन,[63] जहां संसद के एक सदस्य पर एक बयान देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था जिसे वे जानते थे कि यह गलत है। एक व्यक्ति ने अर्ल रसेल को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष पेश करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें लॉर्ड चीफ बैरन पर एक संसदीय समिति के समक्ष जानबूझकर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था। इससे इस तरह के निष्कासन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा एक अभिभाषण पर लॉर्ड चीफ बैरन को हटा दिया गया होगा। अर्ल रसेल, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड चीफ बैरन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस आशय के भाषण देने की साजिश रची कि झूठ के आरोप निराधार थे, यह जानने के बावजूद कि आरोप सही थे। मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर आवेदक का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया कि संसद में दिया गया भाषण किसी भी अभियोग योग्य अपराध का खुलासा नहीं कर सकता है। महारानी की पीठ ने आदेश की पुष्टि की।

133. कॉकबर्न, मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा कि किसी भी सदन में दिए गए भाषण किसी तीसरे व्यक्ति के हितों को चोट पहुंचाने की परवाह किए बिना नागरिक या आपराधिक कार्यवाही को जन्म नहीं दे सकते हैं। राय के साथ सहमति लुश, न्यायमूर्ति ने कहा कि:

“[...] मेरा स्पष्ट मत है कि हमें एक क्षण के लिए भी यह संदेह नहीं होने देना चाहिए कि किसी भी सदन के सदस्यों के उद्देश्यों या इरादों की जांच सदन में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात के संबंध में आपराधिक कार्यवाही द्वारा नहीं की जा सकती।

इसलिए रानी की बेंच ने माना कि सदन के अंदर दिए गए भाषण को नागरिक या आपराधिक कार्रवाई में अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही में सवाल नहीं किया जा सकता है और न ही इस तरह के कृत्यों के प्रदर्शन के पीछे के उद्देश्यों पर सवाल उठाया जा सकता है।

134. रिश्वतखोरी का मुद्दा केवल 1889 तक सामान्य कानून द्वारा शासित था। विभिन्न सामान्य कानून अपराधों को विभिन्न कार्यालयों और उनके कार्यों द्वारा भ्रष्टाचार के आधार पर आकर्षित किया गया था। सार्वजनिक निकाय भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1889, जो केवल स्थानीय सरकारी निकायों पर लागू होता है, ने भ्रष्टाचार का पहला वैधानिक अपराध बनाया। इसके बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1906 ने भ्रष्टाचार के अपराध को निजी क्षेत्र तक बढ़ा दिया। इनमें से किसी भी क़ानून ने स्वीकृति को कवर नहीं किया। संसद के एक सदस्य द्वारा रिश्वत का आरोप। कानून के अभाव में, संसद सदस्य द्वारा रिश्वत लेने का सवाल विशेषाधिकार हनन का सवाल बना हुआ था और केवल सदन को इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार था।

135. लॉर्ड सैल्मन की अध्यक्षता में सार्वजनिक जीवन में आचरण के मानकों पर रॉयल कमीशन ने 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की गई है कि किसी सांसद के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और रिश्वतखोरी के प्रयास को आपराधिक कानून के दायरे में लाया जाए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए, लॉर्ड सैल्मन ने कहा:

उन्होंने कहा, 'मेरे विचार से कानून के समक्ष समानता स्वतंत्रता के स्तंभों में से एक है। यह कहना कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा जो संसद सदस्य को रिश्वत देने की कोशिश करता है और कोई भी संसद सदस्य जो रिश्वत स्वीकार करता है, अधिकारों के विधेयक से उपजा है, संभवतः एक गंभीर गलती है। अधिकारों के विधेयक में पारित किया गया है: "संसद में भाषण और बहस या कार्यवाही की स्वतंत्रता पर महाभियोग नहीं लगाया जाना चाहिए या किसी भी अदालत में या संसद के बाहर जगह पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। अब यह सभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चार्टर है। यह भ्रष्टाचार का चार्टर नहीं है। मेरे विचार से, अधिकारों का विधेयक, जिसके लिए मेरे मन में मुझसे अधिक सम्मान नहीं है, का उस विषय से अधिक कोई लेना-देना नहीं है जिस पर हम मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट से अधिक चर्चा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का अपराध तब पूरा होता है जब रिश्वत की पेशकश की जाती है या दी जाती है या मांगी जाती है और ली जाती है।

हमने सिफारिश की है कि भ्रष्टाचार से संबंधित सभी संविधियों को एक व्यापक संविधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो वर्तमान विसंगतियों को दूर कर देगा। यदि आप एजेंट नहीं हैं - और संसद सदस्य न तो इस सभा के और न ही किसी अन्य स्थान के एजेंट हैं - यदि आप किसी सार्वजनिक निकाय के सदस्य नहीं हैं (और हम सार्वजनिक निकायों के सदस्य नहीं हैं) तो संविधि आपको नहीं छूती है। कॉमन लॉ में आपको रिश्वत और भ्रष्टाचार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि आप एक कार्यालय के धारक नहीं हैं, और हम में से अधिकांश एक कार्यालय के धारक नहीं हैं।

(महत्त्व दिया गया)

136. सैल्मन रिपोर्ट की इस सिफारिश पर संसद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, आर बनाम ग्रीनवे,[64] संसद के एक सदस्य पर एक कंपनी के हितों की मदद करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन को रद्द करने के लिए मामला दायर किया गया था। संसद सदस्य ने जोर देकर कहा कि उनके कार्यों को संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित किया गया था। इस दावे को खारिज करते हुए, बकले, न्यायमूर्ति ने कहा कि:

'मेरे विचार से मौजूदा समय में एक अस्वीकार्य प्रस्ताव है कि संसद के एक सदस्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो, उसे अदालत में अभियोजन से छूट मिलनी चाहिए। मैं इसे कानून नहीं मानता।

137. संसद के कई सदस्यों द्वारा छींटाकशी के आरोपों के बाद एक और आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड नोलन की अध्यक्षता में सार्वजनिक जीवन में मानकों पर स्थायी समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में संदेह व्यक्त किया गया है कि रिश्वत लेने वाले संसद सदस्य पर अधिकार क्षेत्र किसके पास होगा। सदन और अदालत के बीच अधिकार क्षेत्र के सवाल को हल करने के लिए, रिपोर्ट ने एक क़ानून के रूप में संसद से स्पष्टता की सिफारिश की। रिपोर्ट ने सिफारिश की कि:

"1976 में सैल्मन कमीशन ने सिफारिश की थी कि इस तरह के संदेह को कानून द्वारा हल किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा मानना है कि जब आचरण से संबंधित संसद के कानून के अन्य पहलुओं को स्पष्ट किया जा रहा हो तो इस मुद्दे को बकाया छोड़ना असंतोषजनक होगा। हम सिफारिश करते हैं कि सरकार को अब संसद सदस्य द्वारा रिश्वत लेने या प्राप्त करने से संबंधित कानून को स्पष्ट करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसे रिश्वतखोरी पर क़ानून कानून के समेकन के साथ उपयोगी रूप से जोड़ा जा सकता है, जिसकी सैल्मन ने भी सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर

लिया था, लेकिन जो नहीं किया गया है। यह एक ऐसा कार्य हो सकता है जिसे विधि आयोग आगे ले जा सकता है। (महत्त्व दिया गया)

इस सिफारिश को सरकार ने विधि आयोग के पास भेजा था 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें एक नए कानून की सिफारिश की गई जो भ्रष्टाचार के अपराध को सभी पर लागू करता है। इसने घटनाओं का एक क्रम पैदा किया जो अंततः रिश्वत अधिनियम 2010 के अधिनियमन में समाप्त हुआ। अधिनियम उन उदाहरणों को कवर करता है जहां संसद के सदस्य भ्रष्टाचार में संलग्न हैं।

138. जब सांसदों द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, ब्रिटेन में अदालतों ने रिश्वतखोरी में संलग्न संसद सदस्यों पर अधिकारों के विधेयक के अनुच्छेद IX के दायरे पर सवालों के जवाब देना जारी रखा। जिन आरोपों के कारण नोलन समिति का गठन हुआ था, वे 1995 में अदालतों के सामने आए। आर बनाम मानक के लिए संसदीय आयुक्त पूर्व पक्षीय फयाद,[65] और हैमिल्टन बनाम अल फयाद[66]। पहले मामले में एक व्यक्ति ने एक सांसद पर उससे भ्रष्टाचार का धन लेने का आरोप लगाया था, जबकि वह सदस्य सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर रहा था। संसदीय मानक आयुक्त ने रिश्वत लेने से संबंधित आरोपों से संसद के एक सदस्य को बरी कर दिया था। शिकायतकर्ता ने न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति के लिए आवेदन किया। अपील की अदालत ने आवेदन की अनुमति दी और कहा कि:

"इस आवेदन पर मानक के लिए संसदीय आयुक्त के विशिष्ट कार्य की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो इस आवेदन पर शिकायत का विषय है। ऐसा है कि एक संसद सदस्य को भ्रष्ट भुगतान प्राप्त हुआ। श्री पैनिक ने ठीक ही कहा है कि संसदीय विशेषाधिकार अदालतों को ऐसे मुद्दों की जांच करने से नहीं रोकेगा जैसे कि संसद सदस्य ने आपराधिक अपराध किया है या नहीं, या क्या संसद सदस्य ने संसद के सदन के बाहर कोई बयान दिया है, जिस पर यह आरोप लगाया गया है कि वह मानहानिकारक है। वह प्रस्तुत करता है कि, इसके अनुरूप, आवेदक इस मामले में जिस तरह की शिकायत करता है, वह उस गतिविधि के संबंध में नहीं है, जिसके संबंध में संसद सदस्य को आवश्यक रूप से किसी भी प्रकार की संसदीय प्रतिरक्षा होगी। (महत्त्व दिया गया)

139. हैमिल्टन बनाम अल फयाद (उपरोक्त), संसद के एक अन्य सदस्य के खिलाफ समान तथ्यों से उत्पन्न एक अन्य मामला, एक सवाल उठा कि क्या संसदीय विशेषाधिकारों को माफ किया जा सकता है। न्यायालय तथ्यों पर विशिष्ट निष्कर्षों को वापस करते हुए, यह

भी कहा कि "अदालतों को किसी भी कार्यवाही में मनोरंजन करने से रोका जाता है (जो भी मुद्दा उन कार्यवाही में दांव पर लग सकता है) सबूत, पूछताछ या प्रस्तुतियाँ यह दिखाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं कि संसदीय कार्यवाही में एक गवाह ने जानबूझकर संसद को गुमराह किया है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में अदालत ने 1956 के फैसले पर भरोसा किया। प्रीबल बनाम टेलीविज़न न्यूज़ीलैंड।[67]

140. उपरोक्त मामले में, प्रतिवादी ने सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए एक कार्यक्रम प्रसारित किया था कि एक मंत्री ने एक व्यापारी और सार्वजनिक अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य की संपत्ति की बिक्री को बढ़ावा देने और लागू करने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य व्यवसायी को अनुचित अनुकूल शर्तों पर संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति देना था। मंत्री ने चैनल पर मानहानि का मुकदमा किया। चैनल ने सच्चाई की रक्षा करने और संसद में कही गई बातों और कृत्यों पर भरोसा करने की मांग की। इसने तर्क दिया कि बिल ऑफ राइट्स के अनुच्छेद IX के तहत संरक्षण केवल एक सदस्य को किसी भी सदन में अपने भाषण के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने से बचाएगा। हालांकि, उन्हें बचाव के रूप में रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है यदि इसका उपयोग किसी भी सदन में दिए गए भाषण पर दायित्व डालने के लिए नहीं किया जा रहा है। प्रिवी काउंसिल ने माना कि एक मुकदमे के पक्षकार सदन में कही गई या की गई किसी भी बात पर सवाल नहीं उठा सकते हैं या उन कार्यों के लिए किसी भी मकसद को आरोपित नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने सदन की कार्यवाही के आधिकारिक प्रकाशन पर इस हद तक निर्भरता की अनुमति दी कि उनका उपयोग यह सुझाव देने के लिए नहीं किया जाता है कि शब्द अनुचित तरीके से बोले गए थे, या अनुचित उपयोग के लिए कोई क़ानून पारित किया गया था।

141. विधायी सामग्री पर निर्भरता के सवाल को 2009 में विधायिका के पक्ष में तौला गया था। सरकारी वाणिज्य कार्यालय बनाम सूचना आयुक्त (अटॉर्नी जनरल हस्तक्षेप) ,[68] क्वीन्स बेंच डिवीजन ने माना कि संसदीय समितियों की राय उनके काम की प्रकृति को देखते हुए अदालत के समक्ष अप्रासंगिक होगी। यह धारण अधिकारों के विधेयक के अनुच्छेद IX के शब्दों और संबंधित इतिहास से प्रभावित था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के खंड (2) से अधिक व्यापक रूप से लिखा गया है। पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) मामले में अल्पसंख्यक राय इस मुद्दे पर इस प्रकार प्रकाश डालता है:

“ 41. […] अनुच्छेद 105 के खंड (2) के अधीन दिया गया संरक्षण अधिकार विधेयक के अनुच्छेद 9 के अधीन प्रदत्त संरक्षण से इस अर्थ में संकुचित है कि उस खंड द्वारा प्रदत्त

उन्मुक्ति प्रकृति में व्यक्तिगत है और सदस्य को सदन या उसकी किसी समिति में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उपलब्ध है। उक्त खंड संसद सदस्य द्वारा दिए गए भाषण या वोट पर अदालत में चुनौती देने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। अनुच्छेद 105 के खंड (2) के तहत दिया गया संरक्षण इस प्रकार हंट, न्यायमूर्ति द्वारा रखे गए निर्माण के तहत परिकल्पित सुरक्षा के समान है। आर बनाम मर्फी [(1986) 5 एनएसडब्ल्यूएलआर 18] अधिकारों के विधेयक के अनुच्छेद 9 पर जिसे प्रिवी काउंसिल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है प्रीबल बनाम टेलीविजन न्यूजीलैंड लिमिटेड [(1994) 3 ऑल ईआर 407, पीसी] एक्स पी वासन [(1869) 4 क्यूबी 573: 38 एलजेक्यूबी 302] में निर्णय जो बिल ऑफ राइट्स के अनुच्छेद 9 के संदर्भ में दिया गया था, इसलिए, अनुच्छेद 105 के खंड (2) के निर्माण के मामले में कोई आवेदन नहीं हो सकता है। […]"

क्या अदालतें संसदीय समिति के प्रतिवेदनों में निहित टिप्पणियों पर भरोसा कर सकती हैं, इस मुद्दे का अब इस न्यायालय की संविधान पीठ ने 1995 में निपटारा कर दिया। कल्पना मेहता (उपरोक्त)।

142. पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले में बहुमत का फैसला यू.के. के पहले के मामलों पर निर्भर था जो आम तौर पर भाषण और बहस की रक्षा के लिए अनुच्छेद IX की व्याख्या करते हैं। इन निर्णयों पर भरोसा करते हुए, बहुमत ने अदालतों के समक्ष कुछ भी पेश करने की अनुमति नहीं देने के एक सामान्य सिद्धांत का विस्तार किया, जो आकस्मिक रूप से या आकस्मिक रूप से एक विधायक के कृत्यों से संबंधित हो सकता है। न्यायालय ने तब अनुच्छेद 105 (2) की व्याख्या करके इस सिद्धांत को व्यापक तरीके से लागू किया ताकि विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने में प्राप्त रिश्वत के लिए प्रतिरक्षा संलग्न की जा सके। कोर्ट ने बकले, न्यायमूर्ति आर बनाम ग्रीनवे के मामले में इन की राय को खारिज कर दिया इस आधार पर कि अपील में इसका परीक्षण किया जाना बाकी है। इसलिए बहुमत ब्रिटेन और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले विभिन्न खंडों को प्रासंगिक रूप से लागू करने में विफल रहा। बहुमत द्वारा संदर्भित मामले, जबकि आम तौर पर कानून को समझने में सहायक होते हैं, वोटों को प्रभावित करने के लिए प्राप्त रिश्वत को प्रतिरक्षित करने में सहायता नहीं करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, संसद द्वारा रिश्वत पर विशेष अधिकार क्षेत्र के दावे के पीछे एक कारण यह था कि संसद के सदस्य भ्रष्टाचार-विरोधी क़ानून द्वारा कवर नहीं किए गए थे। हालांकि, एक संवैधानिक व्याख्या का जवाब देना होगा कि क्या अनुपस्थिति में किसी कानून के अनुसार, संसद का

सदस्य भ्रष्टाचार के धन को लेने के लिए प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है और इस तरह अपने वोट को प्रभावित कर सकता है।

143. इस न्यायालय के पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के निर्णय के बाद से यू.के. में अदालतों ने अनुच्छेद IX के तहत प्रतिरक्षा की संकीर्ण व्याख्या की है। आर बनाम चैटोर[69] का मामला, संसद सदस्यों पर झूठे दावे प्रस्तुत करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए मुकदमा चलाया गया था। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिल ऑफ राइट्स के अनुच्छेद IX का उद्देश्य सदन में बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। न्यायालय ने कहा कि प्रावधान को एक संकीर्ण दृष्टिकोण दिया जाना चाहिए और कहा कि अभियोजन पक्ष संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। कोर्ट ने होल्डिंग पर भरोसा किया ग्रीनवे (उपरोक्त) कि रिश्वत और संसद में दिए गए भाषण के बीच सांठगांठ अदालतों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करती है। इसलिए न्यायालय ने कहा कि खर्चों के लिए दावा प्रस्तुत करना और इस तरह की कार्यवाही में भाग लेना संसदीय विशेषाधिकारों के लिए और भी अधिक कठिन संबंध है और अभियोजन पक्ष से प्रतिरक्षा नहीं हो सकती है। न्यायालय ने इस परीक्षण को लागू किया कि क्या संसद के सदस्य की कार्रवाई, जिस पर सवाल उठाया जा रहा था, संसद के मूल या आवश्यक कार्य पर प्रभाव डालता है। लॉर्ड फिलिप ने कहा कि:

" 47. जिस न्यायशास्त्र का मैंने उल्लेख किया है वह विरल है और इन अपीलों के तथ्यों पर सीधे असर नहीं डालता है। हालांकि, यह इस प्रस्ताव का समर्थन करता है कि मुख्य मामला जिसके लिए अनुच्छेद 9 निर्देशित है, वह संसद के सदनों और संसदीय समितियों में भाषण और बहस की स्वतंत्रता है। यहीं पर संसद का मुख्य या आवश्यक कार्य होता है। इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या सदनों और समितियों के बाहर की कार्रवाई संसदीय कार्यवाही के भीतर आती है क्योंकि उनके साथ संबंध हैं, उस संबंध की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है और क्या यदि इस तरह के कार्यों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, तो इससे संसद के मुख्य या आवश्यक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ."

(महत्त्व दिया गया)

144. लॉर्ड रॉजर ने अपनी सहमति की राय के दौरान इस मुद्दे पर सदन के अवमानना अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होने पर प्रकाश डाला संसद का। लॉर्ड रॉजर ने माना कि यह एक अतिव्यापी क्षेत्राधिकार होगा और अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने की बात नहीं होगी। मकुडी बनाम बैरन ट्रिसमैन ऑफ़ ट्रॉटेनहैम[70] का मामला, अपील की अदालत ने माना कि एक गवाह द्वारा सार्वजनिक रूप से दिया गया एक बयान, जिसने संसदीय समिति के

समक्ष अपनी गवाही को दोहराया, प्रतिरक्षा को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि यह एक अतिरिक्त-संसदीय भाषण था जो संसदीय समिति के समक्ष बोलने के लिए बहुत दूर था। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रतिरक्षा कब आकर्षित हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि:

" 25. तथापि, मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां अनुच्छेद 9 का संरक्षण वास्तव में संसदेत्तर भाषण तक फैला हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे तथ्यों पर भिन्न होंगे, लेकिन आम तौर पर मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में ये दो विशेषताएं होंगी: (1) संसदीय कथन की पुनरावृत्ति में सार्वजनिक हित, जिसे अध्यक्ष को यथोचित रूप से सेवा करनी चाहिए, और (2) उनके बोलने के अवसरों के बीच एक सांठगांठ इतनी करीबी हो जाती है कि दूसरे अवसर पर बोलने के लिए उनके दायित्व की संभावना (या उम्मीद या वादा जो वह करेंगे इसलिए) पहले के समय यथोचित रूप से अनुमानित है और दोनों अवसरों पर बोलने में उसका उद्देश्य समान या बहुत निकट से संबंधित है। [...]"

145. ब्रिटेन में अदालतों ने, समय के साथ, विशेषाधिकारों के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले पहले के मामलों की तुलना में एक संकीर्ण दृष्टिकोण को उन्नत किया है। उन्होंने गैर-विधायी गतिविधियों के प्रतिरक्षा होने के लिए आवश्यक सांठगांठ के लिए एक संकीर्ण दायरे की व्याख्या की है। इससे यह धारणा बनी है कि अदालतों के अधिकार क्षेत्र को सदस्यों की प्रतिरक्षा या रिश्वतखोरी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की सदन की क्षमता से बाहर नहीं किया जाता है।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में संसदीय विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 1 की धारा 6 से उत्पन्न होते हैं। प्रावधान का प्रासंगिक हिस्सा, जिसे भाषण और बहस खंड के रूप में संदर्भित किया गया है, अंग्रेजी बिल ऑफ राइट्स 1689 के अनुच्छेद IX से प्रभावित है। खंड इस प्रकार है:

"सीनेटर और प्रतिनिधि को उनकी सेवाओं के लिए मुआवजा प्राप्त होगा जो कानून से प्राप्त होगा, और संयुक्त राज्य अमेरिका के खजाने से भुगतान किया जायेगा। वे राजद्रोह, गुंडागर्दी और शांति भंग को छोड़कर सभी मामलों में विशेषाधिकार प्राप्त होंगे अपने संबंधित सदनों के सत्र में उनकी उपस्थिति के दौरान गिरफ्तारी से, और उसी से जाने और लौटने में; और किसी भी सदन में किसी भाषण या वाद-विवाद के लिए, उन पर किसी अन्य स्थान पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।" (महत्त्व दिया गया)

जहां तक कांग्रेस के सदस्यों के विधायी कृत्यों का संबंध है, अमरीका में न्यायालयों ने भाषण और वाद-विवाद खंड की व्यापक व्याख्या की है। इसके अलावा, न्यायालयों ने माना है कि कांग्रेस का एक सदस्य सामान्य आवेदन के आपराधिक क़ानून के तहत उत्तरदायी हो सकता है। जो कुछ भी निषिद्ध है वह अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए सदस्य के आधिकारिक कृत्यों पर निर्भरता है।

147. संयुक्त राज्य बनाम थॉमस एफ जॉनसन का मामला,[71] कांग्रेस के एक सदस्य पर हितों के टकराव और संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। जॉनसन के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने मेल धोखाधड़ी के आरोप में एक बचत और ऋण कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ लंबित अभियोगों को प्रभावित करने और खारिज करने की साजिश रची। साजिश के हिस्से के रूप में, जॉनसन ने सदन में स्वतंत्र बचत और ऋण संघों के अनुकूल भाषण दिए। आरोपी को निचली अदालत ने दोषी पाया था। उनकी सजा को चौथे सर्किट के लिए अपील की अदालत ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि भाषण और बहस खंड के तहत आरोपों को अदालत में उठाए जाने से रोक दिया गया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भाषण और बहस खंड की व्याख्या करते हुए कहा कि सरकार कांग्रेस के किसी सदस्य द्वारा दिए गए भाषण का उपयोग नहीं कर सकती है या कानून की अदालत में इसकी प्रेरणा पर सवाल नहीं उठा सकती है। हालांकि, अभियोजन पक्ष कांग्रेसी द्वारा दिए गए भाषण पर भरोसा किए बिना मामला बना सकता है। न्यायालय ने कहा कि इसका निर्णय एक सामान्य आपराधिक कानून का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन पक्ष पर लागू नहीं होता है, जो 'कांग्रेस के प्रतिवादी सदस्य के विधायी कृत्यों या उन्हें प्रदर्शन करने के उनके उद्देश्यों पर सवाल नहीं उठाता है।

148. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा किया है जॉनसन (उपरोक्त) कांग्रेस के सदस्यों द्वारा रिश्वत से जुड़े वाद के मामलों में यह धारण करने के लिए कि वे तब तक मुकदमा चलाया जा सकता है जब तक कि वे विधायक द्वारा दिए गए भाषण या वोट पर भरोसा नहीं करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम ब्रूस्टर,[72] एक सीनेटर पर डाक दर कानून के संबंध में आधिकारिक कृत्यों के अपने प्रदर्शन में प्रभावित होने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर आरोपों को खारिज कर दिया कि सीनेटर ने संसदीय विशेषाधिकारों को आकर्षित किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से माना कि भाषण और वाद-विवाद खंड ने अभियोजकों को सबूत पेश करने से रोका कि कांग्रेस के सदस्य ने वास्तव में कुछ विधायी कार्य किए, जैसे कि भाषण देना या कानून पेश करना, एक भ्रष्ट योजना के

हिस्से के रूप में, लेकिन अन्य सबूत यह स्थापित कर सकते हैं कि सदस्य ने भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन किया था। न्यायालय ने कहा कि:

“43. हमारे संविधान के निर्माता विशेषाधिकार की आवश्यकता और दुरुपयोग दोनों के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे जो बहुत व्यापक सुरक्षा उपायों से उत्पन्न हो सकते हैं। अन्य मूल्यों को संरक्षित करने के लिए, उन्होंने विशेषाधिकार लिखा ताकि यह अन्य नागरिकों द्वारा किए जाने पर सहन और संरक्षित सदस्यों की ओर से व्यवहार को सहन और संरक्षित न करे, लेकिन ढाल विधायी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक से आगे नहीं बढ़ती है . […]

60. यह संदेह से परे है कि भाषण या वाद-विवाद खंड विधायी प्रक्रिया के नियमित पाठ्यक्रम में होने वाले कृत्यों की जांच और उन कृत्यों के लिए प्रेरणा से बचाता है। तो व्यक्त किया, विशेषाधिकार विधायी शाखा की ऐतिहासिक स्वतंत्रता का बीमा करने के लिए पर्याप्त व्यापक है, जो हमारी शक्तियों के पृथक्करण के लिए आवश्यक है, लेकिन उन लोगों की ज्यादतियों से बचाने के लिए पर्याप्त संकीर्ण है जो इसके सदस्यों को भ्रष्ट करके प्रक्रिया को भ्रष्ट करेंगे। […]

62. सवाल यह है कि क्या यह पूछताछ करना आवश्यक है कि अपीलकर्ता ने कैसे बात की, उसने कैसे बहस की, उसने कैसे मतदान किया, या उसने चैंबर में या समिति में क्रम में कुछ भी किया इस क़ानून का उल्लंघन करने के लिए। अवैध आचरण एक निश्चित तरीके से कार्य करने के वादे के लिए पैसे लेना या सहमत होना है। सरकार को यह दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अपीलकर्ता ने कथित अवैध सौदेबाजी को पूरा किया; रिश्वत स्वीकार करना कानून का उल्लंघन है, अवैध वादे का प्रदर्शन नहीं।

(महत्त्व दिया गया)

इसलिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार विधायिका की स्वतंत्रता को संरक्षित करना था। स्वतंत्रता वास्तव में क्या समझौता किया जाएगा अगर भाषण और बहस खंड को कांग्रेस के सदस्यों द्वारा रिश्वत के कृत्यों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करने के रूप में समझा जाना था। इसलिए, संविधान के तहत प्रतिरक्षा केवल उन कार्यों के लिए आकर्षित होती है जो स्पष्ट रूप से विधायी प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं।

149. न्यायालय में ब्रूस्टर (उपरोक्त) कार्यपालिका द्वारा जांच शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के प्रति सचेत था, लेकिन यह माना कि बहुमत से कार्य करने वाला सदन अभियुक्त के अधिकारों के लिए अधिक हानिकारक होगा यदि इसे अंतिम मध्यस्थ के रूप में छोड़ दिया जाए। न्यायालय ने कहा कि कांग्रेस के एक सदस्य को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से वंचित किया जाएगा जो अदालत आरोपी व्यक्तियों को देती है। कोर्ट ने आगे कहा कि:

" 58. अगर हम इसे स्वीकार करने में विफल रहे तो हम अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविकताओं के लिए अपनी आँखें बंद कर लेंगे कई गैर-विधायी गतिविधियां सदस्य की भूमिका का एक स्थापित और स्वीकृत हिस्सा हैं, और वास्तव में विधायी प्रक्रिया से 'संबंधित' हैं। लेकिन अगर कार्यपालिका किसी सदस्य के प्रयास पर मुकदमा चला सकती है, जैसा कि जॉनसन में, रिश्वत के बदले में सरकार की किसी अन्य शाखा को प्रभावित करने के लिए, परेशान करने की उसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ जाती है यदि वह रिश्वत के बदले में विधायी कार्य से संबंधित वादे के लिए मुकदमा चला सकती है। इसलिए हम आज हमारी पकड़ के परिणामस्वरूप विधायी शाखा पर कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं की शक्ति में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं देखते हैं। [...]

59. [...] जैसा कि हमने शुरू में उल्लेख किया था, भाषण या वाद-विवाद खंड का उद्देश्य व्यक्तिगत विधायक की रक्षा करना है, न केवल अपने लिए, बल्कि स्वतंत्रता और इस तरह विधायी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए। लेकिन रिश्वत के माध्यम से वित्तीय दुरुपयोग, शायद कार्यकारी शक्ति से भी अधिक, विधायी अखंडता को गंभीर रूप से कमजोर कर देगा और जनता के ईमानदार प्रतिनिधित्व के अधिकार को हरा देगा, कार्यपालिका को जांच और मुकदमा चलाने की शक्ति से वंचित करेगा और न्यायपालिका को कांग्रेस के सदस्यों की रिश्वतखोरी को दंडित करने की शक्ति से विधायी स्वतंत्रता बढ़ाने की संभावना नहीं है।

63. रिश्वत लेना, जाहिर है, विधायी प्रक्रिया या कार्य का कोई हिस्सा नहीं है; यह विधायी अधिनियम नहीं है। यह किसी भी बोधगम्य व्याख्या द्वारा, एक विधायक की भूमिका के एक हिस्से के रूप में या यहां तक कि आकस्मिक रूप से किया गया कार्य नहीं है। यह कार्यालय की प्रकृति और निष्पादन के परिणामस्वरूप कोई कार्य नहीं है, न ही यह उस कार्यालय के कार्यों के अभ्यास में, एक प्रतिनिधि के रूप में उसके द्वारा कही गई या की गई बात है, › 4 मास, 27 पर। न ही इस क़ानून या इस अभियोग के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक विधायी अधिनियम या विधायी अधिनियम के लिए प्रेरणा की जांच आवश्यक

है। जब रिश्वत ली जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस वादे के लिए रिश्वत दी गई थी, वह यहां एक विधायी कार्य के प्रदर्शन के लिए था या, जैसा कि जॉनसन में, कार्यकारी शाखा के साथ कांग्रेस के प्रभाव के उपयोग के लिए था। और रिश्वत के उद्देश्य की जांच 'कांग्रेस के प्रतिवादी सदस्य के विधायी कृत्यों या उन्हें करने के उनके उद्देश्यों पर सवाल नहीं उठाती है। 383 यूएस, 185 पर, 86 एससीटी, 758 पर।

64. न ही इससे कोई फर्क पड़ता है कि सदस्य अपने अवैध सौदेबाजी में चूक करता है। इस अभियोग के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए, सरकार को भुगतान के लिए भ्रष्ट वादे के बाद अपीलकर्ता का कोई कार्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह रिश्वत ले रहा है, अवैध समझौते का प्रदर्शन नहीं है, यह एक आपराधिक कार्य है। यदि, उदाहरण के लिए, निर्विवाद सबूत थे कि एक सदस्य ने किसी दिए गए बिल के लिए मतदान करने के लिए एक समझौते के बदले रिश्वत ली थी और यदि निर्विवाद सबूत भी थे कि उसने वास्तव में, बिल के खिलाफ मतदान किया था, तो क्या यह सोचा जा सकता है कि यह रिश्वत की प्रकृति को बदल देता है या इसे गलत काम के क्षेत्र से हटा देता है जिसे कांग्रेस ने अपराध बनाने की मांग की थी?

67. श्री न्यायमूर्ति ब्रेनन का सुझाव है कि कथित रिश्वत की जांच एक विधायी कार्य के लिए प्रेरणा की जांच है, और यह आग्रह किया जाता है कि जॉनसन में इस जांच की निंदा की गई थी। यह तर्क विधायी कृत्यों के लिए प्रेरणा की अवधारणा को गलत मानता है। भाषण या वाद-विवाद खंड अवैध आचरण की जांच को केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं करता है क्योंकि इसका विधायी कार्यों से कुछ संबंध है। जॉनसन में, कोर्ट ने कहा कि, रिमांड पर, जॉनसन को साजिश-से-धोखाधड़ी की गिनती पर फिर से कोशिश की जा सकती है, जब तक कि हाउस फ्लोर पर उनके भाषण से संबंधित सबूत स्वीकार नहीं किए जाते। […]." (महत्त्व दिया गया)

इसलिए न्यायालय ने इस विचार को खारिज कर दिया कि विधायी कार्यों से सांठगांठ रखने वाली कोई भी चीज अमेरिकी संविधान के भाषण और बहस खंड के तहत स्वचालित रूप से प्रतिरक्षा को आकर्षित करेगी।

150. वशिष्ठ गैवेल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, 73 कुछ गुप्त दस्तावेजों को सीनेटर गैवेल द्वारा अमेरिकी सीनेट में एक उप-समिति की सुनवाई के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था। फिर उन्होंने पूरे दस्तावेज़ को एक निजी प्रकाशन में प्रकाशित किया। सीनेटर के एक सहयोगी को ग्रैंड जूरी द्वारा सम्मन दिया गया था जो इस मामले की जांच कर रहा था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या सीनेटर के

सहयोगी को भाषण और वाद-विवाद खंड के तहत कोई प्रतिरक्षा प्राप्त है और उससे किस हद तक पूछताछ की जा सकती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायी कार्य की विस्तृत प्रकृति को देखते हुए, कांग्रेस के एक सदस्य के सहयोगी को भाषण और बहस खंड के तहत संरक्षित किया जाएगा, लेकिन केवल इस हद तक कि यह विधायक को उसके विधायी कार्यों के निर्वहन में सहायता करने से संबंधित है। न्यायालय ने आगे कहा कि दस्तावेज़ का निजी प्रकाशन सीनेटर के कार्यों का एक आवश्यक हिस्सा नहीं था और उस संबंध में कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी। न्यायालय ने कहा कि:

" 26. विधायी कार्य सर्वव्यापी नहीं हैं। खंड का केंद्र किसी भी सदन में भाषण या बहस है। जहां तक खंड का अर्थ अन्य मामलों तक पहुंचने के लिए लगाया गया है, वे विचार-विमर्श और संचार प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग होना चाहिए जिसके द्वारा सदस्य प्रस्तावित कानून पर विचार करने और पारित करने या अस्वीकार करने के संबंध में या अन्य मामलों के संबंध में समिति और सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं जिन्हें संविधान किसी भी सदन के अधिकार क्षेत्र में रखता है। जैसा कि अपील की अदालत ने कहा, अदालतों ने किसी भी सदन में शुद्ध भाषण या बहस से परे मामलों के लिए विशेषाधिकार बढ़ाया है, लेकिन 'केवल जब इस तरह के विचार-विमर्श की अप्रत्यक्ष हानि को रोकने के लिए आवश्यक हो। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम डो, 455 च.2घ, 760 पर।

27. यहां, बीकन प्रेस के सहयोग से सीनेटर ग्रेवल द्वारा निजी प्रकाशन सीनेट के विचार-विमर्श के लिए किसी भी तरह से आवश्यक नहीं था; न ही निजी प्रकाशन के रूप में पूछताछ से सीनेट की अखंडता या स्वतंत्रता को खतरा है, जो कार्यकारी प्रभाव के लिए अपने विचार-विमर्श को उजागर करता है। सीनेटर ने अपनी सुनवाई की थी; रिकॉर्ड और आने वाली कोई भी रिपोर्ट उनकी समिति और सीनेट दोनों के लिए उपलब्ध थी। जहां तक हमें सलाह दी जाती है, न तो कांग्रेस और न ही पूर्ण समिति ने प्रकाशन का आदेश दिया या अधिकृत किया। यहां दावा किया गया एकमात्र संवैधानिक दावा भाषण या वाद-विवाद खंड पर आधारित है। हमें उन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब कांग्रेस या या तो सदन, जैसा कि एक सदस्य से अलग है, समिति की सुनवाई, रिपोर्ट या अन्य सामग्रियों के प्रकाशन और या सार्वजनिक वितरण का आदेश देता है। बेशक, कला। मैं, § 5, खंड 3, की आवश्यकता है कि प्रत्येक सदन ‹ अपनी कार्यवाही की एक पत्रिका रखें, और समय-समय पर इसे प्रकाशित करें, ऐसे भागों को छोड़कर जो उनके निर्णय में गोपनीयता की आवश्यकता हो सकती है। यह खंड व्यापक न्यायिक परीक्षा का विषय नहीं रहा है। देखें फील्ड बनाम क्लार्क, 143 यूएस 649, 670-671, 12 एससीटी 495,

496-497, 36 एल.एड. संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम बैलिन, 144 यूएस 1, 4, 12 एससीटी 507, 508, 36 एलईडी 321 (1892)। हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि बीकन प्रेस के साथ सीनेटर की व्यवस्था विधायी प्रक्रिया का हिस्सा और अभिन्न अंग नहीं थी।

(महत्त्व दिया गया)

151, न्यायालय ने गवेल (उपरोक्त) मामले में ने उसी मानक को लागू किया जो उसने किया था ब्रूस्टर (उपरोक्त) के मामले में यह मानने के लिए कि केवल ऐसे कार्य जो सदन के विचार-विमर्श के लिए आवश्यक हैं या संविधान के तहत निहित कार्यों के निर्वहन में कानून की अदालत के समक्ष अभियोजन से प्रतिरक्षा हैं। अन्य कार्य जो किसी तरह से विधायक के भाषण या वोट से संबंधित हो सकते हैं, उन्हें भाषण और बहस खंड के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे विधायक के कार्य के लिए आवश्यक न हों। इसलिए न्यायालय ने एक सुसंगत स्थिति रखी कि कांग्रेस के सदस्यों को केवल उनके 'वैध विधायी गतिविधि के क्षेत्र' के लिए संविधान के तहत प्रतिरक्षा होगी।

152. संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम हेलस्टोस्की,[74] प्रतिनिधि सभा के एक सदस्य पर आव्रजन कानूनों के आवेदन को निलंबित करने के लिए कुछ निजी बिल पेश करने के बदले में धन स्वीकार करने का आरोप लगाया गया था मैं अपने पिछले फैसलों पर भरोसा करते हुए जॉनसन (उपरोक्त), ब्रूस्टर (उपरोक्त) और मुँगरी (उपरोक्त) अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाषण और बहस खंड का उद्देश्य विधायक को कार्यकारी और न्यायिक निरीक्षण से मुक्त करना था जो वास्तविक रूप से एक विधायक के रूप में अपने आचरण को नियंत्रित करने की धमकी देता है। न्यायालय ने अमेरिकी कानून की स्थिति की पुष्टि की कि आरोपी कांग्रेसी के विधायी कृत्यों की सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता है या ग्रैंड जूरी के सामने नहीं रखा जा सकता है, लेकिन रिश्वत के सबूत और भविष्य के विधायी कार्य करने का वादा करने की जांच की जा सकती है क्योंकि वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विधायक के एक आवश्यक कार्य का गठन नहीं करते हैं।

153. हम संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून की स्थिति के विश्लेषण के समापन से पहले एक और निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। हचिंसन बनाम प्रॉक्समायर का मामला,[75] एक सीनेटर एक प्रकाशन जारी करेगा जिसमें वह "बेकार सरकारी खर्च" के रूप में माना जाता है। सीनेटर ने सीनेट के फर्श पर एक भाषण दिया और इसे प्रेस में प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता, जिसे अपने शोध के लिए सार्वजनिक संस्थानों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, सीनेटर द्वारा नामित किया गया था। प्रेस विज्ञप्ति एजेंसियों सहित एक लाख से अधिक

लोगों को परिचालित की गई थी। जिसने शिकायतकर्ता के शोध को वित्त पोषित किया। शिकायतकर्ता ने अपने पेशे में सम्मान की हानि, आय की हानि और भविष्य में आय अर्जित करने की क्षमता का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया। जिला न्यायालय ने सीनेटर के पक्ष में सारांश निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि प्रकाशन कांग्रेस के 'सूचना कार्य' के तहत आता है और भाषण और बहस खंड के तहत प्रतिरक्षा होगी।

154. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाषण और बहस खंड का इरादा कांग्रेस के सदस्यों के पक्ष में एक पूर्ण विशेषाधिकार बनाना नहीं था। न्यायालय ने कहा कि यह खंड केवल "विधायी गतिविधियों" के लिए आकर्षित होता है और मानहानिकारक बयानों के पुनर्प्रकाशन की रक्षा नहीं करेगा। न्यायालय ने कहा कि:

"विधायी गतिविधियों" शब्द में जो भी अशुद्धि हो सकती है, यह स्पष्ट है कि इतिहास में या खंड की स्पष्ट भाषा में कुछ भी चैंबर के बाहर दिए गए मानहानिकारक बयानों के लिए दायित्व या वाद से पूर्ण विशेषाधिकार बनाने के किसी भी इरादे का सुझाव नहीं देता है।

विधायी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक से परे जाने वाले खंड के तहत दावों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

वास्तव में, पूर्वोदाहरण इस निष्कर्ष का बहुतायत से समर्थन करते हैं कि किसी सदस्य को मूल रूप से किसी भी सदन में दिए गए मानहानिकारक बयानों को पुनः प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। हम उस लंबे समय से स्थापित नियम से कोई कारण नहीं देखते हैं। (महत्त्व दिया गया)

155. सिद्धांत जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेषाधिकारों के संबंध में उठाए गए दृष्टिकोण से उभरता है, वह यह है कि कांग्रेस का एक सदस्य भाषण या वोट के संदर्भ में विधायी कृत्यों को करने के लिए रिश्वत में संलग्न होने के लिए प्रतिरक्षा नहीं है। भाषण और वाद-विवाद खंड विधायी गतिविधि के साथ सांठगांठ वाली सभी चीजों के संबंध में एक विधायक को कोई पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं देता है। प्रतिरक्षा केवल उन कार्यों के लिए आकर्षित होती है जो आवश्यक हैं और विधायी कार्य के वैध क्षेत्र के भीतर हैं। अभियोजन पक्ष में एक कांग्रेसी को आकर्षित करने वाला एकमात्र विशेषाधिकार यह है कि भाषण, वोट या विधायी कृत्यों की सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत के रूप में पेश नहीं की जा सकती है।

156. बहुमत का फैसला - पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले में जो व्याख्या की है और जॉनसन (उपरोक्त) में असहमतिपूर्ण राय ब्रूस्टर (उपरोक्त) में उसी निष्कर्ष पर पहुंचने

के लिए जो उसने यूके में कानून के प्रतिबिंब पर किया था। यहां भी, बहुमत का फैसला दो खातों पर विफल होता है। सबसे पहले, यह इस तथ्य को ध्यान में रखने में विफल रहता है कि भाषण और वाद-विवाद खंड जो अंग्रेजी बिल ऑफ राइट्स के अनुच्छेद IX से काफी हद तक उधार लिया गया है, संसद में किए गए भाषण और वोट के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बहुमत के फैसले में पहुंची समझ को संयुक्त राज्य अमेरिका में मामलों की एक पंक्ति में कानून के विकास द्वारा सूचित नहीं किया गया था। इसके विपरीत, बहुमत का निर्णय पूरी तरह से 1977 में असहमतिपूर्ण राय पर निर्भर था। ब्रूस्टर (उपरोक्त) इस तरह की निर्भरता के लिए पर्याप्त पुष्टि के बिना। दूसरे, बहुमत के फैसले ने भाषण और वाद-विवाद खंड की अपनी व्याख्या को बढ़ा दिया है और इस समझ को संतुष्ट करने के लिए अनुच्छेद 105 (2) की व्याख्या को कबूतर - खाना बना दिया है।

3. कनाडा

157. इस सटीक प्रश्न का कि क्या विधायकों को किसी निश्चित दिशा में मतदान करने के लिए रिश्वत देना संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में आता है, इस पर रानी की बेंच ने 1995 में निर्णय दिया था। आर बनाम बंटिंग एट अल।[76] उस मामले में, प्रतिवादियों ने सरकार के खिलाफ वोट देने के लिए विधायिका के सदस्यों को रिश्वत देकर ओंटारियो प्रांत की सरकार को बदलने की साजिश के लिए एक अभियोग को रद्द करने की मांग की थी। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विधायिका के सदस्यों को रिश्वत देने और साजिश रचने का अपराध अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस तरह की जांच संसदीय विशेषाधिकार का अतिक्रमण नहीं करेगी। इसके अलावा, यह माना गया कि यदि प्रतिवादियों के खिलाफ अदालत द्वारा कार्यवाही की गई थी, तो अधिकारों और विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए विधायिका द्वारा उनके खिलाफ समानांतर रूप से पूछताछ की जा सकती है। कार्यवाही विभिन्न अपराधों के लिए होती है, अपने आप में आयोजित की जा सकती है और ऐसी स्थितियों में दोहरी सजा या दोहरे खतरे का मामला नहीं बनता है। कोर्ट (विल्सन, मुख्या न्यायमूर्ति के माध्यम से बोलते हुए) ने अभिनिर्धारित किया:

"मेरे विचार से यह एक प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है कि इस न्यायालय के पास इस तरह के मामले में आम कानून के रूप में रिश्वत के अपराध पर अधिकार क्षेत्र है, जहां विधान सभा का एक सदस्य या तो रिश्वत देने या देने की पेशकश में चिंतित है, या उस विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने किसी भी कर्तव्य के लिए या उसके संबंध में इसे लेने में चिंतित है; और यह भी उतना ही स्पष्ट है कि विधान सभा के पास वह अधिकार क्षेत्र नहीं है जो इस

न्यायालय के पास इस तरह के मामले में है; और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि रिश्वतखोरी की प्राचीन परिभाषा उस अपराध की उचित या कानूनी परिभाषा नहीं है।

इससे अधिक निश्चित रूप से कुछ भी तय नहीं है कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स, और विभिन्न औपनिवेशिक विधानमंडलों ने आपराधिक अधिकार क्षेत्र नहीं किया है, और कभी नहीं था।

लेकिन अगर ये तीन व्यक्ति इस बात पर सहमत होते कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के दो सदस्यों को ये झूठे बयान देने चाहिए, या किसी विशेष तरीके से वोट देना चाहिए, तो उन्हें दी गई रिश्वत के विचार में या भुगतान किया जाना चाहिए, तो यह एक कार्य करने की साजिश होगी, जरूरी नहीं कि अवैध हो, लेकिन अवैध तरीकों से कार्य करने के लिए, रिश्वत कानून के खिलाफ अपराध है; और साजिश का अपराध उन अवैध साधनों के कारण पूरा हो गया होगा जिनके द्वारा अधिनियम को प्रभावित किया जाना था। उस अपराध की जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती थी, क्योंकि जो कुछ भी किया गया था, वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बाहर के मामलों की होती, और इसलिए लेक्स संसद का कोई उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं हो सकता था। (महत्त्व दिया गया)

158. पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के निर्णय में बुन्तिंग (उपरोक्त) में न्यायालय के समक्ष था। अल्पसंख्यक ने स्पष्ट रूप से निर्णय पर भरोसा किया, यह मानते हुए कि एक विधायक को रिश्वत देना कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आपराधिक कानून के तहत एक सामान्य कानून अपराध के रूप में माना जाता था और एक विधायक पर अपराध के लिए आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। अग्रवाल, न्यायमूर्ति ने नोट किया:

" 54. [...] ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जहां एक विधायक की रिश्वतखोरी को आम कानून में अपराध माना जाता था, अदालतों ने 1956 में वाइट [13 एससीआर (एनएसडब्ल्यू) 332], बोस्टन [(1923) 33 सीएलआर 386] और बुन्तिंग [(1884-85) 7 ओंटारियो रिपोर्ट 524] ने माना था कि विधायक पर उक्त अपराध के लिए आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। अत यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि हाउस ऑफ कामन्स के किसी सदस्य द्वारा रिश्वत स्वीकार किए जाने को हाउस ऑफ कामन्स द्वारा विशेषाधिकार हनन माना गया था और सभा द्वारा सदस्य के विरुद्ध अवमान के लिए कार्रवाई की जा सकती थी, इसलिए 26-1-1950 को हाउस ऑफ कामन्स के सदस्य संसद के कार्य के संबंध में रिश्वत स्वीकार करने वाले आचरण के संबंध में विशेषाधिकार का उपभोग कर रहे थे। उन्हें केवल सदन के विशेषाधिकार हनन के लिए दंडित किया जा सकता था और उन पर

न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (3) को अपीलकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप के संबंध में अभियोजन से प्रतिरक्षा का दावा करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

55. [...] निर्णय के पहले भाग में हमने पाया है कि पिछले 100 से अधिक वर्षों से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में विधायकों पर उनकी विधायी गतिविधियों के संबंध में रिश्वत के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और, यूनाइटेड किंगडम के अपवाद के साथ, अधिकांश राष्ट्रमंडल देश विधायिका के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को एक आपराधिक अपराध मानते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी इस संबंध में कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव है। ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि भारत में विधायकों को रिश्वत और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाले कानूनों की सीमा से परे होना चाहिए, जब अन्य सभी सार्वजनिक पदाधिकारी ऐसे कानूनों के अधीन हैं। इसलिए, हम श्री ठाकुर के उपरोक्त तर्क को बरकरार रखने में असमर्थ हैं। (महत्त्व दिया गया)

दूसरी ओर, बहुमत का निर्णय एक संदर्भ देता है बुन्तिंग (उपरोक्त) के मामले में रिकॉर्ड पर रखे गए कनाडाई अदालतों के फैसले या किसी अन्य फैसले पर भरोसा नहीं करने का विकल्प चुनता है।

159. न्यायशास्त्र की एक और दिलचस्प रेखा, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 के निर्णय के बाद विस्तारित की गई। पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त), इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रासंगिक है। संसदीय विशेषाधिकार के परित्याग से निपटते हुए, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय के भाग एफ में तैयार किए गए पैरीक्षण के समान एक सूत्रीकरण में 'आवश्यकता' की कसौटी को अपनाया है। इस संबंध में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय कनाडा (हाउस ऑफ कॉमन्स) बनाम वैद,[77] कुछ विस्तार से नोट किया जा सकता है।

160. उपरोक्त मामले में, हाउस ऑफ कॉमन्स के पूर्व अध्यक्ष पर उन कारणों से अपने चालक को बर्खास्त करने का आरोप लगाया गया था जो कथित तौर पर कनाडाई मानवाधिकार अधिनियम, 1985 के तहत कार्यस्थल भेदभाव का गठन करते थे। इसका हाउस ऑफ कॉमन्स ने विरोध किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि इस तरह की जांच संसदीय विशेषाधिकार पर अतिक्रमण का गठन करती है और सदन के कर्मचारियों की भर्ती और बर्खास्तगी "आंतरिक मामला" है, जिस पर सदन के अलावा किसी भी न्यायाधिकरण या

अदालत द्वारा सवाल या समीक्षा नहीं की जा सकती है। अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

161. कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधायी निकाय भूमि के सामान्य कानून से परिरक्षित एन्क्लेव का गठन नहीं करते हैं। जो पार्टी संसदीय विशेषाधिकार की व्यापक छतरी के नीचे प्रतिरक्षा पर भरोसा करना चाहती है, उसके पास अपना अस्तित्व स्थापित करने का दायित्व है। कनाडा में, यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स का उपयोग संसदीय विशेषाधिकार के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेषाधिकार वास्तव में मौजूद है, पहला कदम यह जांचना है कि क्या यह कनाडा की संसद या हाउस ऑफ कॉमन्स के संबंध में आधिकारिक रूप से स्थापित है। यदि अस्तित्व स्थापित नहीं किया गया है, तो आवश्यकता के सिद्धांत को यह निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना है कि क्या अधिनियम संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित है। संक्षेप में, विधायिका या प्रतिरक्षा चाहने वाले सदस्य को यह साबित करना होगा कि जिस गतिविधि के लिए विशेषाधिकार का दावा किया गया है, वह विधायिका द्वारा अपने कार्यों की पूर्ति के साथ निकटता से और सीधे जुड़ा हुआ है और बाहरी हस्तक्षेप विधानसभा के लिए आवश्यक स्वायत्तता को प्रभावित करेगा "गरिमा और दक्षता" के साथ अपने कार्यों को पूरा करने के लिए .

162. कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"जबकि संसद के प्रत्येक सदन के लिए बहुत अधिक अक्षांश छोड़ दिया जाता है, विशेषाधिकार की परिभाषा के लिए इस तरह के एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सीमाओं का अर्थ है। सामान्य मान्यता है, उदाहरण के लिए, यह विशेषाधिकार "संसद में कार्यवाही" से जुड़ा हुआ है। फिर भी, जैसा कि एर्स्किन मई (19 वां संस्करण 1976) में कहा गया है, पृष्ठ 89 पर, "व्यापार के लेन-देन के दौरान चैंबर के भीतर जो कुछ भी कहा या किया जाता है, वह संसद में कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनता है। विशिष्ट शब्द या कार्य किसी ऐसे कार्य से पूर्णत असंबंधित हो सकते हैं जो संव्यवहार के दौरान हो या अधिक सामान्य अर्थ में सभा के समक्ष हो क्योंकि उसे यथासमय उसके समक्ष आने का आदेश दिया गया हो। (इस मार्ग को रे क्लार्क में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था। इस प्रकार आर. बनाम बुन्तिंग (1885), 7 ओ.आर. 524, उदाहरण के लिए, क्वीन्स बेंच डिवीजन ने माना कि प्रांतीय विधायिका के सदस्यों को रिश्वत देकर सरकार में बदलाव लाने की साजिश किसी भी तरह से संसद में कार्यवाही से जुड़ी नहीं थी और इसलिए, अदालत के पास अपराध

की कोशिश करने का अधिकार क्षेत्र था। एर्स्किन मई (23 वां संस्करण) 1815 में "विशेषाधिकार समिति" की एक राय को संदर्भित करता है कि चैंबर में लॉर्ड कोचरन (कॉमन्स के सदस्य) की फिर से गिरफ्तारी (सदन बैठक में नहीं था) विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं था। विशेष शब्द या कार्य किसी भी व्यवसाय से पूरी तरह से असंबंधित हो सकते हैं या नियत समय में सदन के समक्ष आने का आदेश दिया जा सकता है।

ये सभी स्रोत एक समान निष्कर्ष की दिशा में इंगित करते हैं। संसदीय विशेषाधिकार के दावे को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रतिरक्षा की मांग करने वाले विधानसभा या सदस्य को यह दिखाना होगा कि गतिविधि का क्षेत्र जिसके लिए विशेषाधिकार का दावा किया जाता है, विधानसभा या उसके सदस्यों द्वारा विधायी और विचार-विमर्श निकाय के रूप में उनके कार्यों की पूर्ति के साथ इतनी निकटता से और सीधे जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकार को जवाबदेह ठहराने में विधानसभा का काम शामिल है, यह बाहरी हस्तक्षेप विधानसभा और उसके सदस्यों को गरिमा और दक्षता के साथ अपना काम करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्वायत्तता के स्तर को कमजोर करेगा। (महत्त्व दिया गया)

163. इसी प्रकार कनाडा के उच्चतम न्यायालय का 1997 में दिया गया निर्णय चैगनोन बनाम *Syndicat* de *la fonction publique et parapublique du Québe*,[78] पर निर्भर करता है वैद (उपरोक्त) और समान शब्दों में 'आवश्यकता' की परीक्षा को अपनाता है। उस मामले में, क्यूबेक की नेशनल असेंबली द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्डों को विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। श्रम मध्यस्थ के समक्ष बर्खास्तगी पर हमला किया गया था। इस पर इस आधार पर आपत्ति की गई थी कि गार्डों को बर्खास्त करने का निर्णय समीक्षा के अधीन नहीं है और संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित है। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुमत की राय में माना कि सुरक्षा गार्डों की बर्खास्तगी संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार की अंतर्निहित प्रकृति इंगित करती है कि इसका दायरा इसके औचित्य पर आधारित होना चाहिए, अर्थात विधायिकाओं को उनके विधायी और विचारशील कार्यों के निर्वहन में रक्षा करना। एक संसदीय विशेषाधिकार को मान्यता देने वाली अदालत इस बात पर जोर देती है कि अदालत अपने अभ्यास की समीक्षा नहीं कर सकती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए कि यह केवल विधानसभा की संवैधानिक भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है। तथ्यात्मक संदर्भ में, न्यायालय ने माना कि सुरक्षा गार्डों के प्रबंधन पर संसदीय विशेषाधिकार की आवश्यकता स्थापित नहीं की जा

सकती है। गार्डों के प्रबंधन को विधानसभा की सुरक्षा या मुद्दों पर विचार-विमर्श करने की क्षमता को बाधित किए बिना सामान्य कानून के तहत निपटाया जा सकता है।

4.ऑस्ट्रेलिया

164. ऑस्ट्रेलिया में कानून की स्थिति 1875 से सुसंगत रही है। अदालतों ने माना है कि अपने वोटों को प्रभावित करने के लिए विधायिका के एक सदस्य को रिश्वत देने का प्रयास आम कानून के तहत एक आपराधिक अपराध है। न्यू साउथ वेल्स के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आर बनाम एडवर्ड व्हाइट[79] इस संबंध में एक मील का पत्थर था। सर जेम्स मार्टिन (मुख्य न्यायमूर्ति) ने अवलोकित किया:

"अब न्यायालय के विचार के लिए बिंदु, क्या इस प्रकार की गई आपत्ति वैध है या नहीं, या दूसरे शब्दों में, क्या विधान सभा के किसी सदस्य को रिश्वत देने का प्रयास एक आपराधिक अपराध है। मेरी स्पष्ट राय है कि इस तरह का प्रयास आम कानून में एक दुष्कर्म है। यद्यपि विधानमंडल के सदस्य को रिश्वत देने का प्रयास करने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ सूचना या अभियोग पर कोई मामला नहीं पाया जा सकता है, ऐसे कई मामले हैं जो दिखाते हैं कि इस तरह का प्रयास एक अपराध है।

जनता को चोट अधिक प्रत्यक्ष है और निश्चित रूप से वास्तव में चुने गए व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ करने में अधिक है, जो उसे चुनने वाले व्यक्तियों की तुलना में है। भ्रष्ट रूप से प्राप्त मतों के माध्यम से विधानमंडल में भेजा गया व्यक्ति एक सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ सदस्य हो सकता है; लेकिन एक विधायक जो रिश्वत से प्रभावित होने के लिए अपने वोट को पीड़ित करता है, वह करता है जो उनकी नींव में प्रतिनिधि संस्थानों की उपयोगिता को खत्म करने के लिए गणना की जाती है। यह आम कानून के लिए एक तिरस्कार होगा यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा रिश्वत की पेशकश, या स्वीकृति, अपराध नहीं थी। (महत्त्व दिया गया)

इसी तरह, न्यायमूर्ति हरग्रेव ने भी इस प्रकार देखा:

"ये कई आधुनिक प्राधिकरण स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि रिश्वतखोरी के खिलाफ पुराने आम कानून निषेध लंबे समय से केवल न्यायिक अधिकारियों से परे कार्यालय की शपथ के तहत कार्य करने से परे हैं, सभी व्यक्तियों के लिए जो भी सार्वजनिक विश्वास और विश्वास के पद धारण करते हैं; और यह समझना असंभव प्रतीत होता है कि हमारी विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों, जिन्हें हमारे कानूनों को लागू करने का सार्वजनिक कर्तव्य सौंपा गया है, को कम से कम रिश्वत और भ्रष्टाचार से उतना ही संरक्षित क्यों नहीं

किया जाना चाहिए जितना कि किसी न्यायाधीश या कांस्टेबल को कानून का पालन करना है।" (महत्त्व दिया गया)

165. इसके बाद, निर्णय वाइट (उपरोक्त) का अनुसरण ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने भी 1956 में किया था। आर बनाम बोस्टन।[80] यह एक ऐसा मामला था जहां कुछ निजी पार्टियों ने विधान सभा के सदस्यों को रिश्वत देने के लिए एक समझौता किया था ताकि वे कुछ सम्पदाओं के अधिग्रहण को सुरक्षित करने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग कर सकें। न्यायालय के समक्ष जो तर्क दिया गया वह अद्‌वितीय था। अपीलकर्ता ने 1996 में स्थापित प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। वाइट (उपरोक्त) कि विधानसभा के एक सदस्य को उनके वोट को प्रभावित करने के लिए पैसे का भुगतान करने का समझौता एक आपराधिक अपराध होगा। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि इस मामले में रिश्वत विधानसभा के सदस्य को रिश्वत देने वालों के पक्ष में विधानसभा के अंदर नहीं बल्कि बाहर अपने पद का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए थी। न्यायालय ने संसद के अंदर कृत्यों को करने के लिए अवैध संतुष्टि और संसद के बाहर कृत्यों के बीच कृत्रिम अंतर को खारिज कर दिया और माना कि दोनों मामलों में, रिश्वत का कार्य सदस्य की उदासीन निर्णय लेने की क्षमता को कम करता है, जिससे लोगों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। नॉक्स, मुख्या न्यायमूर्ति ने अभिनिर्धारित किया:

"[...] मेरी राय में, संसद के एक सदस्य को धन का भुगतान, और धन की प्राप्ति, उसे अपने आधिकारिक पद का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए, चाहे संसद के अंदर या बाहर, किसी मंत्री या क्राउन के अन्य अधिकारी को प्रभावित करने या दबाव डालने के उद्‌देश्य से सार्वजनिक धन से धन के भुगतान से जुड़े लेनदेन में प्रवेश करने या करने के लिए, सार्वजनिक शरारत के लिए प्रवृत्त कार्य हैं, और इस तरह के कृत्यों को करने के लिए एक समझौता या संयोजन एक आपराधिक अपराध है। सार्वजनिक शरारत की प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से, मैं किसी सदस्य को संसद में अपने मत का प्रयोग किसी विशेष दिशा में करने के लिए प्रलोभन देने के लिए धन देने और संसद के बाहर अपने पद का प्रयोग मंत्रियों को प्रभावित करने या उन पर दबाव डालने के लिए करने के लिए उसे धन देने के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखता।

संसद के किसी सदस्य को किसी विशेष लेन-देन को करने के लिए किसी मंत्री को मनाने या प्रभावित करने या दबाव डालने के लिए प्रेरित करने के लिए धन का भुगतान कई तरह से सार्वजनिक शरारत करता है, भले ही संसद के अंदर या बाहर आचरण द्‌वारा दबाव डाला

जाए। यह प्राप्तकर्ता को सार्वजनिक हित की परवाह किए बिना अपने पे-मास्टर के हित की सेवा करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है, और संसद में बैठने और मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग उस परिणाम को लाने के साधन के रूप में करता है जिसे प्राप्त करने के लिए उसे भुगतान किया जाता है। यह सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से लेन-देन के गुणों पर एक उदासीन निर्णय लेने की उसकी क्षमता को कम करता है और उसे लोगों के प्रतिनिधि के बजाय उस व्यक्ति का सेवक बनाता है जो उसे भुगतान करता है। "

(महत्त्व दिया गया)

166. ऑस्ट्रेलिया के न्यायालयों ने भी 1966 में यू.के. के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति का पालन किया है। चैटोर (उपरोक्त) कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास सदन के सदस्यों द्वारा आपराधिक आचरण से निपटने का विशेष अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसे मामलों का एकमात्र अपवाद तब होता है जब संसदीय विशेषाधिकार का अस्तित्व मुद्दों को निर्धारित करना लगभग असंभव बना देता है या यदि कार्यवाही सदन की विधायी और विचार-विमर्श के व्यवसाय का संचालन करने की क्षमता में हस्तक्षेप करती है। उदाहरण के लिए, में ओबेद बनाम क्वीन,[81] अपीलकर्ता पर अपने लिए आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए अपने पद का उपयोग करके कार्यालय में कदाचार के अपराध का आरोप लगाया गया था। न्यू साउथ वेल्स के लिए आपराधिक अपील की अदालत के समक्ष तर्क दिए गए आधारों में से एक यह था कि चूंकि संसद के पास विधानसभा के सदस्यों द्वारा इस तरह के उल्लंघनों से निपटने की शक्ति थी, इसलिए अदालत को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से बचना चाहिए था। कोर्ट ने पीछा किया चैटोर (उपरोक्त) यह धारण करने के लिए कि न्यायालय और संसद के पास आपराधिक मामलों के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार हो सकता है और ऐसा कोई कानून नहीं था जो अदालत को उन मामलों का निर्धारण करने से रोकता हो जो "संसद में कार्यवाही" का गठन नहीं करते हैं।

167. निर्णय- वाइट (उपरोक्त) और बोस्टन (उपरोक्त) को 1996 में न्यायालय के समक्ष रखा गया था। पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त)। अल्पमत के फैसले में दोनों निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला गया कि किसी विधायक को संसद में मतदान करने या बोलने के लिए प्रभावित करने के लिए रिश्वत देना एक आपराधिक अपराध है, जिसे अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है। बहुमत का निर्णय, हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई उदाहरणों का उल्लेख नहीं करता है।

(झ) राज्य सभा के चुनाव अनुच्छेद 194(2)

168. अंत में हम अपना ध्यान विद्वान महान्यायवादी श्री वेंकटरमणी द्वारा दिए गए तर्क की ओर आकषत कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि निर्णय पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। में तथ्यात्मक स्थिति पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) यह अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है, जबकि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने राज्य सभा या राज्यसभा में रिक्त सीटों को भरने के लिए मतदान किया था। प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था बाहर यदि सभा लॉबी में है, तो इसे अविश्वास प्रस्ताव की तरह सभा की कार्यवाही नहीं माना जा सकता। हालांकि, मौखिक तर्कों और अपने लिखित प्रस्तुतियों के दौरान, अटॉर्नी जनरल ने इस तर्क को आधार बनाया कि राज्यसभा के लिए मतदान अनुच्छेद 194 (2) द्वारा इस आधार पर संरक्षित नहीं है कि इस तरह के चुनाव चुनाव की भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना सदन की विधायी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होते हैं। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए महान्यायवादी ने सन् 1957 में इस न्यायालय के तीन निर्णयों पर भरोसा किया। पशुपति नाथ सुकुल बनाम नेमचंद्र जैन और ओआरएस[82] मधुकर जेटली बनाम भारत संघ,[83] और कुलदीप नैयर बनाम भारत संघा[84]

169. इस तरह का तर्क, हालांकि पहली बार में आकर्षक है, गलत प्रतीत होता है। संक्षेप में, सवाल यह है कि क्या राज्यसभा के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा डाले गए वोट संविधान के अनुच्छेद 194 (2) द्वारा संरक्षित हैं। विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों को संबोधित करने से पहले, हम संविधान के उन प्रावधानों का विश्लेषण करेंगे जो संवैधानिक व्याख्या के इस दिलचस्प प्रश्न को नियंत्रित करते हैं।

अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद या राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को नियंत्रित करता है। प्रावधान इस प्रकार है:

“80. राज्य सभा की संरचना। –

(1) राज्य सभा निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

(i). बारह सदस्य जो खंड (3) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएँगे; और

(ii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दो सौ अड़तीस से अधिक प्रतिनिधि।

(2) राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आबंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।...

(4) राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि होंगे राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार। (महत्त्व दिया गया)

171. अनुच्छेद 80 के अनुसरण में, राज्य सभा में बारह सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दो सौ अड़तीस से अधिक प्रतिनिधि नहीं होते हैं। गौरतलब है कि अनुच्छेद 80 (4) के तहत राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अतः राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए 'मतदान' करने की शक्ति केवल राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को सौंपी गई है। यह प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के रूप में उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों का एक अभिन्न अंग है।

172. इसलिए, अगला सवाल यह उठता है कि क्या अनुच्छेद 194 (2) संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित होने वाले ऐसे वोट पर कोई प्रतिबंध लगाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 194 (2) इस प्रकार है:

“194. विधान-मंडलों के सदनों की और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। –

(2) किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई सदस्य उसके द्वारा विधान-मंडल या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कोई व्यक्ति ऐसे विधान-मंडल के सदन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किसी प्रतिवेदन के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार दायी नहीं होगा, कागज, वोट या कार्यवाही से सम्बंधित

…”

173. अनुच्छेद 194 के लिए सीमांत नोट वाक्यांश का उपयोग करता है "शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि। घरों विधानमंडलों और उनके सदस्यों और समितियों की। यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सीमांत एक क़ानून में एक अनुभाग के लिए नोट अनुभाग के मुख्य भाग के अर्थ को नियंत्रित नहीं करता है यदि नियोजित भाषा स्पष्ट है। संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में, एक सीमांत नोट का उपयोग "अनुच्छेद के अर्थ और उद्देश्य के रूप में कुछ सुराग" प्रदान करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। हालाँकि, अनुच्छेद का वास्तविक अर्थ अनुच्छेद के नंगे पाठ से लिया जाना है। जब अनुच्छेद की भाषा

सादा और अस्पष्ट होती है, तो इसके साथ संलग्न सीमांत नोट पर अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता है।[85] केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरला[86], हेगड़े, न्यायमूर्ति (खुद के लिए बोलते हुए और ए के मुखर्जी, न्यायमूर्ति) ने इस प्रकार अवलोकन किया:

“620. [...] स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए, अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल हैं। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में निहित सीमांत टिप्पणी को कोई अनुचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। सीमांत नोट एक वैधानिक प्रावधान के निर्माण में बहुत कम भूमिका निभाता है। संवैधानिक उपबंध बनाने में इसका महत्व बहुत कम होना चाहिए। हमारे विचार से अनुच्छेद 368 की भाषा सरल और स्पष्ट है। इसलिए हमें निर्माण के किसी भी नियम को सहायता में बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बारे में सुनवाई में बहुत बहस हुई थी। चूंकि अनुच्छेद के तहत संशोधन करने की शक्ति, जैसा कि मूल रूप से खड़ा था, केवल निहित था, सीमांत नोट ने संशोधन की प्रक्रिया को सही ढंग से संदर्भित किया। सीमांत टिप्पणी में प्रक्रिया का संदर्भ अनुच्छेद में निहित शक्ति के अस्तित्व को नकारात्मक नहीं करता है। (महत्त्व दिया गया)

174. सीमांत नोट से अलग, प्रावधान के पाठ में, शब्द का एक सचेत उपयोग है " विधान-मंडल " के बजाय " सदन उपयुक्त स्थानों पर विधायिका का। प्रावधान के प्रारूपण से यह स्पष्ट है कि दो शब्दों का परस्पर उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 194(2) का पहला अंग "में कही गई कोई बात या उनके द्वारा दिए गए किसी भी वोट से संबंधित है। विधान-मंडल या उसकी कोई समिति"। फिर भी, दूसरे अंग में, प्रयुक्त वाक्यांश है "के अधिकार द्वारा या उसके तहत प्रकाशन के संबंध में ऐसे विधानमंडल का सदन किसी भी रिपोर्ट, कागज, वोट या कार्यवाही का।“ विधानमंडल शब्द से स्पष्ट विचलन है जिसका प्रयोग प्रथम अंग में हाउस ऑफ ऐसा उपबंध के दूसरे अंग में एक विधायिका। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रावधान एक पूरे के रूप में "विधायिका" (पहले अंग में) और एक ही विधायिका के "सदन" (दूसरे अंग में) के बीच अंतर पैदा करता है।

175. जैसा कि अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन द्वारा सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है, "विधानमंडल का सदन" और "विधानमंडल" शब्दों के अलग-अलग अर्थ हैं। "विधानमंडल का सदन" न्यायिक निकाय को संदर्भित करता है, जिसे अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है।[87] दूसरी ओर, "विधानमंडल" शब्द, अनुच्छेद 168 के तहत व्यापक अवधारणा को संदर्भित करता है,[88] जिसमें राज्यपाल और विधानमंडल के

सदन शामिल हैं। यह अनिश्चित काल तक कार्य करता है और तब भी अस्तित्व में रहता है जब राज्यपाल ने सदन नहीं बुलाया होता है।

176. "विधानमंडल के सदन" के बजाय "विधानमंडल में" वाक्यांश का उपयोग महत्वपूर्ण है। कई संसदीय प्रक्रियाएं हैं जो सदन के पटल पर नहीं होती हैं, यानी जब यह सत्र में होता है, राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है। उदाहरण के लिए, वहाँ हैं तदर्थ समितियां और स्थायी समितियां जो नीति या सरकारी प्रशासन के मामलों सहित विभिन्न मुद्दों की जांच करती हैं। इनमें से कई समितियां सदन में पेश किए गए कानूनों या बिलों पर विचार-विमर्श नहीं करती हैं या जब 'सदन' नहीं बैठती हैं तो कार्य करना बंद कर देती हैं। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि ऐसी समितियों में होने वाले विचार-विमर्श ("कुछ भी कहा गया") को संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा।

177. अनुच्छेद 80 के तहत आयोजित राज्यसभा के चुनाव, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तब भी हो सकते हैं जब सदन सत्र में नहीं होता है क्योंकि राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं होने पर सीटें खाली हो सकती हैं। हालांकि, चुनाव विधानमंडल के कामकाज का एक हिस्सा बने रहते हैं और विधान सभा के परिसर के भीतर होते हैं। इसी प्रकार, अनुच्छेद 54[89] और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के लिए[90] यह तब भी हो सकता है जब संसद या राज्य विधान सभाएं सत्र में न हों। हालांकि, वे संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का एक अभिन्न अंग हैं। ऐसे चुनावों के लिए वोट विधानमंडल या संसद में दिया जाता है, जो अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के पहले अंग के संरक्षण को लागू करने के लिए पर्याप्त है। ऐसी प्रक्रियाएं विधायिका के कामकाज और संसदीय लोकतंत्र की व्यापक संरचना के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 105 (2) और अनुच्छेद 194 (2) के पाठ में कोई प्रतिबंध नहीं है, जो ऐसे चुनावों को प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण से बाहर धकेलता है। इसके अलावा, विधायकों को बिना किसी डर के "बोलने" और "वोट" देने के लिए मंच प्रदान करने के संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य राज्यसभा के चुनावों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर भी समान रूप से लागू होता है।

178. अब हम उन मामलों को संबोधित करेंगे जिन पर अटॉर्नी जनरल ने अपने तर्क को आगे बढ़ाने के लिए भरोसा किया था। में पशुपति नाथ सुकुल (उपरोक्त) , इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि विधान सभा का एक सदस्य संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत आवश्यक संवैधानिक शपथ लेने से पहले ही राज्यसभा में सीट के लिए

उम्मीदवारी का प्रस्ताव कर सकता है और राज्यसभा के चुनाव में मतदान कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि राज्यसभा में सीटों को भरने के लिए चुनाव सदन की विधायी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होता है और न ही वे सदन में दिए गए वोट का गठन करते हैं। सदन इसके समक्ष उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर। इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 193 से प्रभावित नहीं है, जिसमें कहा गया है कि विधान सभा का कोई सदस्य विधानसभा में बैठकर मतदान नहीं कर सकता है। सदन के शपथ की सदस्यता लेने से पहले। दिलचस्प बात यह है कि न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिसूचना में निर्वाचित सदस्य के नाम और संवैधानिक शपथ लेने वाले सदस्य के बीच की अवधि में, वह सभी विशेषाधिकारों, वेतन और भत्तों की हकदार है विधान सभा के सदस्य का। यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने माना कि विधान सभा के सदस्य विशेषाधिकारों के हकदार हैं, भले ही वे 'कानून बनाने' में भाग नहीं ले सकते हैं या भाग नहीं ले रहे हैं। इन विशेषाधिकारों में से एक अनुच्छेद 194 के तहत विधान सभा के सदस्यों को दिया गया संसदीय विशेषाधिकार है। न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“ 18. […] संविधान के अनुच्छेद 193 में निहित नियम, जैसा कि पहले कहा गया है, यह है कि विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान से पहले सदन में बैठकर मतदान नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 193 में "बैठक और मतदान" शब्द का अर्थ है कि राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक करने के लिए बुलाया जाना जो वह ठीक समझे और उक्त समन या स्थगित बैठक के अनुसरण में सदन की बैठक आयोजित करना। एक निर्वाचित सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 193 के उल्लंघन के लिए तभी जुर्माना लगाया जाता है जब वह सदन की ऐसी बैठक में बैठता है और मतदान करता है। अधिनियम की धारा 73 द्वारा यथा उपबंधित आम चुनाव के बाद सदन के गठन और सदन की पहली बैठक बुलाने के बीच निरपवाद रूप से समय का अंतराल होता है। उस अंतराल के दौरान विधानसभा का एक निर्वाचित सदस्य जिसका नाम अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी अधिसूचना में दिखाई देता है, विधान सभा के सदस्य के सभी विशेषाधिकारों, वेतन और भत्तों का हकदार होता है, उनमें से एक राज्य सभा में सीट भरने के लिए आयोजित चुनाव में निर्वाचक के रूप में कार्य करने का अधिकार होता है। यह अधिनियम की धारा 73 का प्रभाव है जिसमें कहा गया है कि इसके अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर सभा का गठन किया गया माना जाएगा। विचाराधीन चुनाव सदन की विधायी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होता है, जो इसकी बैठक में किया जाता है। न ही इस तरह के चुनाव में डाला गया वोट सदन के समक्ष उठने

वाले किसी भी मुद्दे पर सदन में दिया गया वोट है। अध्यक्ष का चुनाव पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। चुनाव इस उद्देश्य के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 33 के तहत नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को अधिनियम की धारा 30 के तहत नामांकन करने के लिए अधिसूचित अंतिम दिन से पहले पूर्वाह्न ग्यारह बजे और दोपहर तीन बजे के बीच रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। फिर नामांकन की जांच और नामांकन वापस लेने जैसे सभी कदम रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष होते हैं। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 69 उपबंध करता है कि विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में जहां मतदान आवश्यक हो जाता है, ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी, अभ्यनिर्वाचन वापसी की अंतिम तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक निर्वाचक को मतदान के लिए नियत तारीख, समय और स्थान के बारे में सूचित करते हुए एक सूचना भेजेगा। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का भाग VI, जिसमें नियम 69 और उसका भाग VII शामिल है, विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 85 यह उपबंध करता है कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचित होने की घोषणा किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को प्ररूप 24 में निर्वाचन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और अभ्यर्थी से उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसकी रसीद की पावती प्राप्त करेगा और पावती को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा राज्य सभा के सचिव या जैसा भी मामला हो, भेजेगा विधान परिषद के सचिव बनें। इस प्रकार चुनाव के दौरान उठाए गए सभी कदम सदन की बैठक में होने वाली कार्यवाही से बाहर हो जाते हैं। (महत्त्व दिया गया)

179. मधुकर जेटली (उपरोक्त), का मामला जिस पर न्यायालय ने भरोसा किया पशुपति नाथ सुकुल (उपरोक्त) में शामिल किया गया है और दोहराया है कि राज्य सभा के लिए निर्वाचन सभा की विधायी कार्यवाही का हिस्सा नहीं होता है और ऐसे निर्वाचन में डाला गया मत सभा की बैठक में दिया गया मत नहीं माना जाता है। प्रासंगिक रूप से, दोनों पशुपति नाथ सुकुल (उपरोक्त) और मधुकर जेटली (उपरोक्त) अनुच्छेद 194(2) की व्याख्या और दायरे से संबंधित किसी प्रश्न या संसदीय विशेषाधिकार के किसी दावे से संबंधित नहीं था।

180. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि राज्य सभा के चुनाव कानून बनाने के कार्यों का हिस्सा नहीं हैं और सदन की बैठक के दौरान नहीं होते हैं। हालांकि, अनुच्छेद 194 का पाठ संसदीय प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए जानबूझकर 'सदन' के बजाय 'विधानमंडल' शब्द का उपयोग करता है, जो जरूरी नहीं है सभा के पटल पर घटित होता है या अपने पांडित्यपूर्ण अर्थ में 'कानून बनाने' को शामिल करता है।

181. अंत में, विद्वान महान्यायवादी ने कुलदीप नायर (उपरोक्त) मामले का अवलंबन लिया इस न्यायालय की एक संविधान पीठ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक संशोधन की वैधता पर निर्णय दे रही थी, जिसके द्वारा राज्य में किसी निर्वाचन क्षेत्र से राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार के निर्वाचक होने की आवश्यकता को हटा दिया गया था; और राज्यसभा के चुनावों में एक खुला मतपत्र पेश किया गया था।

182. राज्यसभा के चुनावों में खुले मतपत्रों के उपयोग को रोकने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियों में से एक यह था कि वोट अनुच्छेद 194 (2) द्वारा संरक्षित हैं। यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 194 (1) और (2) के तहत विधायकों को गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार से अलग है, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है। यह आग्रह किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 194 (2) के तहत मतदान करने की पूर्ण स्वतंत्रता को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक वैधानिक संशोधन के माध्यम से खुले मतपत्रों की अनुमति दी जा रही है। इस तर्क को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि राज्यसभा में सीटों को भरने के लिए चुनाव विधायिका की कार्यवाही नहीं है, बल्कि केवल मताधिकार का अभ्यास है, जो अनुच्छेद 194 के दायरे से बाहर है। कोर्ट (वाईके सभरवाल, मुख्या न्यायमूर्ति के माध्यम से बोलते हुए) ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“विधायी विशेषाधिकारों और दसवीं अनुसूची पर आधारित तर्क

372. विद्वान वकील का यह तर्क है कि अनुच्छेद 80(4) के प्रावधानों के तहत राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए राज्यवार निर्वाचक मंडल गठित करने वाले राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 194(2) में निहित प्रावधान के दायरे और अवधि के बारे में भी यही व्याख्या होनी चाहिए। वकील का तर्क है कि अनुच्छेद 194 (2) से प्रवाहित होने वाले कानूनी परिणामों के डर के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 80 (4) के तहत निर्वाचक मंडल के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करते समय विधान सभाओं के सदस्यों को मिलनी चाहिए।

373. यह तर्क, हालांकि आकर्षक है, हाथ में संदर्भ में किसी भी विश्वास के लायक नहीं है। अनुच्छेद 80 के तहत चुनाव से संबंधित कार्यवाही अनुच्छेद 194 के अर्थ के भीतर "राज्य के विधानमंडल के सदन" की कार्यवाही नहीं है। विधान सभा के निर्वाचित सदस्य ही हैं जो अनुच्छेद 80 के अधीन राज्य सभा में उस राज्य को आबंटित स्थान को भरने के लिए राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। यह

उल्लेखनीय है कि यह पूरी विधान सभा नहीं है जो निर्वाचक मंडल बन जाती है, बल्कि केवल उसके सदस्यों की निर्दिष्ट श्रेणी होती है। जब ऐसे सदस्य एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, तो वे ऐसा करते हैं कि वे संविधान के तहत विधान सभा को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन न करें। चुनाव में उनकी भागीदारी केवल चुनाव के लिए मतदाताओं की उनकी पदेन क्षमता के कारण होती है। इस प्रकार, उनमें से प्रत्येक द्वारा वोट डालने का कार्य, जो उन सभी के एक साथ या एक ही समय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल मताधिकार का प्रयोग है और विधायिका की कार्यवाही नहीं है। ” (महत्त्व दिया गया)

183. अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत संरक्षण गारंटी देता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य का मतदान, जैसा भी मामला हो, अदालत में कार्यवाही का विषय नहीं हो सकता है। यह "गुप्त मतदान" की गारंटी नहीं देता है। वास्तव में, यहां तक कि जब संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य सदन की बैठक के दौरान विधेयकों पर मतदान करते हैं, जो निर्विवाद रूप से अनुच्छेद 105 और 194 के दायरे में आता है, तो उन्हें गुप्त मतदान का आश्वासन नहीं दिया जाता है। जबकि मतदान आमतौर पर ध्वनि मत द्वारा किया जाता है, विधायिका के सदस्य "डिवीजन वोट" के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। ऐसे में मतों का मतविभाजन, अर्थात किस सदस्य ने प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतदान किया, यह पूरे सदन और आम जनता को दिखाई देता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 194 (2) के तहत संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य विधायिका को संसद में उनके वोटों या भाषणों में गुमनामी प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें उनके द्वारा डाले गए वोटों या उनके द्वारा दिए गए भाषणों से संबंधित कानूनी कार्यवाही से बचाना है। यह बात कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतों और भाषणों की सामग्री नागरिकों की पहुंच में हो, संसदीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है।

184. अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने तर्क दिया है कि कुलदीप नैयर (उपरोक्त) का गठन नहीं करते हैं अनुपात निर्णय निर्णय के और हैं ओबिटर . यह ट्राइट लॉ है कि यह न्यायालय केवल पिछले निर्णय के अनुपात से बंधा है। इस तर्क में कुछ दम हो सकता है। हालांकि, किसी भी घटना में, इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों का संयोजन होने के नाते, यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए मतदान अनुच्छेद 194 (2) के दायरे में आता है। अन्य सभी बातों पर, संविधान पीठ का कुलदीप नैयर (उपरोक्त) पर दिया गया निर्णय एक अच्छा है।

185. दिलचस्प है की, कुलदीप नैयर (उपरोक्त) का मामला जिसमें न्यायालय ने 1995 में अल्पमत के फैसले पर भरोसा किया था। पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) इस प्रस्ताव को मजबूत करने के लिए कि संविधान की व्याख्या करते समय, न्यायालय को एक ऐसे निर्माण को अपनाना चाहिए जो संविधान की मूलभूत विशेषताओं और मूल संरचना को मजबूत करता है। कानून के इस प्रस्ताव को इस सवाल पर लागू करना कि क्या राज्यसभा के लिए मतदान अनुच्छेद 194 (2) के दायरे में आता है, हमें भी इसी तरह के निष्कर्ष पर लाता है।

हम में से एक (डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति) में के.एस. पुट्टास्वामी (आधार - 5 न्यायमूर्तियों) बनाम भारत संघ,[91] राज्य सभा के महत्व और "हमारे लोकतंत्र की नींव" पर द्विसदनवाद पर विचार करने का अवसर मिला था। यह देखा गया कि:

“ 1106. राज्यसभा की संस्थागत संरचना को राष्ट्र के बहुलवाद और भाषा, संस्कृति, धारणा और रुचि की विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित किया गया है। विधायी प्रस्तावों की व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा की परिकल्पना की गई थी। संसद के दूसरे कक्ष के रूप में, यह जल्दबाजी और बिना सोचे-समझे बनाए गए कानून पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, जिससे विधायी कार्य की जांच का अवसर मिलता है। राज्य सभा की भूमिका कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने और शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए आंतरिक है। उच्च सदन कई मायनों में निचले सदन के कामकाज का पूरक है। राज्य सभा लोकसभा के संबंध में संतुलन की संस्था के रूप में कार्य करती है और भारत के संघीय ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य सभा का अस्तित्व और भूमिका दोनों ही संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। हमारे संविधान की संरचना में राज्य सभा की परिकल्पना संघीय द्विसदनवाद की संस्था के रूप में की गई है न कि केवल एक साधारण द्विसदनी विधायिका के हिस्से के रूप में। "सीनेट" के बजाय "राज्यों की परिषद" के रूप में इसका नामकरण उचित रूप से इसके संघीय महत्व को सही ठहराता है।

1108. […] एक पुनरीक्षण कक्ष के रूप में, संविधान-निर्माताओं ने कल्पना की कि यह संविधान के मूल्यों की रक्षा करेगा, भले ही यह लोकप्रिय इच्छा के विरुद्ध हो। राज्यसभा बहुसंख्यकवाद के खिलाफ एक प्रतीक है।

1110. सहभागी शासन लोकतंत्र का सार है। यह जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। राज्यसभा द्वारा संशोधित विधेयकों के विश्लेषण से पता चलता है कि कई मामलों में, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों में राज्यसभा द्वारा अनुशंसित परिवर्तन अंततः किए गए थे। दहेज निषेध विधेयक एक ऐसे विधान का उदाहरण है जिसमें संशोधनों पर राज्य सभा के

जोर देने के कारण दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में, राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों में से एक को बिना मत विभाजन के स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्र निर्माण में राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के बीच संवाद अलग-अलग दृष्टिकोणों से विवादों को हल करने में मदद करता है। भारतीय संसद की द्विसदनीय प्रकृति संघीय संविधान के कामकाज का अभिन्न अंग है। यह हमारे लोकतंत्र की नींव रखता है। यह संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, इसलिए संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय प्रक्रिया का विषय नहीं है। इसका सीधा प्रभाव राज्यसभा की भूमिका पर पड़ता है और इसलिए संघीय राजनीति के कामकाज पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

(महत्त्व दिया गया)

187. राज्य सभा या राज्य सभा हमारे लोकतंत्र के कार्यकरण और राज्य द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका में अभिन्न कार्य करती है सभा संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। इसलिए, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करने में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता है कि वोट स्वतंत्र रूप से और कानूनी उत्पीड़न के डर के बिना किया जाए। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते समय विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मताधिकार का स्वतंत्र और निडर प्रयोग निस्संदेह राज्य विधानसभा की गरिमा और कुशल कामकाज के लिए आवश्यक है। कोई अन्य व्याख्या अनुच्छेद 194(2) के पाठ और संसदीय विशेषाधिकार के उद्देश्य को झुठलाती है। दरअसल, अनुच्छेद 105 और 194 के तहत संरक्षण को बोलचाल की भाषा में "संसदीय विशेषाधिकार" कहा गया है, न कि किसी कारण से "विधायी विशेषाधिकार"। इसे केवल सदन के पटल पर कानून बनाने तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि निर्वाचित सदस्यों की अन्य शक्तियों और जिम्मेदारियों तक विस्तारित किया जाता है, जो विधानमंडल या संसद में होती हैं, तब भी जब सदन नहीं बैठा हो।

(ञ) समाप्ति

188. इस निर्णय के दौरान, 1999 में बहुसंख्यक और अल्पमत के तर्कों का विश्लेषण करते हुए। पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) हमने विवाद के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है, अर्थात्, क्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के आधार पर, संसद या विधान सभा, जैसा भी मामला हो, एक आपराधिक अदालत में रिश्वत के आरोप में अभियोजन से

प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है। हम इस पहलू पर बहुमत के फैसले से असहमत हैं और उसे खारिज करते हैं। हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

188.1. सिद्धांत - स्टेयर डेसीसिस कानून का एक अनम्य शासन नहीं है। इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ उपयुक्त मामलों में पिछले निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है, जो इस न्यायालय के उदाहरणों में तैयार किए गए परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए है। पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) में बहुमत का फैसला, जो विधायिका के एक सदस्य को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो कथित रूप से वोट डालने या बोलने के लिए रिश्वत में लिप्त है, जिसका सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस न्यायालय द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किए जाने पर त्रुटि को बनाए रखने की अनुमति देने का एक गंभीर खतरा है;

188.2. ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह भारत में निहित विशेषाधिकार 'प्राचीन और निस्संदेह' नहीं हैं। संसद और राजा के बीच संघर्ष के बाद। स्वतंत्रता-पूर्व भारत में विशेषाधिकार एक अनिच्छुक औपनिवेशिक सरकार के सामने क़ानून द्वारा शासित थे। संविधान के प्रारंभ के बाद वैधानिक विशेषाधिकार एक संवैधानिक विशेषाधिकार में परिवर्तित हो गया;

188.3. क्या किसी विशेष मामले में विशेषाधिकार का दावा संविधान के मापदंडों के अनुरूप है, न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है;

188.4. विधायिका का कोई व्यक्तिगत सदस्य विधायिका में वोट या भाषण के संबंध में रिश्वत के आरोप में अभियोजन से अनुच्छेद 105 और 194 के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। प्रतिरक्षा का ऐसा दावा दोहरे परीक्षण को पूरा करने में विफल रहता है कि दावा सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा हुआ है और यह एक विधायक के आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है;

188.5. संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिसमें विधायिका के भीतर बहस और विचार-विमर्श हो सकता है। यह उद्देश्य तब नष्ट हो जाता है जब किसी सदस्य को रिश्वत के कार्य के कारण एक निश्चित तरीके से वोट देने या बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है;

188.6. अभिव्यक्ति "कुछ भी" और "कोई भी" अनुच्छेद 105(2) और 194(2) में साथ दी गई अभिव्यक्तियों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए. शब्द "के संबंध में" का अर्थ है 'से उत्पन्न

होना' या 'स्पष्ट संबंध रखना' और इसका अर्थ किसी भी ऐसी चीज से नहीं लगाया जा सकता है जिसका दिए गए भाषण या वोट के साथ दूरस्थ संबंध भी हो सकता है;

188.7. रिश्वतखोरी अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194 के तदनुरूपी प्रावधान के तहत प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि रिश्वत में संलग्न एक सदस्य एक अपराध करता है जो वोट डालने के लिए आवश्यक नहीं है या यह तय करने की क्षमता नहीं है कि वोट कैसे डाला जाना चाहिए। सदन या समिति में भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी पर भी यही सिद्धांत लागू होता है;

188.8. विधायिका के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में शुचिता को नष्ट करती है;

188.9. अधिकार क्षेत्र जो एक सक्षम न्यायालय द्वारा एक आपराधिक अपराध और सदन के अधिकार पर मुकदमा चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विधायिका के एक सदस्य द्वारा रिश्वत की स्वीकृति के संबंध में अनुशासन के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद हैं। एक आपराधिक अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का दायरा, उद्देश्य और परिणाम और उसके सदस्यों को अनुशासित करने के लिए सदन का अधिकार अलग-अलग हैं;

188.10. विधायिका के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ दुरुपयोग की संभावना न तो बढ़ाई जाती है और न ही विधायिका के एक सदस्य पर मुकदमा चलाने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र को पहचानने से कम होती है, जिस पर रिश्वत के कार्य में लिप्त होने का आरोप है;

188.11. रिश्वत का अपराध सहमत कार्रवाई के प्रदर्शन के लिए अज्ञेयवादी है और अवैध परितोषण के आदान-प्रदान पर क्रिस्टलीकृत होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोट सहमत दिशा में डाला गया है या यदि वोट डाला गया है। रिश्वतखोरी का अपराध उस समय पूरा होता है जब विधायक रिश्वत स्वीकार करता है; और

188.12. पीवी नरसिम्हा राव (उपरोक्त) के मामले में जो मुद्दे थे बहुमत द्वारा दिए गए निर्णय की सवालों की व्याख्या पर वो एक विरोधाभासी परिणाम देता है जहां एक विधायक को प्रतिरक्षा से सम्मानित किया जाता है जब वे रिश्वत स्वीकार करते हैं और सहमत दिशा में मतदान करके पालन करते हैं। दूसरी ओर, एक विधायक जो रिश्वत स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, लेकिन अंततः स्वतंत्र रूप से मतदान करने का फैसला करता है, उस

पर मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसी व्याख्या अनुच्छेद 105 और 194 के पाठ और उद्देश्य के विपरीत है।

189. संदर्भ का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया गया है। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न का उत्तर देने के बाद, आपराधिक अपील उपरोक्त शर्तों में निपटाई जाती है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान कर दिया गया है।

संदर्भ का उत्तर दिया गया और आपराधिक अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।